चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

www.chauthiduniya.com

कहीं यह चिंगारी शाहरुख़ को न जला दे

पेज 3

चार सप्ताह पहले चौथी दुनिया ने किया ख़ुलासा

पेज 4

आईपीएल की काली दुनिया

पेज 5

भक्ति की शक्ति

पेज 12

मूल्य 5 रुपये

दिल्ली, 03 मई–09 मई 2010

संसद, सुप्रीम कोर्ट, 10 जनपथ और इंडियन फिक्सिंग लीग

सवाल ललित मोदी का है नहीं, मोदी एक कड़ी भर हैं. इस कड़ी से जुड़ी बहुत सी कड़िया हैं, जिनमें शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल सहित पांच से ज़्यादा मंत्री, इनके परिवार के लोग, सांसद, खेल को लूट का ज़रिया बनाने वाले खेलों के कर्ताधर्ता और इनका गुणगान करने वाले मीडिया के लोग और ग्लैमर की दुनिया के वे सितारे हैं, जो इस वीभत्स खेल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. इस समय मोदी का बलिदान करने की योजना पर बीसीसीआई अमल कर रहा है. सवाल मोदी के रुकने या जाने का नहीं है. इस घोटाले में बीसीसीआई से जुड़े सारे अधिकारी शामिल हैं. इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच आवश्यक है.

संतोष भारतीय

भारत की राजनीति को साफ़ करने का समय आ गया है. सारे देश को मूर्ख बना कर पैसा बनाने का घिनौना खेल अपने अंतर्विरोध की वजह से खुल गया है. दरअसल यह हिंदुस्तान का वाटर गेट है, जिसकी शुरुआत एक टिप्पणी से हुई और आज इसमें भारत सरकार के कई मंत्री, क्रिकेट से जुड़े बड़े लोग और अपराध की दुनिया के बादशाह एक साथ, हाथ मिलाए खड़े दिखाई दे रहे हैं. इसमें पर्दे के पीछे खेलने वाले फ़िल्मी दुनिया के लोग भी अब सामने आ गए हैं.

सबसे बड़ा खेल तो इन शातिरों ने दस जनपथ से जुड़े लोगों को अपने साथ सार्वजनिक रूप से दिखाकर खेला है. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वडेरा को जिन्होंने आईपीएल से जोड़ा, उन्होंने जानबूझ कर जोड़ा. आईपीएल के सारे खिलाड़ी सब कुछ जानबूझ कर रहे थे. उन्हें मालूम था कि यदि वे फंसे तो देश का सबसे ताक़तवर परिवार जो सत्ता चला रहा है, उन्हें बचाने आएगा. आज इस परिवार की साख दांव पर है, सवाल है कि क्या आईपीएल के खेल में इस परिवार का भी पैसा लगा है? जिन लोगों ने इस परिवार को आईपीएल के जाल में उलझाया है, उन्होंने देश के व्यापार जगत को यही बताया है कि यह परिवार उन्हें सब कुछ करने की इजाज़त दे चुका है. आख़िर सच है क्या? सौ करोड़ से ज़्यादा की ताक़त वाले देश की क़िस्मत एक माफिया डॉन के हाथों में कैद है. इस डॉन के पास आईपीएल के सौदों की, मंत्रियों के बीच होने वाली बातचीत के टेप हैं. इन्कम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट को कुछ टेप इस डॉन ने भिजवाए हैं. अपनी ताक़त दिखाने के लिए डॉन सारी बातचीत आम कर सकता है और उस स्थिति में भारत सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है.

भारत की संसद और भारत की न्यायपालिका की साख भी सवालिया दायरे में आ गई है. इस महान घोटाले की जांच, जिसने देश के आम आदमी को अपने जाल में फंसा लिया, सीबीआई नहीं कर सकती, क्योंकि जिसमें देश चलाने वाले फंसे हों, उनके सामने सीबीआई असहाय है. इसकी जांच सिर्फ़ संसद की संयुक्त जांच कमेटी कर सकती है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश. इस सवाल पर सर्वोच्च न्यायालय को भी स्वत: संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यह सारा मामला देश के लोकतंत्र पर विश्वास से जुड़ा है.

केंद्रीय मंत्री, बड़े सांसद, बड़े अधिकारी, बड़े उद्योगपति, बड़े खिलाड़ी, बड़े सिनेमा स्टार जब मिल कर देश को लूटने की योजना बनाएं और सफलतापूर्वक लागू करें, तब सुप्रीम कोर्ट ही एक आशा बचती है. बुंदेलखंड में पानी नहीं है, उड़ीसा में भूख से मौतें हो रही हैं, छत्तीसगढ़ में भूखे लोग हाथ में हथियार उठा रहे हैं, देश में महंगाई ने आम आदमी को रुला दिया है. ऐसी स्थिति में सरकार के ताक़तवर लोग आईपीएल के ज़रिए अरबों रुपया विदेश भेज रहे हैं.

दस जनपथ की साख ख़तरे में है, देखना है वे किन्हें बचाते हैं. वे जनता के साथ खड़े होते हैं या उनके साथ, जिन्होंने उन्हें सार्वजनिक रूप से आर्थिक अपराधियों के साथ खड़ा कर दिया है. संसद की ताक़त, संसद की समझ भी यह बताएगी कि वह देश के सवाल पर कुछ कर पाती है या नहीं. या एक नपुंसक संस्था की तरह केवल बातों की ताली पीट कर चुप हो जाएगी.

अगर आज सुप्रीम कोर्ट और संसद नहीं चेते तो कल लोकतंत्र न चाहने वाले खड़े हो

editor@chauthiduniya.com

कहीं यह चिंगारी शाहरुख़ को न जला दे

आईपीएल की आग इतना भयंकर रुप ले लेगी, यह किसी को पता नहीं था. सिर्फ़ एक सवाल के सही जवाब से यह घोटाला आज़ाद भारत में सबसे बड़े राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बन सकता है. यक्ष प्रश्न यह है कि शाहरुख़ ख़ान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में किसका कितना पैसा लगा है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है. चौथी दुनिया के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक़ शाहरुख़ ख़ान की टीम में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं और एक पूर्व दागदार मुख्यमंत्री का पैसा लगा है. हमारे सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के एक बड़े मंत्री ने शाहरुख़ ख़ान की एक कांग्रेसी नेता से मुलाक़ात करवाई, जो दस जनपथ का क़रीबी माना जाता है, साथ ही बीसीसीआई का अधिकारी भी है. यही मुलाक़ात शाहरुख़ को गांधी परिवार के काफी क़रीब ले गई. आईपीएल की टीम ख़रीदने के दौरान शाहरुख़ ख़ान को पैसे की ज़रूरत पड़ी. इसी केंद्रीय मंत्री ने शाहरुख़ ख़ान की फिर मदद की. उन्होंने ख़ान को एक और शख्स से मिलवाया जिसका नाम है मधु कोड़ा. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोपी हैं. हमारे सूत्रों के मुताबिक़ शाहरुख़ की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स में मधु कोड़ा ने भी पैसे लगाए थे. इसके अलावा, शाहरुख़ की टीम में महाराष्ट्र के एक बड़े कांग्रेसी नेता की हिस्सेदारी की भी चर्चा हो रही है. अब सवाल यह है कि इस केंद्रीय मंत्री और शाहरुख़ ख़ान के बीच क्या रिश्ता है? मंत्री की पत्नी एक पूर्व अभिनेत्री हैं और वह शाहरुख़ की पत्नी गौरी ख़ान के साथ एक इंटरटेंनमेंट और एडवर्टाइज़मेंट कंपनी में पार्टनर हैं. सवाल यह भी है कि आईपीएल की यह आग कहां रुकेगी. अंडरवर्ल्ड, ब्लैकमनी, पॉलिटिक्स और क्रिकेट के इस घालमेल का किस्सा कहां ख़त्म होगा. शाहरुख़ ख़ान की टीम में और किन किन लोगों का पैसा लगा है और इन पैसों का स्त्रोत क्या है? शाहरुख़ की टीम और अंडरवर्ल्ड के बीच का रिश्ता क्या है, यह पूरा खुलासा पढ़िए पेज नंबर 3 पर

खेल ख़त्म नहीं हुआ

हिंदुस्तान के अब तक के सबसे बड़े घोटाले का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है. अभी तो अंडरवर्ल्ड के किस्से का खुलासा होना बाक़ी है. ललित मोदी बीसीसीआई के पापों का घड़ा फोड़ने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि आज हर कोई उनके ख़िलाफ़ है. आपने मारियो पूजो की किताब पर बनी फ़िल्म गॉडफादर देखी हो तो यह समझ लीजिए आज हालात उससे ज़्यादा अलग नहीं हैं. यदि किसी क्षण किसी बड़ी हस्ती पर गोलियां चलने लगे या फिर कत्ल हो जाए तो मत चौंकिएगा. सुना है कि प्यार और लड़ाई में सब कुछ जायज़ है लेकिन यहां तो सारा खेल ही नाजायज़ पैसों का है. वो भी करोड़ों का. अभी कई और चेहरे सामने आएंगे, जिनमें फ़िल्म स्टार्स से लेकर क्रिकेट खिलाड़ी, राजनेता और नौकरशाह तक शामिल हो सकते हैं. यह जंगल की आग की तरह है. इस खेल में कहां, कौन, कैसे और कब जलेगा, यह किसी को पता नहीं है.

(पूरी ख़बर पेज 2 पर)

अंडरवर्ल्ड और क्रिकेट अधिकारियों की कृपा से यह अब ऐसा तमाशा बन चुका है, जिसमें खिलाड़ी से ज़्यादा बड़ी भूमिका सट्टेबाज़ों और सुंदर-कमसिन बालाओं की होती है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

ऊर्जा क्षेत्र में मचा घमासान

देश के ऊर्जा क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों की कोई कमी नहीं है. लेकिन सरकार को इस क्षेत्र में देश की शीर्ष नीति नियामक संस्था सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (सीईए) में चल रहे घालमेल का जवाब तलाशना ही होगा. सूत्रों के मुताबिक़ सीईए के सदस्य गुरदयाल सिंह को संस्था का कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने के बाद कई लोग विद्रोह पर उतारू हो गए हैं. सिंह को राकेश नाथ की जगह नियुक्त किया गया है, जो सेवानिवृत्ति के बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के सदस्य बनाये गए हैं. लेकिन गुरदयाल सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष बनाये जाने के खिलाफ सीईए के चार सदस्यों में से एक वी रामकृष्ण छुट्टी पर चले गए हैं. हालांकि, ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक़ सीईए के अध्यक्ष पद के लिए रामकृष्ण के दावे में कोई ख़ास दम नहीं है, क्योंकि अगले कुछेक महीनों में ही वह सेवानिवृत्त होने वाले हैं. उनका यह भी कहना है कि सिंह की इस नियुक्ति ने नई समस्या भले खड़ी कर दी हो, लेकिन सीईए के कामकाज पर बुरा असर डालने वाली यह अकेली समस्या नहीं है. सीईए पहले ही अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है. सूत्र बताते हैं कि अथॉरिटी में 170 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं जिनमें अधिकांश पद तकनीकी हैं. इन पदों को भरने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा. अब जबकि अथॉरिटी के शीर्ष पद के लिए मारामारी मची है, सीईए को भविष्य में और ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है और यह ऊर्जा क्षेत्र में चल रही तमाम परियोजनाओं के लिहाज़ से अच्छी ख़बर नहीं है.

ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़ा करने वाले नौकरशाह

चंडीगढ के पास मोहाली में अवैध ज़मीन अधिग्रहण के मामले की जांच कर रहे पंजाब पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने उच्च न्यायालय को पेश रिपोर्ट में यह ख़ुलासा किया है कि मोहाली के डिप्टी कमिश्नर द्वारा पांच सौ एकड़ ज़मीन का हस्तांतरण अवैध है. डिप्टी कमिश्नर ने यह ज़मीन नेताओं और नौकरशाहों के नाम हस्तांतरित की थी. अदालत ने अब इस मामले की जांच का ज़िम्मा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक चंदर शेखर को सौंपा है. वह इन आरोपों की जांच करेंगे कि ग्राम पंचायत की पांच सौ एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन प्रभावशाली नेताओं और नौकरशाहों के हाथों में कैसे चली गई.

ज़मीन पर अवैध क़ब्ज़े का ऐसा ही एक मामला गुजरात से भी प्रकाश में आया है. आरोप है कि सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड (एसएसएनएनएल) की इस ज़मीन पर नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों ने क़ब्ज़ा कर लिया है. उन्होंने इस ज़मीन पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक रेजिडेंशियल कालोनी का निर्माण किया है. चार सौ एकड़ ज़मीन का यह टुकड़ा वनीकरण के लिए 15 सालों की लीज पर एसएसएनएनएल को 1993 में दिया गया था. मामले के प्रकाश में आने के बाद एसएसएनएनएल के संयुक्त प्रबंध निदेशक और आईएएस अधिकारी के श्रीनिवास के खिलाफ राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करने संबंधी मामला दायर किया गया है. लेकिन हमारे देश की क़ानून व्यवस्था जिस तरह काम करती है, उसे देखकर इसकी संभावना कम ही है कि प्रभावशाली बाबुओं और नेताओं की इस जमात का बाल भी बांका होगा.

dilipcherian@chauthiduniya.com

खेल ख़त्म नहीं हुआ

चार सप्ताह पहले ही चौथी दुनिया ने एक सनसनीखेज ख़बर छापी थी, जिससे क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया. हमने पहली बार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, आईपीएल, ललित मोदी और अंडरवर्ल्ड के गोरखधंधे का पर्दाफ़ाश किया तो बाक़ी दुनिया बस मूक दर्शक बनी हुई थी. फिर अचानक जैसे एक धमाका हुआ और कोई कुछ समझ पाए, इससे पहले ही सारे गड़े मुर्दे उखड़ने शुरू हो गए. ललित मोदी द्वारा ट्विटर पर की गई एक टिप्पणी ने क्रिकेट के नाम पर चल रहे काले कारनामों पर से परदा हटाया. आज यह खेल गेंद और बल्ले के बीच के संघर्ष से कहीं दूर पैसा कमाने का धंधा, ब्लैक मनी को व्हाइट करने की मशीन में बदल चुका है. क्रिकेट का खेल महज़ एक छलावा बन कर रह गया है और क्रिकेट का जुनून पालने वाली देश की जनता बेवकूफ बन रही है. अंडरवर्ल्ड और क्रिकेट अधिकारियों की कृपा से यह अब ऐसा तमाशा बन चुका है, जिसमें खिलाड़ी से ज़्यादा बड़ी भूमिका सट्टेबाज़ों और सुंदर-कमसिन बालाओं की होती है. कोच्चि विवाद से चर्चा में आई सुनंदा पुष्कर ने अब साफ़-साफ़ कहना शुरू कर दिया है कि आईपीएल में अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के पैसे लगे हुए हैं. जो बात क्रिकेट से जुड़े हर नेता, अधिकारी और खिलाड़ी को पता है, वो सुनंदा अब कह रही हैं. उनका दावा है कि ललित मोदी दाउद इब्राहिम के एजेंट की तरह काम करता है. अब सुनंदा पुष्कर से यह बात पूछनी चाहिए कि अगर उन्हें अंडरवर्ल्ड और आईपीएल के रिश्ते के बारे में पता था, तो फिर भी वो आईपीएल से क्यों जुड़ना चाहती थी.

चौथी दुनिया ने जब यह बताया कि आईपीएल के तीसरे सीज़न का फाइनल मुक़ाबला दो छुपे रूस्तमों के बीच होगा और मुंबई इंडियंस टीम इस बार फाइनल तक जाएगी तो किसी को एकबारगी भरोसा नहीं हुआ. इसकी वजहें भी थीं. उस समय टूर्नामेंट अपने शुरुआती दौर में था और मुंबई की टीम लीग के पहले दो सीज़न में सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकी थी. लेकिन हमारी रिपोर्ट किसी पंडित की भविष्यवाणी नहीं थी. कई सटोरियों से बातचीत पर आधारित थी. उस समय न तो शशि थरूर का विवाद था, न ही मोदी के ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई की सुगबुगाहट. फिर भी हमने चार सप्ताह पहले ही अपनी रिपोर्ट में राजनीतिज्ञों (ख़ासकर दो केंद्रीय मंत्रियों) की संलिप्तता की चर्चा भी की थी. साथ ही, यह भी बताया था कि ललित मोदी ने किस तरह आईपीएल के माध्यम से सट्टेबाज़ी के धंधे को कॉरपोरेट शक्ल दे दी है.

असलियत यह है कि आईपीएल के हर मैच में दो-दो जगहों पर मुक़ाबला होता है. एक मैदान के अंदर और एक मैदान के बाहर. मैदान के अंदर खिलाड़ियों के बीच बैट, बॉल और रनों का संघर्ष चलता है, लेकिन मैदान के बाहर सट्टेबाज़ों का अलग खेल होता है. यहां पैसे की जंग होती है. मैदान के अंदर का खेल टीवी पर दिखाई देता है, लेकिन जो असल खेल है वह दुनिया की निगाहों से बचा कर खेला जाता है. इस खेल को खेलने वालों का मक़सद आईपीएल के तमाशे से पैसा कमाने का होता है, जिसमें देश के कई नामचीन लोग शामिल हैं.

यह सारा खेल केवल पैसे का है. आज चारों ओर यह चर्चा है कि किंग्स इलेवन पंजाब की टीम सट्टेबाज़ी के गोरखधंधे में शामिल है. ख़बरें तो यह भी बताती हैं कि आयकर विभाग के अधिकारियों को इसके पूरे सबूत मिल चुके हैं. जो काम लीग के दूसरे सीज़न में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किया था, तीसरे सीज़न में वही काम किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने किया. अब ज़रा इस साल के आईपीएल के आख़िरी लीग मैच को याद कीजिए. आईपीएल में सब टीमों पर भारी पड़ने वाली मुंबई टीम सबसे फिसड्डी टीम शाहरुख ख़ान की कोलकाता नाइट राइडर्स से हार गई. हालांकि, इस मुक़ाबले से पहले ही मुंबई की टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो चुका था, फिर भी मुंबई की जीत निश्चित मानी जा रही थी. सट्टा बाज़ार में मुंबई की जीत पर हर एक रुपये पर 20 पैसे का भाव लगा था, जबकि कोलकाता की जीत की हालत में हर एक रुपये पर पांच रुपये का दांव लगा था. फिर भी, कोलकाता की टीम यह मैच जीत गई. इससे कोलकाता टीम के मालिक शाहरुख ख़ान को जमकर फ़ायदा हुआ, लेकिन असली मलाई तो भारतीय टीम के एक पूर्व सलामी बल्लेबाज़ ने काटी. टीम के मालिकों से लेकर राजनेता और आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी तक रेवड़ियां समेट कर और पैसे को विदेशों में पहुंचाकर सुकून से हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आईपीएल घोटाले में मंत्री भी शामिल हैं

न जाने इस देश को क्या हो गया है. जहां कहीं भी कोई बुराई नज़र आती है उसमें खादी पहनने वाले नेताओं का नाम आना अनिवार्य हो गया है. सट्टेबाज़ी के धंधे में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल का नाम काफ़ी जाना-पहचाना है. इसके अलावा सत्यजीत गायकवाड़ और कांग्रेस आलाकमान के क़रीबी होने का दावा करने वाले बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें भरपूर दख़ल रखते हैं. जैसे जैसे आईपीएल घोटाले की तहक़ीक़ात बढ़ती जाएगी. कई और सफ़ेदपोश नेताओं पर छींटें पड़ेंगे. नेताओं की चालाकी यह है कि ये खुलकर सट्टेबाज़ी नहीं करते, बल्कि यह ज़िम्मा कुछ ख़ास लोगों को दे देते हैं, जो इनके लिए एजेंट की तरह काम करते हैं. इन लोगों में रॉकी, पटेल, राजपूत और लावन्या के नाम लिए जा सकते हैं. डगलस मॉरिशस में बैठकर ललित मोदी के धंधे का संचालन करता है तो एंड्रयू लंदन में. पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ललित मोदी के प्रियपात्र हैं तो विजय माल्या और प्रफुल्ल पटेल की दोस्ती जगज़ाहिर है. एक हाई प्रोफाइल एयरलाइन कंपनी को विशेष रियायतें दी जाती हैं क्योंकि दोनों रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की टीम के साथ जुड़े हैं.

आईपीएल मैच के बाद पार्टी में मौज-मस्ती करते खिलाड़ी.

चौथी दुनिया
देश का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 2 अंक 8
दिल्ली, 03 मई–09 मई 2010

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63, नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.

संपादकीय 0120–4783999/11–23418962
विज्ञापन + 91 9873575318
प्रसार + 91 9910220786
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16 (+4)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

ललित मोदी का वर्तमान जितना दागदार है, उनका इतिहास उससे भी ज़्यादा रंगीन और काले कारनामों से पटा पड़ा है. ललित मोदी मशहूर उद्योगपति और गॉडफ्रे फिलिप इंडिया कंपनी के मालिक केके मोदी के बेटे हैं.

ललित मोदी का सफ़रनामा

पूरी दुनिया ललित मोदी के जिस चेहरे को जानती है, वह चेहरा नकली है. ललित मोदी की असलियत से हम पर्दा उठाएं, इससे पहले यह सवाल करना ज़रूरी है कि इस विवाद की शुरुआत होने तक शरद पवार, विजय माल्या, प्रफुल्ल पटेल, आई एस बिंद्रा, फारुख़ अब्दुल्ला और शिल्पा शेट्टी आईपीएल की सफलता के लिए ललित मोदी की पीठ थपथपा रहे थे. लेकिन मामला गर्म होते ही उनके सबसे अजीज़ दोस्त शाहरुख़ ख़ान ने चुप्पी साध ली. इस पूरे विवाद में शाहरुख ख़ान की ख़ामोशी का राज़ क्या है? क्या शाहरुख़ मोदी के असली चेहरे से वाक़िफ़ हैं या फिर ख़ुद को इस आग से बचाने के लिए एक स्ट्रेट्ज़ी के तहत काम कर रहे हैं. ललित मोदी का असली चेहरा यह है कि वह आज दुनिया का सबसे बड़ा सट्टेबाज़ है. दुनिया की 15 सबसे बड़ी सट्टा लगाने वाली कंपनियों में ललित मोदी का हिस्सा है. मतलब यह कि मैच दिल्ली में हो या फिर लंदन या सिडनी में, जिस मैच पर भी सट्टेबाज़ी होती है, ललित मोदी को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है. सरकार को इस बात की तहक़ीक़ात करनी चाहिए कि इतना बड़ा सट्टेबाज़ हमारे देश में क्रिकेट की सबसे महत्वपूर्ण संस्था का हिस्सा कैसे बन गया. वे कौन लोग थे जिन्होंने ललित मोदी को बीसीसीआई में अधिकारी बनाने में मदद की. वे कौन लोग हैं जिन्होंने उसे राजस्थान क्रिकेट एसोशिएसन का अध्यक्ष बनाया.

ललित मोदी का वर्तमान जितना दागदार है, उनका इतिहास उससे भी ज़्यादा रंगीन और काले कारनामों से पटा पड़ा है. ललित मोदी मशहूर उद्योगपति और गॉडफ्रे फिलिप इंडिया कंपनी के मालिक केके मोदी के बेटे हैं. 15 हज़ार करोड़ रुपये के कारोबार वाली यह कंपनी फोर स्क्वायर सिगरेट बनाती है. मोदी बचपन से ही ज़िद्दी और अक्खड़ स्वभाव के थे. उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई अमेरिका में की है जहां वह कई ग़लत आदतों के शिकार हुए. मोदी ड्यूक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. इस दौरान ही उन पर ड्रग्स के सेवन का आरोप लगा था. इस वजह से उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज़ किया गया और उन्हें सजा के अलावा जुर्माना भी भरना पड़ा था. अमेरिका में हुई बदनामी के बाद वे भारत लौटे. पिता ने उन्हें गॉडफ्रे इंडिया कंपनी में डायरेक्टर बना दिया. लेकिन पिता का हाथ बंटाना उन्हें पसंद नहीं आया. वह शुरुआत से ही क्रिकेट और खेल जगत की चकाचौंध के कायल थे. खेल जगत में घुसने के लिए उन्होंने पैसे का ज़ोर लगाया. टेनिस और क्रिकेट प्रतियोगिताओं के प्रायोजक बने. फिर पूर्व भारतीय विकेटकीपर नयन मोंगिया और चार अन्य खिलाड़ियों के साथ करार किया, जिसके तहत उनके बल्लों पर फोर स्क्वायर का लोगो लगा होता था. इसके बाद उन्होंने भारत में ईएसपीएन के वितरण की ज़िम्मेदारी संभाली, लेकिन मोदी इतने से संतुष्ट नहीं थे. वह शुरू से ही यूरोप के लीग फुटबॉल की तर्ज पर भारत में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराना चाहते थे. आईपीएल जैसे किसी टूर्नामेंट की शुरुआत करना उनकी पुरानी ख्वाहिश थी. इसके लिए वह क्रिकेट प्रशासन की दुनिया में प्रवेश पाने को बेताब थे. उनकी यह बेताबी 2004 में रंग लाई, जब वह राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए. इसके बाद उन्हें बीसीसीआई में उपाध्यक्ष, मार्केटिंग के रूप में चुना गया. 2007 में उन्हें आईपीएल के आयोजन के लिए बीसीसीआई की मंजूरी मिली और उन्हें लीग के कमिश्नर पद का ओहदा मिला.

क्रिकेट के खेल से पैसा बनाने में मोदी की महारत का पहला उदाहरण 2006 में अबूधाबी में भारत–पाकिस्तान सीरीज़ के आयोजन के दौरान देखने को मिला. इस सीरीज़ के ब्रॉडकास्टिंग और मर्केंडाइज़िंग अधिकार उन्होंने पहले से दोगुने दामों पर बेचे. अचानक ही बीसीसीआई की कमाई आसमान छूने लगी. इस काम में उन्हें शरद पवार, आईएस बिंद्रा, एमपी पांडोव के अलावा सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री का भी भरपूर सहयोग मिला, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि आख़िर इसका राज़ क्या है. फिर इसके बाद आया आईपीएल और मोदी इसके सर्वेसर्वा बने. इसका मक़सद एक ही था, ग्लैमर की चाशनी में लपेटकर क्रिकेट को बाज़ार में पहुंचाना और इस चकाचौंध के पीछे सट्टेबाज़ी का बेजोड़ खेल चलाना. फ़िल्मी सितारे से लेकर कॉरपोरेट घराने और राजनेता तक आईपीएल एक्सप्रेस में सवार हो गए. उस दौरान शरद पवार बीसीसीआई के अध्यक्ष थे और मोदी को आईपीएल से जुड़े हर मामले में फ़ैसला लेने की पूरी छूट थी. उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया और कई टीमों में हिस्सेदारी ख़रीद ली. यह हिस्सेदारी कहीं बेनामी है तो कहीं उनके रिश्ते–नातेदारों के नाम. राजस्थान रॉयल्स टीम में मोदी के रिश्तेदार के शेयर हैं तो किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से वह मोहित बर्मन के माध्यम से जुड़े हैं. मोहित, ललित मोदी के दामाद गौरव बर्मन के भाई हैं. बर्मन, मोदी और आईपीएल के रिश्ते यहीं तक सीमित नहीं हैं. बर्मन आईपीएल के इंटरनेट अधिकार से जुड़ी डील में भी शामिल हैं. मोदी के आर्थिक हित वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप, निंबस और परसेप्ट कंपनियों से भी जुड़े हैं. 80 करोड़ रुपये की फैसिलिटेशन फीस के भुगतान को लेकर वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ हुए समझौते पर आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि इसमें फेमा क़ानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है. सूत्रों के मुताबिक़ मोदी ने लीग की टीमों में हिस्सेदारी ख़रीदने के लिए पिछले रास्ते का सहारा लिया. बहामास और मारिशस जैसी जगहों पर ऐसी बेनामी कंपनियां बनाई गईं जिनका पेड अप कैपिटल उनके निवेश से कहीं कम था. शाहरुख़ ख़ान और राज कुंद्रा के साथ नज़दीकी रिश्ते इसमें उनके मददगार बने. मोदी केवल आईपीएल की टीमों और उनके मालिकों से ही नज़दीक नहीं हैं, बल्कि सट्टेबाज़ों से मिली जानकारी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंकाई टीमों के खिलाड़ियों से भी उनके निकट संबंध हैं और इन टीमों तक उनकी सीधी पहुंच है, जिसके बूते वह मैचों का परिणाम प्रभावित करने में सफल होते हैं. लैडब्रोक्स हो या लंदन या फिर दुबई, मोदी के विश्वस्त सिपहसलारों की फौज इन जगहों पर बैठकर सट्टा लगाती है और वह अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की मदद से करोड़ों की कमाई करने में कामयाब होते हैं. केवल तीन साल के अंदर 30 हज़ार करोड़ रुपये के मालिक बने मोदी का इतिहास और वर्तमान ऐसे गोरखधंधों से पटा पड़ा है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि आज तक किसी ने इस पर अंगुली नहीं उठाई. आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल में पूर्व खिलाड़ी से लेकर राजनेता और देश के नामी वकील तक शामिल हैं, लेकिन उनका दावा है कि वे मोदी की इन कारगुज़ारियों से अंजान थे. कुछ सदस्यों का तो यह भी कहना है कि कई बार आईपीएल के डीलों की पूरी जानकारी भी उन्हें नहीं दी जाती थी. यदि ऐसा है तो वे इतने दिनों तक चुप क्यों बैठे रहे. आज जब सारी दुनिया मोदी के पीछे पड़ी है, तो इस तरह के बयान देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश ज़िम्मेदारियों से भागना नहीं तो और क्या है.

अगर कोई मुक्केबाज़ या वेटलिफ्टर अनजाने में या फिर कोच के झांसे में आकर ग़लती से भी ड्रग्स ले लेता है तो उस खिलाड़ी को आजीवन बैन कर दिया जाता है. मेडल छीन लिए जाते हैं. बेचारे ये ग़रीब खेलों के असहाय खिलाड़ी न्याय की गुहार करते–करते थक जाते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती. अगर खेल का यही क़ानून है तो यह क्रिकेट पर क्यों नहीं लागू है. अब इस सवाल का जवाब कौन देगा कि कैसे एक ऐसे शख्स को आईपीएल का सर्वेसर्वा बना दिया गया, जिस पर ड्रग्स लेने और बेचने का संगीन आरोप लग चुका हो और जिसके लिए उसे सजा भी मिल चुकी हो.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कहीं यह चिंगारी शाहरुख़ को न जला दे

मोदी के ट्विटर से उठे बवाल का अंत क्या होगा. अब लोगों की नज़र शाहरुख़ ख़ान पर जा टिकी है. जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, उससे यही लगता है कि आईपीएल की इस चिंगारी से शाहरुख भी नहीं बच पाएंगे. शाहरुख़ ख़ान पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम के साथ मिलकर आईपीएल में सट्टेबाज़ी का आरोप लग रहा है. आज जब आईपीएल की हर टीम के शेयर होल्डिंग पैटर्न का ब्यौरा निकाला जा रहा है, तो सबसे सनसनीखेज मामला शाहरुख़ ख़ान की कोलकाता नाइट राइडर्स का सामने आ रहा है. इसमें मारिशस बेस्ड एक कंपनी का नाम आ रहा है. इस कंपनी के मालिक जय मेहता हैं. जय मेहता शाहरुख़ के पार्टनर हैं और फ़िल्म अभिनेत्री जूही चावला के पति हैं. हैरानी की बात यह है कि जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल मात्र 100 डॉलर था, उसमें अचानक से पचास करोड़ रुपये जमा हो जाते हैं. रातोंरात यह कंपनी बड़ी बन जाती है. विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि यह पैसा दाउद के किसी सहयोगी ने बेटिंग के एडवांस के रूप में दिया था. तभी इस बात का भी खुलासा हुआ कि क्यों अकरम को टीम का बॉलिंग कोच बनाया गया, जबकि किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी को किसी भी आईपीएल टीम में नहीं रखा गया. यह बात भी जग ज़ाहिर है कि आईसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक़ वसीम अकरम के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं. यह भी जगज़ाहिर है कि आईपीएल की सारी टीमों में से मोदी के सबसे क़रीबी शाहरुख खान हैं. जब सुनंदा पुष्कर आईपीएल में दाउद इब्राहिम की बात करती हैं तो यही लगता है उनको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि किस टीम में दाउद के कितने पैसे लगे हैं और ये पैसे किस काम के लिए दिए गए हैं. आईपीएल के शुरुआत से ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को लेकर हंगामा होता रहा है. लीग के तीसरे सीज़न में किसी भी टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपनी टीम में नहीं चुना. लेकिन वसीम अकरम के शाहरुख़ ख़ान की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के गेंदबाज़ी कोच बनने पर किसी ने अंगुली नहीं उठाई. शाहरुख़ को इसकी इजाज़त कैसे मिली, जबकि अकरम पर सट्टेबाज़ी में शामिल होने और अंडरवर्ल्ड से तार जुड़े होने के आरोप कई बार लग चुके हैं. ताज्जुब की बात है कि अकरम को लेकर किसी ने आज तक कोई सवाल नहीं किया. शाहरुख़ के चारों ओर सब कुछ संदेहास्पद लगता है, लेकिन ग्लैमर की चादर तले सब कुछ छुप जाता है. कांग्रेस पार्टी शाहरुख़ के लिए हर नियम–क़ानून को ताक पर रखने को तैयार हो जाती है जबकि उसे यह पता है कि किंग ख़ान ललित मोदी के निकटतम दोस्तों में हैं.

पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम लगातार हारती चली गई तो लोगों ने इसे कोच जॉन बुकानन की ग़लत नीतियों और टीम में गुटबाज़ी का नतीजा माना. कुछ हद तक यह सही भी है लेकिन सच यह भी है कि इससे सट्टेबाज़ों को जमकर फ़ायदा हुआ. उन्होंने सौ करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई की. लेकिन इसने एक दूसरे संदेह को भी जन्म दिया, शाहरुख ख़ान और ललित मोदी के बीच के रिश्ते. यह किसी से छुपा नहीं है और कोई अंदर झांक कर देखे तो आसानी से यह जान सकता है कि किस तरह शाहरुख़ ख़ान के लोगों ने उनकी टीम की हार से कमाई की. इसमें संदेह की सुई एक पूर्व भारतीय कप्तान पर भी घूमती है जो वसीम अकरम और डेव व्हाटमोर के साथ मिलकर इसे अंजाम देते हैं. जनता कभी यह नहीं जान पाएगी कि केकेआर की हार की वजह क्या रही, लेकिन संदेह की यह चिंगारी शाहरुख़ ख़ान को भी जला सकती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

आईपीएल की अंदरूनी कहानी

आईपीएल के मैचों का जो हाल है, आईपीएल से जुड़ी सारी घटनाओं का वही हाल है–सब कुछ परदे के पीछे से होता है. आईपीएल की शुरुआत से 20 दिन पहले शरद पवार बाल ठाकरे से मिलने उनके घर जाते हैं. मीडिया इन दोनों की मुलाक़ात का राजनीतिक मतलब निकालने में जुट जाता है. उसे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति के ये दो दिग्गज आपसी गठजोड़ की संभावनाएं तलाशने इकट्ठा हुए हैं. मीटिंग से बाहर निकल पवार कहते हैं कि मीटिंग का असली मक़सद मुंबई में होने वाले आईपीएल के मैचों की सुरक्षा और इंटरटेनमेंट टैक्स पर चर्चा करना था. लेकिन वह अंदर से कुछ और ही खिचड़ी पकाकर बाहर निकले थे. सूत्रों के मुताबिक़ शरद पवार ने एक हज़ार करोड़ में सौदा तय किया था. वैसे यह भी सोचने वाली बात है कि जब भी क्रिकेट की बात होती है तो शिवसेना विरोध में उतर जाती है, लेकिन अब शायद आपको यह अंदाज़ा लग गया हो कि इस सारे शोर–शराबे के बीच शिवसेना चुप क्यों है. आईपीएल शुरू हुआ और इसके साथ ही शुरू हुआ क्रिकेट इतिहास में सट्टेबाजी का सबसे बड़ा खेल. अकेले लैडब्रोक्स में लगे सट्टे की रकम विश्व कप क्रिकेट पर लगी रकम से ज्यादा है. हर दिन पांच हजार करोड़ रुपये का वारा–न्यारा होता है. सारा लेनदेन अमेरिकी डॉलर में होता है और पैसों को मारिशस, दुबई और लंदन के सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया जाता है. काले धन को कारपोरेट घरानों के रास्ते सफेद बनाकर दोबारा निवेश करने का इससे बढिया रास्ता भला और क्या हो सकता है. लीग की शुरुआत से ठीक दस दिन पहले मोदी के पास अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का धमकी भरा फोन आता है. अब मोदी भी कोई छोटे खिलाड़ी तो हैं नहीं, कई लोगों से उनके खुद भी संबंध हैं. हम सुनंदा पुष्कर के आरोपों की चर्चा पहले ही कर चुके हैं. उन्हें जानकारियां देने और मुकाबलों को फिक्स करने के लिए तैयार किया जाता है. बदले में जो रकम उन्हें मिलती है, उसकी शायद आपने कल्पना भी न की हो.

सट्टेबाज हर चीज पर दांव लगाते हैं. कौन सी टीम खिताब जीतेगी, यह तो है ही, लेकिन यहां तो हर मुकाबले की तकरीबन हर गेंद पर दांव लगा है. मैच कौन जीतेगा, कौन सी टीम कितने रन बनाएगी, और तो और कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाएगा, इस पर तक दांव लगा है. हर मुक़ाबले से अंडरवर्ल्ड कम से कम 60–80 करोड़ की कमाई करता है तो मोदी की जेब में 15–18 करोड़ रुपये चुपके से पहुंच जाते हैं.

अब इन पैसों का बंटवारा कैसे होता है. शक़ की पहली सुई बीसीसीआई के कर्ताधर्ता अधिकारी और बोर्ड के छह सदस्यों की ओर जाती है. थोड़ा और आगे बढ़ें तो मोदी के साथ शरद पवार और टीमों के प्रमोटर्स का नाम उभरकर सामने आता है. लेकिन इन सबके बीच खिलाड़ी कहां हैं? क्या वे इस गोरखधंधे में शामिल नहीं हैं? सट्टेबाज़ों की माने तो वीरेंद्र सहवाग, अनिल कुंबले और कई अन्य खिलाड़ी परदे के पीछे रहकर मैचों के परिणामों को प्रभावित करते हैं. लेकिन इनका नाम कौन लेगा? ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि यदि हो गया तो सारा सिस्टम ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा.

सट्टेबाज़ी के इस खेल में कोई दूध का धुला नहीं है, वह चाहे फ़िल्म स्टार हो, क्रिकेट खिलाड़ी, राजनेता या फिर खेल प्रशासक. बॉलीवुड के नज़रिए से देखें तो इस पूरे प्रकरण पर एक फ़िल्म बनाई जा सकती है, जिसका नाम होगा, हमाम में सब नंगे हैं. हम चर्चा ललित मोदी के भविष्य की कर रहे थे. सच्चाई यह है कि मामला सत्ताधारी पार्टी के हाथों से भी निकल चुका है. वह भी कुछ ख़ास नहीं कर सकती, लेकिन पैसा हो तो सब कुछ संभव है. एक बार फिर पैसों का लेनदेन होगा, सैकड़ों–हज़ारों करोड़ रुपये एक हाथ से दूसरे हाथ तक का सफ़र तय करेंगे और सारे मामले की लीपापोती हो जाएगी.

आज क्रिकेट की धमक संसद के अंदर भी सुनाई दे रही है. मंत्री पैसे बना रहे हैं, आईपीएल कमिश्नर पैसे बना रहे हैं, पुराने से लेकर नए खिलाड़ियों तक का बैंक अकाउंट हर मुक़ाबले के बाद बढ़ता जा रहा है. क्रिकेट को अपना धर्म मानने वाली जनता तो केवल ख़ामोश, अंजानी गवाह बन कर रह गई है, जबकि यह सारा खेल उसके पैसों से ही हो रहा है. आप बेवजह चिंता न करें क्योंकि क्रिकेट के मैदान को गंदला करने वाले ये गंदे और ख़तरनाक चेहरे कभी खुलकर सामने नहीं आएंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पिछले कुछ सालों से टी-20 क्रिकेट की लोकप्रियता ने गेंद और बल्ले के इस खेल को नया आयाम दिया है, लेकिन हैरत की बात है कि सट्टेबाज़ी के रोग से यह भी अछूता नहीं है.

दिल्ली, 03 मई-09 मई 2010 चौथी दुनिया

चौथी दुनिया ने पहले ही किया था ख़ुलासा

यह आईपीएल नहीं इंडियन फिक्सिंग लीग है

चौथी दुनिया ने यह रिपोर्ट तीस दिन पहले छापी थी, जब आईपीएल का तीसरा सीजन शुरू ही हुआ था. सट्टेबाज़ों से बातचीत के आधार पर तैयार इस रिपोर्ट में हमने ख़ुलासा किया था कि मैच के मुक़ाबले पहले से ही फिक्स हैं और फिक्सिंग के इस खेल में खिलाड़ी से लेकर क्रिकेट के कर्ताधर्ता, राजनेता और फ़िल्मी सितारे तक जुड़े हैं.

महाभारत युग में द्रौपदी का चीरहरण कोई अतिश्योक्ति नहीं, बल्कि समाज का एक आईना था, तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का वास्तविक प्रतिबिंब था. खेल की दुनिया अब दूध की धुली नहीं है और भारत इसका अगला ठिकाना है. क्रिकेट में फिक्सिंग का खेल तो अब कॉरपोरेट का रूप लेता जा रहा है. पहले इस खेल में अंडरवर्ल्ड, सट्टेबाज़ और कुछ पूर्व खिलाड़ी शामिल होते थे, लेकिन अब तो ख़ुद क्रिकेट बोर्ड ही इसका एक हिस्सा बन चुका है.

मैच फिक्सिंग का खेल सिर्फ़ भारत, पाकिस्तान और शारजाह तक ही सीमित नहीं है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों तक सटोरियों का दबदबा है. क्रिकेट के इतिहास में ऐसे कई मैच दर्ज़ हैं, जो सट्टेबाज़ों की वजह से सुर्ख़ियों में रहे हैं. 1999 के विश्वकप में बांग्लादेश के हाथों पाकिस्तान की हार हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी, 2000 में भारतीय टीम का फाइनल तक का सफर हो या फिर विश्व कप-2003 में टीम इंडिया का फाइनल में जगह बनाना, क्रिकेट की अनिश्चितताओं के बीच इन सभी मुक़ाबलों पर मैच फिक्सिंग का काला साया भी लगातार अपना असर छोड़ता रहा है. पाकिस्तानी टीम की हार के पीछे की कहानी तो यह है कि ख़ुद खिलाड़ी ही अपनी हार के लिए दांव लगाते हैं.

पिछले कुछ सालों से टी-20 क्रिकेट की लोकप्रियता ने गेंद और बल्ले के इस खेल को नया आयाम दिया है, लेकिन हैरत की बात है कि सट्टेबाज़ी के रोग से यह भी अछूता नहीं है. टी-20 की लोकप्रियता ने क्रिकेट में लीग कल्चर को बढ़ावा दिया तो आईपीएल बॉलीवुड और उद्योग जगत को क्रिकेट के साथ जोड़कर कामयाबी की नई इबारतें लिख रहा है. लेकिन इसके साथ ही इसने खेल में सट्टेबाज़ी को भी उद्योग का दर्ज़ा दिला दिया है. यहां राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं नहीं होतीं, खिलाड़ी टीम फ्रेंचाइजी के स्टाफ भर होते हैं और उन्हें वही करना होता है, जो मालिक की इच्छा होती है. आईपीएल में केवल खिलाड़ियों की ही ख़रीद-फरोख्त नहीं होती, बल्कि यहां तो मालिक से लेकर पूरा कुनबा ही बिकने के लिए तैयार है. एक सट्टेबाज़ के मुताबिक़, आईपीएल से जुड़ी बॉलीवुड की एक बड़ी हस्ती और उद्योग जगत की एक मशहूर शख्सियत मैदान पर तो अपनी टीम की जीत के लिए खेलते हैं, लेकिन मैदान के बाहर ख़ुद अपनी टीम की हार के लिए दांव लगाने से भी नहीं चूकते. और, उनका साथ देते हैं लीग के ही एक सर्वशक्तिमान अधिकारी और बीसीसीआई में उनके आका.

आठ टीमें, फ़िल्म स्टार्स, चीयरगर्ल्स, पुरज़ोर मार्केटिंग. प्रायोजक राशि इतनी कि लोगों का सिर चकरा जाए. बॉलीवुड के सितारे, मॉडल, राजनीति के खिलाड़ी और बड़ी-बड़ी ब्रांडिंग कंपनियां इस महा आयोजन के लिए एक साथ जमा हुए. हर टीम ने दस साल के लिए 400 से 600 करोड़ रुपये की राशि अदा की. आकलन के मुताबिक़, केवल तीन सालों में टेलीविज़न अधिकार, स्पांसरशिप और गेट फीस से वे इस रकम की भरपाई करने में कामयाब हो जाएंगे. कुछ दिन पहले आईपीएल में दो टीमों की बढ़ोतरी हुई. पुणे और कोच्चि की टीमों की क़ीमत बाक़ी आठ टीमों की कुल क़ीमत से भी ज़्यादा है. अब इन दोनों टीमों को फ़ायदा कैसे होगा, यह सवाल अहम है. इसका जवाब कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट या ब्रांड प्लानर नहीं दे सकता. इसका जवाब हमें कुछ सट्टेबाज़ों ने दिया. उन्होंने बताया कि पैसे का असली स्रोत तो फिक्सिंग है. ब्रांडिंग और टीवी पर आने वाले प्रचार बस दिखावा भर हैं. इन सट्टेबाज़ों की बातों पर कितना विश्वास किया जाए, यह कहना तो मुश्किल है. उनकी बातें सौ फ़ीसदी सही हों, यह भी नहीं माना जा सकता और न ही हम ऐसा दावा करते हैं कि इन सटोरियों ने जो कुछ बताया है, वह पूरी तरह सही है. लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने जो सवाल उठाए, वे ग़ौर करने लायक़ ज़रूर हैं.

आईपीएल-1

टूर्नामेंट में सबसे कमज़ोर समझी जाने वाली टीम राजस्थान रॉयल्स अंत में विजेता बनी. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले रॉयल्स की जीत पर एक रुपये पर 25 रुपये का दांव लगा था. रॉयल्स जीत गए. और, इसके साथ ही बीसीसीआई के छह शीर्ष अधिकारी, आईपीएल के एक शीर्ष अधिकारी एवं टीम के मालिक भी जीते. इनमें से हरेक की जेब में 40-80 करोड़ रुपये पहुंच गए. टूर्नामेंट के 35 दिनों के दौरान 50,000 करोड़ से ज़्यादा के सट्टे का खेल खेला गया. क्रिकेट का यह नया स्वरूप अनोखा भले हो, लेकिन यह लगातार चलने वाला है. आरोप तो यहां तक लगा कि आईपीएल के अनेक शीर्ष अधिकारियों और ख़ासतौर से इसके एक बड़े अधिकारी को ही अकेले 200 करोड़ रुपये का फ़ायदा हुआ. पर इस ख़बर के आने के बाद भी जांच के लिए किसी की भी आवाज़ नहीं उठी. किसी को कानोंकान ख़बर भी नहीं हुई, कोई जांच नहीं, कोई हो-हल्ला नहीं. आख़िर हो भी तो कैसे? जब सटोरियों की टोली में शीर्ष राजनीतिक दलों के नेताओं के भी शामिल होने की बात होने लगे, तो फिर जांच का सवाल ही नहीं उठता.

आईपीएल-2

सुरक्षा कारणों से इस बार यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया. रॉयल चैलेंजर्स ने नया कप्तान नियुक्त किया. सट्टा बाज़ार के मुताबिक़, बैंगलोर और डेक्कन चार्जर्स की टीमें खिताबी दौड़ में सबसे पीछे थीं. मैच का परिणाम क्या हो, इसका फ़ैसला लीग के अधिकारियों और टीमों के मालिकों ने मिलकर किया. मुक़ाबलों के नतीजों को ऐसे मोड़ा गया कि कोई भी कुछ समझ नहीं पाया. वैसे भी टूर्नामेंट से जुड़े प्रायोजक, बॉलीवुड के सितारे और एक्सपर्ट कमेंटेटरों की टीम आदि टीआरपी के लिए पर्याप्त थे. कोई अंदर झांक कर नहीं देखता, लेकिन अंदर की दुनिया बड़ी गंदी है. इस बार डेक्कन चार्जर्स की टीम जीती, जबकि रॉयल चैलेंजर्स उप विजेता बनी. एक बार फिर 1500 करोड़ रुपये का बंदरबांट हुआ, जिसमें से 400 करोड़ अकेले लीग अधिकारी की जेब में गए, ऐसा बताया गया.

आईपीएल-3

टूर्नामेंट जब शुरू हुआ तो कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीमों को सबसे फिसड्डी माना जा रहा था, लेकिन आगे चलकर अचानक ही दृश्य बदलने लगा. आप मानें या न मानें, लेकिन कहा जा रहा है कि तीसरे सीजन में आईपीएल पर लगभग 70,000 करोड़ रुपये का सट्टा लग चुका है. पिछले साल एक बड़े फ़िल्मी सितारे की हाई प्रोफाइल टीम मैदान पर अपने प्रदर्शन से ज़्यादा दूसरे कारणों से चर्चा में रही. लेकिन उसकी टीम नैचुरली हार रही थी या उसे हारना ही था, यह बात खिलाड़ियों से ज़्यादा सट्टेबाज़ ही जानते हैं. और, यदि उनकी बातों पर भरोसा करें तो लगातार हो रही हारों के बावजूद टीम का मालिक सौ करोड़ से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने में कामयाब रहा. इसमें उसकी मदद टीम के ही एक वरिष्ठ खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य ने की. ज़ाहिर है कि लीग के सर्वशक्तिमान अधिकारी उन्हें जिताने से कैसे इंकार कर सकते हैं. सब कुछ पहले से ही तय है. मैदान के बाहर बैठे लोग तो केवल दर्शक भर हैं. टूर्नामेंट अभी अपने शुरुआती दौर में है और अभी तक के प्रदर्शन के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स ख़िताब की सबसे सशक्त दावेदार लगती है. लेकिन, अगले 20 दिनों में तस्वीर का रुख़ पूरी तरह बदल सकता है. बोर्ड के लोग लंदन में बैठकर दांव लगाते हैं तो बॉलीवुड के सितारे का खेल अमेरिका और दुबई से संचालित होता है. हाई प्रोफाइल उद्योगपति के सट्टे का कारोबार हांगकांग और लंदन से चलता है. रॉयल चैलेंजर्स नहीं जीत सकते, क्योंकि जीतना तो किसी छुपे रुस्तम को ही है. सट्टा बाज़ार का यही नियम है, क्योंकि कमज़ोर टीम की जीत में ही सबका फ़ायदा है. लेकिन इसके पीछे छुपे सवालों का जवाब कौन देगा. क्रिकेट के प्रशंसक तो खेल के उतार-चढ़ावों में ही मगन हैं. लेकिन हम आपको बता दें कि आईपीएल यानी इंडियन फिक्सिंग लीग चालू है और भारत के आम क्रिकेटप्रेमी सट्टेबाज़ों के जाल में फंस कर वैसे ही जेब से पैसा निकाल कर उनके हवाले कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स के शिकार लोग अपनी जेब का पैसा ड्रग्स व्यापारियों को देते हैं. दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

तीन महीने में रचा इतिहास

- हिन्दी की सबसे पॉपुलर वेबसाइट
- हर महीने 12,00,000 से ज़्यादा पाठक
- हर दिन 40,000 से ज़्यादा पाठक
- स्पेशल प्रोग्राम-भारत का राजनीतिक इतिहास
- एक्सक्लुसिव ख़बरें, स्कूप और ब्रेकिंग न्यूज़
- संगीत और फ़िल्मों पर विशेष कार्यक्रम
- साई की महिमा

www.chauthiduniya.tv

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301

अंडरवर्ल्ड और सट्टेबाज़ों की मिलीभगत से चलने वाली यह दुनिया बाहर से जितनी रंगीन नज़र आती है, अंदर से उतनी ही हैरतअंगेज और ख़तरनाक है.

IPL की काली दुनिया

आईपीएल की शुरुआत ने क्रिकेट की काली दुनिया को हमारे सामने ला खड़ा किया है. एक ऐसी दुनिया जिसमें खिलाड़ी से लेकर टीमों के मालिक और राजनीतिज्ञ तक एक समान रूप से शामिल हैं. क्रिकेट की इस काली दुनिया में बैट और बॉल से ज़्यादा शराब, शबाब, कबाब और ड्रग्स का ज़ोर चलता है. लेकिन हैरत की बात है कि इस दुनिया का रिंग मास्टर कहीं और बैठा है. अंडरवर्ल्ड और सट्टेबाज़ों की मिलीभगत से चलने वाली यह दुनिया बाहर से जितनी रंगीन नज़र आती है, अंदर से उतनी ही हैरतअंगेज और ख़तरनाक है.

ऐसे फंसते हैं खिलाड़ी

जैसे ही कोई खिलाड़ी अंडर 19 या रणजी ट्रॉफी टीम में शामिल होता है, सट्टेबाज़ों की फ़ौज उन पर नज़र रखना शुरू कर देती है. टीम के सीनियर खिलाड़ी पहले ही उनकी गिरफ्त में होते हैं, लेकिन नए खिलाड़ियों को तब तक इसमें शामिल नहीं किया जाता, जब तक वो विश्वास के क़ाबिल न हो जाएं. इस बीच सट्टेबाज़ों के गुर्गे उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाते हैं. भारतीय टीम का मामला ज़रा अलग है. वहां पर यह खेल कॉरपोरेट घरानों के साथ मिलकर खेला जाता है. सब कुछ इस तरह सुनियोजित होता है कि स्वाभाविक लगे. उदाहरण के लिए यदि टीम को कोई मैच हारना है तो खिलाड़ी अच्छी शुरुआत के बाद आख़िरी ओवरों में आउट हो जाएंगे. विकेटों के पतन से टीम आख़िरी ओवरों में अपेक्षित रन नहीं बना पाएगी और विपक्षी टीम के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखने से दूर रह जाएगी. रही-सही कसर गेंदबाज़ों के लचर प्रदर्शन से पूरी हो जाती है. इधर सट्टेबाज़ टीम की हार के लिए ऐसे दांव लगाते हैं जिस पर कई गुना फ़ायदा होता है. यदि कोई खिलाड़ी सीधे रास्ते इसमें शामिल होने से इंकार करे तो सट्टेबाज़ दूसरे हथकंडे अपनाने से भी नहीं चूकते. उनके तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े होते हैं और उन्हें खिलाड़ियों की हर कमज़ोरनस की जानकारी होती है. आईपीएल जैसे टूर्नामेंटों के दौरान मैचों के बाद होने वाली रंगीन पार्टियों में खिलाड़ी भी शरीक़ होते हैं. मौज-मस्ती के आलम में खिलाड़ी अक्सर बहक जाते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं, जो उनके लिए भारी पड़ जाता है. अंडरवर्ल्ड के लोग भी इन पार्टियों में मौजूद होते हैं और खिलाड़ियों के निजी क्षणों का स्टिंग ऑपरेशन कर अपने पास रख लेते हैं. फिर जब कोई खिलाड़ी सट्टेबाज़ों के मनमाफ़िक प्रदर्शन करने से इंकार करता है तो अंडरवर्ल्ड ख़ुफ़िया कैमरों में क़ैद जानकारियों को लीक करने की धमकी देकर उन्हें मजबूर करता है. अंडरवर्ल्ड और सट्टेबाज़ों का यह तंत्र इतना ख़तरनाक है और इतनी सफ़ाई से काम करता है कि खिलाड़ियों के पास उनकी बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता.

कहां हैं वो मिसिंग फ़ाइलें

आईपीएल कार्यालय में आयकर अधिकारियों के पहुंचने से ठीक पहले गुम हुई ये फ़ाइलें ललित मोदी के पास सुरक्षित हैं. लेकिन पहला सवाल तो यही है कि इन फ़ाइलों को मोदी के ऑफिस से चोरी-छुपे निकालने की ज़रूरत क्या थी, वो भी तब जबकि इन्कम टैक्स के अधिकारी रास्ते में थे. सवाल यह भी है कि इन्कम टैक्स अधिकारियों के ऑफिस पहुंचने की सूचना पहले ही लीक कैसे हो गई. मोदी कहते हैं कि ऐसा हर जगह होता है जब ऑफिस का स्टाफ ज़रूरी काग़ज़ातों की फ़ाइल ऑफिस के बाहर ले जाता है. लेकिन इन फ़ाइलों को जिस फ़िल्मी अंदाज़ में निकाला गया, वह ख़ुद ही किसी घपले की कहानी बयां करती है. यह तो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे का कमाल था, जिससे यह पता चल पाया कि इन फ़ाइलों को लेने के लिए ऑफिस में आने वाला शख़्स और कोई नहीं बल्कि विजय माल्या की बेटी लैला महमूद थीं. यह भी स्पष्ट हो चुका है कि इनमें अदानी और वीडियोकॉन समूहों द्वारा दो कैबिनेट मंत्रियों के रिश्तेदारों को शेयर देने की बात स्पष्ट लिखी हुई है और मोदी एवं उनके पार्टनर्स-इन-क्राइम यह जानकारी सार्वजनिक नहीं होने देना चाहते थे. लेकिन इन फ़ाइलों में केवल कैश फ्लो की ही चर्चा है. परदे के पीछे से होने वाली निवेश और कमाई का कोई आंकड़ा इसमें मौजूद नहीं है, जबकि टीमों के मालिक आईपीएल के हर सीज़न में केवल फिक्सिंग से लगभग 70 करोड़ रुपये की कमाई करते हैं.

किस्सा फ्रेंडशिप सीरीज़ का

जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच मैचों पर प्रतिबंध लगता है, तो देश के प्रबुद्ध लोग खेल और राजनीति को अलग अलग रखने की बात करते नज़र आने लगते हैं. अंग्रेज़ी चैनलों पर बहस शुरू हो जाती है. राजनीति और क्रिकेट का रिश्ता क्या है, यह जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना ज़रूरी है. 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए फ्रेंडशिप सीरीज़ को केवल खेल के मैदान में ही नहीं, बल्कि कूटनीतिक क्षेत्र में भी एक अहम शुरुआत माना गया. इसे स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी का नाम दिया गया लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा सनसनीखेज है. भारत पाकिस्तान के बीच हुई फ्रेंडशिप सीरीज़ का रिश्ता देश में होने वाले चुनाव से था. इसे वोट बैंक राजनीति नहीं बल्कि चुनाव प्रचार में काम आने वाले पैसे को जमा करने के लिए आयोजित किया गया था. इस सीरीज़ को देश की चुनाव व्यवस्था में सट्टेबाज़ी के प्रवेश के रूप में भी देखा जाए तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी. अब तक यह होता आ रहा था कि भारत पाकिस्तान के मैचों पर होने वाली सट्टेबाज़ी पर पूरा कंट्रोल अंडरवर्ल्ड का था और सारा संचालन पाकिस्तान से हो रहा था. इसलिए सट्टे का अधिकांश पैसा पाकिस्तान जा रहा था. अंडरवर्ल्ड के ज़रिए यह पैसा आईएसआई के पास पहुंच जाता, जिसे वह कश्मीरी जनता के ख़िलाफ़ आतंकी कार्रवाईयों में इस्तेमाल कर रहा था.

भारत में 2004 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे और सत्ताधारी दल को पैसे की सख्त ज़रूरत थी. पार्टी के तत्कालीन महासचिव प्रमोद महाजन को क्रिकेट मैच पर लगने वाली सट्टेबाज़ी के बारे में पता चला तो वह इस फ्रेंडशिप सीरीज़ की तैयारी में जुट गए. वह सरकार को मनाने में कामयाब रहे. उन्होंने सट्टे के पैसे का बंटवारा करने की जुगत निकाली. सीरीज़ शुरू होने से पहले ही मैचों का रिज़ल्ट तय हो गया था. दोनों तरफ़ के लोगों ने यह तय किया कि दोनों टीमें एक-एक मैच जीतेंगी और सीरीज़ 1-1 से बराबर रहेगी. पहला मैच किसे जीतना है और दूसरा किसे हारना है, यह भी पहले ही तय हो चुका था. सट्टेबाज़ों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और बदले में दोनों पक्षों को एक-एक हज़ार करोड़ रुपये मिले. अब यह भी इतिहास है किस तरह सट्टे का पैसा पहली बार राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार का हिस्सा बना.

पवार का जादू

पहले ऐसा होता था कि खिलाड़ी टीम की हार से पैसा बनाते थे, लेकिन बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के बाद शरद पवार ने ललित मोदी के साथ मिलकर इस समीकरण को उलट दिया. उन्होंने टीम की जीत से पैसा बनाने की जुगत निकाली और इसके लिए अलग पैंतरा अपनाया. 2007 में भारतीय टीम ने पहले टी20 वर्ल्ड कप में ख़िताबी जीत हासिल की तो इसके बाद टीम का अगला लक्ष्य बना, टेस्ट मैचों में बादशाहत हासिल करना. यह सफल भी रहा, जब भारत 2009 में आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक का ताज़ हासिल करने में कामयाब रहा. इसके लिए मोदी-पवार की जोड़ी ने विदेशी टीमों के सामने पैसों का चारा फेंका. ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को गारंटी मनी के रूप में ज़्यादा पैसे देकर इसके लिए राज़ी कर लिया गया कि वह या तो सीरीज़ हार जाएंगे या ड्रॉ के लिए खेलेंगे. मोदी के साथ मिलकर पवार ने यह योजना बनाई और इससे दोनों का ही फ़ायदा हुआ.

इसके अलावा इस दौरान टीम इंडिया ने 2007 में पहला टी-20 वर्ल्ड कप जीता तो वनडे मैचों में भी विश्व की शीर्ष तीन टीमों में शामिल है.

टीम जीत रही हो तो इसके अपने फ़ायदे हैं. प्रसारण कंपनियां ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए ज़्यादा पैसे देने लगी तो टीम के स्पांसरशिप अधिकार की बोली भी लगभग दोगुनी हो गई. बीसीसीआई की आमदनी आसमान छूने लगी.

लेकिन कितने लोग जानते हैं कि मैचों के नतीजे पहले से ही तय होते हैं. क्रिकेट की दुनिया में भारत का डंका बजने लगा और इसी दरम्यान आईपीएल शुरू होता है. आख़िर पवार का जादू चल ही गया. लेकिन यह मामला मैच फिक्सिंग के अब तक के सभी मामलों से कहीं बढ़कर है. अब यदि भारतीय क्रिकेट की साख बचेगी तो तभी, जब कि भारत वेस्टइंडीज में चल रहे टी20 वर्ल्ड कप में जीत हासिल करे. जीत का ख़ुमार ही कुछ ऐसा होता है कि लोग पिछली सारी बातें भूल जाते हैं.

फोटो-प्रभात पाण्डेय

2007 के बाद से टेस्ट मैचों में भारत का प्रदर्शन

बांग्लादेश में सीरीज जीत	(1-0)
इंग्लैंड में सीरीज जीत	(1-0)
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज जीत	(1-0)
ऑस्ट्रेलिया में पराजय	(2-1)
दक्षिण अफ़्रीका के साथ सीरीज ड्रॉ	(1-1)
श्रीलंका में पराजय	(2-1)
ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ सीरीज जीत	(2-0)
इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज जीत	(1-0)
न्यूजीलैंड में सीरीज जीत	(1-0)
श्रीलंका के ख़िलाफ़ सीरीज जीत	(2-0)
बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज जीत	(2-0)
दक्षिण अफ़्रीका के साथ सीरीज ड्रॉ	(1-1)

सट्टेबाज़ी के धंधे पर है अंडरवर्ल्ड का क़ब्ज़ा

जिनको लगता है कि आईपीएल के मैचों का फ़ैसला मैदान के अंदर होता है, तो हम इसे उनका भोलापन ही कह सकते हैं. क्रिकेट मैच तो बहाना है. आईपीएल सिर्फ़ क्रिकेट ही नहीं, अय्याशी का ऐसा कारोबार है, जिसके जाल में देश के कई नौजवान खिलाड़ी फंस चुके हैं. हर मैच के बाद चार बजे सवेरे तक पार्टियां चलती हैं, जिनमें शराब, शबाब और ड्रग्स का खुलेआम इस्तेमाल होता है. ये पार्टियां कॉरपोरेट घरानों द्वारा आयोजित की जाती हैं और इसमें लगा पैसा अंडरवर्ल्ड और सट्टेबाज़ों का होता है. सच्चाई यह है कि सट्टेबाज़ी के धंधे में अंडरवर्ल्ड का एकछत्र राज है. यदि सट्टे के पैसे को आईपीएल से निकाल दें तो सारा सिस्टम सिकुड़कर रह जाएगा. कोई ग्लैमर नहीं होगा और मीडिया एक तमाशबीन बन कर रह जाएगा. तो क्या गावस्कर और शास्त्री जैसे पुराने धुरंधर भी इसका हिस्सा हैं? हम तो बस इतना ही कहेंगे कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया बड़ी गंदी है. इसके काम करने का तरीक़ा ही कुछ ऐसा है कि कोई चाहे भी तो बच नहीं सकता. ये लोग तब तक अंजान बने रहते हैं जब तक कि इनका काम पूरा न हो जाए. एक बार वो हो गया तो फिर ये ही लोग खिलाड़ियों और खेल प्रशासकों की हर भाव-भंगिमा को अपने अंदाज़ में विश्लेषित कर मीडिया के सामने परोसने में लग जाते हैं.

यह फैसिलिटेशन फीस क्या है

अभी तक यह समझ नहीं आया कि एमएसएम (मल्टीस्क्रीन मीडिया) ने 80 मिलियन की फैसिलिटेशन फीस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप के वेणु नायर को क्यों दी. एमएसएम ने साल 2008 में आईपीएल मैचों के टीवी प्रसारण के अधिकार के लिए 918 मिलियन डॉलर का करार किया. यह करार दस सालों के लिए था, लेकिन 2009 में लीग के दूसरे सीज़न की शुरुआत से ठीक पहले इस करार को रद्द कर दिया गया और प्रसारण अधिकार वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप (डब्ल्यूएसजी)को दे दिए गए. एमएसएम ने अदालत में केस दायर किया, लेकिन फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ गया. हारकर एमएसएम ने प्रसारण अधिकार दोबारा हासिल करने के लिए डब्ल्यूएसजी के साथ नया करार किया और इसके लिए 80 मिलियन डॉलर की फैसिलिटेशन फीस एमएसएम सिंगापुर द्वारा डब्ल्यूएसजी मारिशस को दी गई.

इस पूरी प्रक्रिया में 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लेनदेन हुआ, लेकिन यह पैसा किसके हाथों में पहुंचा, यह अब तक संदेह के घेरे में है. करार करते वक़्त केवल ललित मोदी ही मौजूद थे. लीग के किसी अन्य अधिकारी को सोनी के साथ बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन यह फेमा क़ानूनों का उल्लंघन है. मामला तूल पकड़ता है और कुणाल दासगुप्ता को अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है.

इसमें कोई संदेह नहीं कि सोनी ने फेमा क़ानूनों का उल्लंघन किया है. कंपनी के शीर्ष अधिकारी ललित मोदी के साथ परदे के पीछे करार कर जमकर मुनाफ़ा कमाते हैं और केवल तीन साल के अंदर सौ करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम जमा करने में कामयाब होते हैं.

वर्ष 2008 में होने वाले सीरियल धमाकों के बारे में विभिन्न राय पाई जाती हैं. कुछ लोग इन तमाम घटनाओं को हेडली की भारत यात्रा से जोड़कर देखते हैं.

बाटला हाउस मुठभेड़ कांड

पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है

फोटो– *प्रभात पाण्डेय*

अबू ज़फ़र आदिल आज़मी

बहुचर्चित बाटला हाउस प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं. लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार ने इस मामले की उच्चस्तरीय जांच आख़िर क्यों नहीं कराई?

बाटला हाउस मुठभेड़ कांड के डेढ़ वर्ष बीतने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सार्वजनिक होने से मुठभेड़ की न्यायिक जांच की मांग फिर से तेज़ हो गई है. मानवाधिकार के विभिन्न संगठनों और आम लोग इस मुठभेड़ पर लगातार प्रश्न उठाते रहे हैं और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उनके सवालों को अधिक गंभीर बना दिया है.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र अफरोज़ आलम साहिल ने इस तथाकथित मुठभेड़ से संबंधित विभिन्न दस्तावेज़ पाने के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत लगातार विभिन्न सरकारी एवं ग़ैर सरकारी कार्यालयों के दरवाज़े खटखटाए, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाने में उन्हें डेढ़ वर्ष लग गए. अफरोज़ आलम ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से उन दस्तावेज़ों की मांग की थी, जिनके आधार पर जुलाई 2009 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी. मालूम हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट देते हुए उसका यह तर्क मान लिया था कि उसने गोलियां अपने बचाव में चलाई थीं.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भेजे गए दस्तावेज़ों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस द्वारा आयोग एवं सरकार के समक्ष दाख़िल किए गए विभिन्न काग़ज़ातों के अलावा ख़ुद आयोग की अपनी रिपोर्ट भी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, आतिफ अमीन (24 वर्ष) की मौत तेज़ दर्द से हुई और मुहम्मद साजिद (17 वर्ष) की मौत सिर में गोली लगने के कारण हुई. जबकि इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की मृत्यु का कारण गोली से पेट में हुए घाव से ख़ून का ज़्यादा बहना बताया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, तीनों (आतिफ, साजिद एवं मोहन चंद्र शर्मा) को जो घाव लगे हैं, वे मृत्यु से पूर्व के हैं. रिपोर्ट के अनुसार, मोहम्मद आतिफ अमीन के शरीर पर 21 घाव हैं, जिनमें से 20 गोलियों के हैं. आतिफ को कुल 10 गोलियां लगीं और सारी गोलियां पीछे से मारी गईं. आठ गोलियां पीठ पर, एक दाईं बाजू पर पीछे से और एक बाईं जांघ पर नीचे से. 2X1 सेमी का एक घाव आतिफ के दाएं पैर के घुटनों पर है. यह घाव किसी धारदार चीज़ या रगड़ लगने से हुआ. इसके अलावा रिपोर्ट में आतिफ की पीठ और शरीर पर कई जगह छीलन है, जबकि जख्म नंबर 20 जो बाएं कूल्हे के पास है, से धातु का एक 3 सेमी का टुकड़ा मिला है.

मोहम्मद साजिद के शरीर पर कुल 14 घाव हैं. साजिद को कुल 5 गोलियां लगीं और उनसे 12 घाव हुए. इनमें से तीन गोलियां दाहिनी पेशानी के ऊपर, एक गोली पीठ पर बाईं ओर और एक गोली दाएं कंधे पर लगी. मोहम्मद साजिद को लगने वाली तमाम गोलियां नीचे की ओर निकली हैं, जैसे एक गोली जबड़े के नीचे से (ठोड़ी और गर्दन के बीच), सिर के पिछले हिस्से से और सीने से. साजिद के शरीर से धातु के दो टुकड़े मिलने का रिपोर्ट में उल्लेख है, जिसमें से एक का साइज़ 8X1 सेमी है, जबकि दूसरा पीठ पर लगे घाव (जीएसडब्ल्यू–7) से टीशर्ट से मिला है. इस घाव के पास 5X1.5 सेमी लंबा खाल छिलने का निशान है. पीठ पर बीच में लाल रंग की 4X2 सेमी की खराश है. इसके अलावा दाहिने पैर में सामने (घुटने से नीचे) की ओर 3.5X2 सेमी का गहरा घाव है. इन दोनों घावों के बारे में रिपोर्ट का कहना है कि ये घाव गोली के नहीं हैं. साजिद को लगे कुल 14 घावों में से सात को बहुत गहरा कहा गया है.

इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा के बारे में रिपोर्ट का कहना है कि बाएं कंधे से 10 सेमी नीचे घाव के बाहरी हिस्से की सफाई की गई थी. शर्मा को 19 सितंबर 2008 को एल–18 में घायल होने के बाद निकटतम अस्पताल होली फैमिली में भर्ती कराया गया था. उन्हें कंधे के अलावा पेट में भी गोली लगी थी. रिपोर्ट के अनुसार, पेट में गोली लगने से ख़ून ज़्यादा बह गया और यही मौत का कारण बना. मुठभेड़ के बाद यह प्रश्न उठाया गया था कि जब शर्मा को 10 मिनट के अंदर डॉक्टरी सहायता मिल गई थी और संवेदनशील जगह पर गोली भी नहीं लगी थी, तो फिर उनकी मौत कैसे हो गई? यह भी प्रश्न उठाया गया था कि शर्मा को गोली किस तरफ़ से लगी, आगे से या पीछे से? यह भी कहा जा रहा था कि शर्मा पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसकी व्याख्या नहीं कर पा रही है, क्योंकि होली फैमिली अस्पताल जहां उन्हें पहले लाया गया था और बाद में वहीं उनकी मौत भी हुई, में उनके घावों की सफाई की गई. लिहाज़ा पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर यह नहीं बता सके कि यह गोली के घुसने की जगह है या निकलने की. दूसरा कारण यह है कि शर्मा को एम्स में सफेद सूती कपड़े में ले जाया गया था और उनके घाव उसी से ढके हुए थे. रिपोर्ट में लिखा है कि जांच अधिकारी से निवेदन किया गया था कि वह शर्मा के कपड़े लैब में लाएं. मालूम हो कि शर्मा का पोस्टमार्टम 20 सितंबर 2008 को 12 बजे दिन में किया गया था और उसी समय यह रिपोर्ट भी तैयार की गई थी.

मोहम्मद आतिफ अमीन को लगभग सारी गोलियां पीछे से लगीं. आठ गोलियां पीठ में लगकर सीने से निकली हैं. एक गोली दाहिने हाथ पर पीछे से बाहर की ओर से लगी, जबकि एक गोली बाईं जांघ पर लगी. और, यह गोली हैरतअंगेज तौर पर ऊपर की ओर जाकर बाएं कूल्हे के पास निकली. पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में प्रकाशित समाचारों और उठाए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह तर्क दिया कि आतिफ गोलियां चलाते हुए भागने का प्रयास कर रहा था और उसे मालूम नहीं था कि फ्लैट में कुल कितने लोग हैं, इसलिए क्रॉस फायरिंग में उसे पीछे से गोलियां लगीं. लेकिन, मुठभेड़ या क्रॉस फायरिंग में कोई गोली जांघ में लगकर कूल्हे की ओर कैसे निकल सकती है. आतिफ के दाहिने पैर के घुटने में 1.5X1 सेमी का जो घाव है, उसके बारे में पुलिस का कहना है कि वह गोली चलाते हुए गिर गया था. पीठ में गोलियां लगने से घुटने के बल गिरना तो समझ में आ सकता है, किंतु विशेषज्ञ इस बात पर हैरान हैं कि फिर आतिफ की पीठ की खाल इतनी बुरी तरह कैसे उधड़ गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, आतिफ के दाहिने कूल्हे पर 6 से 7 सेमी के भीतर कई जगह रगड़ के निशान भी पाए गए.

साजिद के बारे में भी पुलिस का कहना है कि साजिद एक गोली लगने के बाद गिर गया था और वह क्रॉस फायरिंग के बीच आ गया. इस तर्क को गुमराह करने के अलावा और क्या कहा जा सकता है. साजिद को जहां गोलियां लगी हैं, उनमें से तीन पेशानी से नीचे की ओर आती हैं. जिसमें से एक गोली ठोड़ी और गर्दन के बीच जबड़े से भी निकली है. साजिद के दाहिने कंधे पर जो गोली मारी गई, वह बिल्कुल सीधे नीचे की ओर आई है. गोलियों के इन निशानों के बारे में पहले ही स्वतंत्र फोरेंसिक विशेषज्ञ का कहना था कि या तो साजिद को बैठने के लिए मजबूर किया गया या फिर गोली चलाने वाला ऊंचाई पर था. ज़ाहिर है, दूसरी सूरत उस फ्लैट में संभव नहीं है. दूसरे यह कि क्रॉस फायरिंग तो आमने–सामने होती है, न कि ऊपर से नीचे की ओर.

साजिद के पैर के घाव के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि यह किसी ग़ैर धारदार वस्तु से लगा है. पुलिस इसका कारण गोली लगने के बाद गिरना बता रही है, लेकिन 3.5X2 सेमी का गहरा घाव फर्श पर गिरने से कैसे आ सकता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस आरोप की पुष्टि होती है कि आतिफ एवं साजिद के साथ मारपीट की गई थी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशानुसार इस प्रकार के मामलों में पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ आयोग के कार्यालय भेजी जाए, लेकिन मोहन चंद्र शर्मा की रिपोर्ट में केवल यह लिखा है कि घावों की फोटो पर आधारित सीडी संबंधित जांच अधिकारी के सुपुर्द की गई. बाटला हाउस की घटना के बाद सरकार, कार्यपालिका और मीडिया ने जो भूमिका अदा की, वह न केवल आश्चर्यजनक है, बल्कि इससे देश के मुसलमानों एवं अन्य लोगों के मन में यह प्रश्न है कि आख़िर सरकार इस मामले की न्यायिक जांच से क्यों कतरा रही है? न्यायिक जांच के लिए जज भी सरकार ही नियुक्त करेगी.

वर्ष 2008 में होने वाले सीरियल धमाकों के बारे में विभिन्न राय पाई जाती हैं. कुछ लोग इन तमाम घटनाओं को हेडली की भारत यात्रा से जोड़कर देखते हैं. जबकि भारतीय जनता पार्टी की नेता सुषमा स्वराज ने अहमदाबाद धमाकों के बाद मीडिया से कहा था कि यह सब कांग्रेस करा रही है, क्योंकि न्युक्लियर समझौते के मुद्दे पर लोकसभा में नोट की गड्डियां पहुंचने से वह परेशान है और जनता के जेहन को मोड़ना चाहती है. समाजवादी पार्टी से निष्कासित सांसद अमर सिंह के अनुसार, सोनिया गांधी बाटला हाउस मामले की जांच कराना चाहती थीं, लेकिन किसी कारण वह ऐसा नहीं कर सकीं, पर उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया कि वह कारण क्या है?

बाटला हाउस मामले की न्यायिक जांच की मांग केंद्रीय सरकार के अलावा अदालत भी नकार चुकी है. सबका यही तर्क है कि इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा. केंद्रीय सरकार और अदालत जब इस तर्क द्वारा जांच की मांग ठुकरा रही थी, उसी समय देहरादून में रणवीर नामक युवक की मुठभेड़ में मौत की जांच हो रही थी और अंत में पुलिस का अपराध सिद्ध हुआ. आख़िर पुलिस का मनोबल रूपी यह कौन सा आधार है, जिसकी रक्षा के लिए न्याय और पारदर्शिता के नियमों को त्यागा जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... आईपीएल का असली खेल !... धीर

निष्पक्ष क़ानून की अवधारणा पर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था में आतंकवाद के इस नए रूप से निबटने के लिए स्पष्ट वैधानिक दिशानिर्देश पहली ज़रूरत है.

साइबर आतंकवाद का बढ़ता ख़तरा

जस्टिस राजेश टंडन

साइबर आतंकवाद का उदय हमारे लिए बेहद ख़तरनाक है. आतंकवाद के परंपरागत रूपों से अलग इसकी प्रकृति घातक और विध्वंसात्मक है. सूचना तकनीक के इस दौर में आतंकियों ने हथियारों के साथ तकनीक को जोड़ने की कला में महारत हासिल कर ली है. यदि समय रहते इस पर लगाम न कसी गई तो आगे चलकर यह और भी ख़तरनाक रूप अख्तियार कर सकता है.

साइबर आतंकवाद को परिभाषित करते हुए कई लोग इसकी बड़ी संकीर्ण व्याख्या करते हैं. अक्सर इसे आतंकी संगठनों की ऐसी कार्रवाइयों के साथ जोड़ा जाता है, जिनमें ख़तरा और दहशत पैदा करने के इरादे से सूचना तंत्र को दुष्प्रभावित करने की कोशिश की जाती है. लेकिन, इस सीमित व्याख्या से साइबर आतंकवाद की पहचान करना बेहद मुश्किल है. साइबर आतंकवाद को और सामान्य एवं विस्तृत तरीक़े से परिभाषित किया जा सकता है. जैसे किसी सामाजिक, धार्मिक, सैद्धांतिक, राजनीतिक या अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कंप्यूटर या कंप्यूटर तंत्र को बाधित करना या ऐसा करने की जानबूझ कर की गई कोशिश. इसका उद्देश्य लोगों को डराना-धमकाना या अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करना हो सकता है. साइबर आतंकवाद की यह विस्तृत व्याख्या टेक्नोलाइटिक्स इंस्टीट्यूट के केविन जी कोलमैन ने प्रस्तुत की थी, जबकि साइबर आतंकवाद शब्द का पहली बार इस्तेमाल जेरेड वेस्ट्रप ने किया था.

कंप्यूटरों को निशाना बनाने की हाल के दिनों में बढ़ी घटनाओं के मद्देनज़र अधिकांश लोगों की यही राय है कि हम आतंकवाद के एक नए एवं अनोखे चेहरे से मुक़ाबिल हैं और इससे निपटने के लिए हमें हर तरीक़े से तैयार हो जाना चाहिए. एक समाज के रूप में आतंकवाद से मुक़ाबला करने के लिए हमारे पास तमाम संसाधन मौजूद हैं. हमारे पास क़ानून का अनुभव है और श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी है, लेकिन क्या हम साइबर स्पेस में आतंकवाद से लोहा लेने के लिए तैयार हैं? किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई की रणनीति बनाते समय दुश्मन के लक्ष्यों, उसके काम करने के तरीक़े, संसाधनों और अंजाम देने वाले लोगों के बारे में जानकारी आवश्यक है. विधायिका और ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई शुरू करने से पहले दुश्मन की सही पहचान ज़रूरी है. यही वजह है कि आतंकवाद की परिभाषा में विस्तार कर साइबर आतंकवाद को इसके दायरे में लाना अनिवार्य हो गया है.

निष्पक्ष क़ानून की अवधारणा पर आधारित हमारी सामाजिक व्यवस्था में आतंकवाद के इस नए रूप से निबटने के लिए स्पष्ट वैधानिक दिशानिर्देश पहली ज़रूरत है. मौजूदा परिस्थितियों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे पास साइबर आतंकवाद की सही और स्पष्ट व्याख्या ही मौजूद नहीं है, जिसके चलते न्याय की उम्मीद भी नहीं की जा सकती. इस परिप्रेक्ष्य में साइबर आतंकवाद की अवधारणा को नए सिरे से समझने की आवश्यकता है. दो शब्दों, साइबर और आतंकवाद, से मिलकर बने साइबर आतंकवाद को अलग-अलग तरीक़ों से परिभाषित किया जा सकता है और यही इसकी स्पष्ट समझ में सबसे बड़ी बाधा है. साइबर शब्द हमारी व्यवसायिक गतिविधियों से जुड़ा कोई भी तरीक़ा हो सकता है, लेकिन आतंकवाद का चरित्र ही ऐसा है कि इसे परिभाषित करना आसान नहीं है. यहां तक कि अमेरिकी सरकार भी अब तक इसकी सर्वमान्य व्याख्या करने में नाकाम रही है. एक आदमी के लिए आतंकवादी दूसरे के लिए स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है, यह पुरानी कहावत अभी भी अपनी जगह पर क़ायम है. एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन में साइबर लॉ को कंप्यूटर और इंटरनेट के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया गया है. दूसरे शब्दों में कहें तो यह कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है. 2005 में प्रकाशित एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन के तीसरे संस्करण में साइबर चोरी (साइबर थेफ्ट) की ऑनलाइन कंप्यूटर सेवाओं के इस्तेमाल से जोड़कर व्याख्या की गई है. इस शब्दकोश में साइबर क़ानून को कुछ इस तरह परिभाषित किया गया है, क़ानून का वह क्षेत्र, जो कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सूचना तक निर्बाध पहुंच जैसी बातें इसके दायरे में आती हैं. परिभाषा की अनेकता के चलते ही साइबर आतंकवाद से निबटने के तरीक़ों में भी अनेकता नज़र आती है. जैसा कि डी डेनिंग ने एक्टिविज़्म, हैक्टिविज़्म और साइबर टेररिज़्म में लिखा है, ईमेल बम को कुछ लोग हैक्टिविज़्म समझते हैं तो अन्य लोग इसे साइबर आतंकवाद समझ सकते हैं.

मीडिया, व्यक्तिगत अनुभव या अन्य उपलब्ध स्रोतों से साइबर आतंकवाद के बारे में कुछ समझदारी विकसित ज़रूर हुई है, लेकिन असल समस्या यह है कि विशेषज्ञों की जमात इसे अपने-अपने नज़रिए से परिभाषित करती है. साइबर टेररिज़्म, बायोटेररिज़्म या केमिकल टेररिज़्म जैसी अवधारणाओं के साथ समस्या यह है कि इन्हें अक्सर टेररिज़्म के पहले लगे शब्द के अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है. कैलिफोर्निया स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्युरिटी एंड इंटेलिजेंस में सीनियर रिसर्च फेलो बैरी कोलिन, जिन्हें 1997 में पहली बार साइबर टेररिज़्म शब्द के इस्तेमाल का श्रेय हासिल है, ने इसे साइबरनेटिक्स और टेररिज़्म का मिश्रण बताया था. एफबीआई से जुड़े मार्क पॉलिट ने भी इसी साल इसकी एक सामान्य परिभाषा दी थी, साइबर आतंकवाद राजनीतिक पूर्वाग्रह के शिकार लोगों द्वारा जानबूझ कर सूचना, कंप्यूटर तंत्र, कंप्यूटर प्रोग्रामों या आंकड़ों को बाधित करने का प्रयास है और इसके निशाने पर ऐसा लक्ष्य होता है, जिसके पास हथियार नहीं होते. तबसे ही साइबर आतंकवाद आईटी विशेषज्ञों, आतंकवाद विशेषज्ञों और मीडिया के शब्दकोश का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है. ऐसे ही एक विशेषज्ञ, जो पुलिस अधिकारी हैं, ने इसे अपने तरीक़े से परिभाषित किया है, साइबर आतंकवाद, बाधाएं खड़ी करने के प्रयास एवं कंप्यूटर के माध्यम से लक्ष्य पर निशाना, कंप्यूटर पर अधिकाधिक रूप से निर्भर होते जा रहे समाज के अस्तित्व के लिए बेहद ख़तरनाक है. मीडिया जगत में साइबर आतंकवाद शब्द के इस्तेमाल में काफी लचीला रुख़ अपनाया जाता है. एक कनाडाई लड़के ने अपने परिवार के साइबर टेररिज़्म की बात कबूली. एमेरीविले (रायटर). एक 15 वर्षीय कनाडाई लड़के ने स्वीकार किया है कि नई तकनीकों की मदद से अपने परिवार के लोगों को महीनों तक डराने-धमकाने के लिए वह स्वयं ज़िम्मेदार था. साइबर आतंकवाद को परिभाषित करते हुए डोरोथी डेनिंग ने कहा है, निहित राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी देश की सरकार या वहां के नागरिकों को डराने या प्रताड़ित करने के लिए कंप्यूटर संसाधन या उसके नेटवर्क एवं उसमें संरक्षित आंकड़ों को अनाधिकार चोट पहुंचाने की कोशिश साइबर आतंकवाद के दायरे में आती है. एसएमएस विश्वविद्यालय के आर स्टार्क के मुताबिक़, सूचना तंत्र पर किसी भी तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश साइबर आतंकवाद कहलाती है, चाहे वह किसी भी माध्यम से की गई हो. उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि दूरभाष क्षेत्र की आधारभूत संरचना को चोट पहुंचाने की कोई भी कोशिश, जिसमें वेबसाइट और कंप्यूटर की मदद से की गई कोई भी छेड़छाड़ शामिल है, साइबर आतंकवाद के दायरे में आती हैं. इसका मतलब है कि साइबर आतंकवाद हमारे लिए एक ख़तरा बन चुका है और हम हर पल इसके ख़ौफ़ में जी रहे हैं. साइबर आतंकवाद का उदय हमारे लिए बेहद ख़तरनाक है. आतंकवाद के परंपरागत रूपों से अलग इसकी प्रकृति घातक और विध्वंसात्मक है. सूचना तकनीक के इस दौर में आतंकियों ने हथियारों के साथ तकनीक को जोड़ने की कला में महारत हासिल कर ली है. यदि समय रहते इस पर लगाम न कसी गई तो आगे चलकर यह और भी ख़तरनाक रूप अख्तियार कर सकता है. इससे होने वाले विध्वंस की कोई भरपाई नहीं की जा सकती. सच तो यह है कि साइबर आतंकवाद के रूप में हम आतंकवाद के सबसे घिनौने स्वरूप से रूबरू हैं. साइबर आतंकवाद की अवधारणा में ही सूचना तकनीक का ऐसा इस्तेमाल निहित है, जिसका उद्देश्य चल-अचल संपत्तियों को नष्ट करना है.

उदाहरण के लिए कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करके उसमें संग्रहीत आंकड़ों को चुराना और फिर अपने व्यवसायिक प्रतिद्वंद्वियों के ख़िलाफ़ उसका इस्तेमाल साइबर आतंकवाद का एक अहम पहलू है. दरअसल, साइबर आतंकवाद का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि किसी एक परिभाषा में इसके सभी पहलुओं को शामिल नहीं किया जा सकता. साइबर स्पेस ऐसा क्षेत्र है, जिसमें रोज़ नई-नई तकनीकों का विकास हो रहा है और यह देखते हुए इसे किसी पूर्व निर्धारित परिभाषा के दायरे में सीमित करना उचित भी नहीं है. साइबर आतंकवाद से निबटने के लिए बने क़ानून भी पर्याप्त नहीं हैं और आतंकियों के ख़तरनाक इरादों एवं वैश्विक स्तर पर तकनीक के लगातार विकास के चलते इसमें लगातार बदलाव की ज़रूरत है. इस समस्या को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल साइबर आतंकवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसकी कोई सीमा नहीं होती. ऐसा हो सकता है कि आतंकी किसी ऐसे देश में बैठकर किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करें, जिसके साथ उसके कोई विशेष राजनयिक संबंध न हों. ऐसी परिस्थिति में तकनीक का इस्तेमाल ही एकमात्र विकल्प हो सकता है. आधुनिकतम सुरक्षा तकनीकों के साथ जोड़कर साइबर क़ानूनों का निर्माण करना समय की ज़रूरत बन चुका है.

इंटरनेट संचार, सूचना और व्यवसाय का एक वैश्विक माध्यम है. इसकी प्रकृति ही ऐसी है कि आर्थिक और वित्तीय घोटाले, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ एवं ब्लॉग आदि पर द्वेषपूर्ण विचारों का प्रकाशन काफी आम है. क्रेडिट कार्डों के नंबर और पासवर्ड की चोरी जैसी वारदातों की बढ़ती संख्या इसका एक उदाहरण है. आर्थिक क्षेत्र में फ़र्ज़ीवाड़ों को साइबर आतंकवाद के दायरे में रखा जा सकता है और इसमें शामिल आरोपियों को क़ानून के तहत आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. लेकिन एक ओर धारा 66-एफ का विस्तार कर वित्तीय फ़र्ज़ीवाड़ों को आतंकवाद के दायरे में लाने की कोशिश और दूसरी ओर सामान्य आतंकी वारदातों के लिए बने पीटीए एवं टाडा जैसे क़ानूनों को ख़त्म करना ख़ुद में एक विरोधाभास है. कंप्यूटर और इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर अपराधों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है. चिंता की बात तो यह है कि इसकी प्रकृति लगातार बदलती रहती है. क्रेडिट कार्ड के फ़र्ज़ीवाड़े और आवश्यक सेवाओं को बाधित करने के नए तरीक़े आदि इसी के उदाहरण हैं. ईमेल के माध्यम से ब्लैकमेलिंग एवं मानहानि की कोशिश आदि साइबर अपराध के परंपरागत तरीक़े हैं. हाल के दिनों में निजी एवं सरकारी संस्थान, बैंक और आम नागरिक भी अपराध के नए-नए तरीक़ों-जैसे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़, आंकड़े एवं बैंक खातों के पासवर्ड चोरी होना, द्वेषपूर्ण एवं मानहानि वाले ईमेल, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक खातों से राशि निकाल लेना आदि वारदातों के शिकार हुए हैं.

(लेखक साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन हैं)

feedback@chauthiduniya.com

थरूर की बदक़िस्मती यह थी कि उनका प्रतिद्वंद्वी ऐसा निकला, जो आईपीएल के रणक्षेत्र में आधी रात के बाद भी ट्विटर के हथियार से उन्हें चुनौती दे सके.

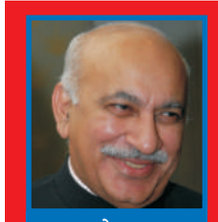

एम जे अकबर

हैलो शशि मोदी, ललित थरूर से मिलिए

शशि थरूर के करियर पर नज़र डालें तो इसमें विरोधाभासों की कोई कमी नहीं है. चार साल पहले थरूर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए मनमोहन सिंह के चुने हुए उम्मीदवार थे. कूटनीति के क्षेत्र में दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले इस पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को लेकर विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को मना किया था, क्योंकि थरूर के जीतने की संभावना नहीं के बराबर थी, फिर भी मनमोहन अपने फ़ैसले पर क़ायम रहे. लेकिन पिछले साल जब प्रधानमंत्री इस हालत में थे कि वह थरूर को कोई पद दे सकें तो उन्होंने राज्यमंत्री पद के लिए उन्हें चुना. एक ऐसा ओहदा, जिसे कैबिनेट स्तर के मंत्री की छत्रछाया में काम करना होता है और सच तो यह है कि उसके पास करने के लिए कुछ ख़ास होता ही नहीं है.

अब हम जैसा कि जान चुके हैं, 2009 में मनमोहन सिंह का यह फ़ैसला बिल्कुल सही था, लेकिन थरूर की असलियत को जानने वाले पहले इंसान थे प्रधानमंत्री के निजी मित्र एवं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश. साल 2006 के दौरान जब इन दोनों राजनेताओं की मित्रता भारत–अमेरिका संबंधों में नई गर्माहट भर रही थी, वाशिंगटन ने कूटनीति के मामलों में थरूर को अपरिपक्व करार दिया था. थरूर लाख दावे करें, लेकिन सच्चाई यही है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने ऊंचे ओहदे और अच्छे वेतन वाली नौकरी को इसलिए नहीं छोड़ा था कि वह देश की राजनीति के लिए कोई अहसान करना चाहते थे. उनकी असली मंशा तो विश्व की शीर्ष संस्था के शीर्षतम पद पर पहुंचना था.

ख़ैर, ज़्यादा मौजूं सवाल यह है कि थरूर दिल्ली आकर पदावनति के लिए राजी कैसे हुए. वह ऐसे इंसान तो नहीं दिखते, जो आसानी से झुक जाए. इसका कोई न कोई कारण तो ज़रूर रहा होगा. सच तो यह है कि थरूर काम से ज़्यादा प्रचार, ख़बरों में बने रहने और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं. कुछ नहीं से थोड़ा–बहुत ही सही. राजनीतिज्ञों की जमात की ख़ासियत है कि वह लगातार ख़बरों में बनी रहना चाहती है. अंतर सिर्फ़ इसके पैमाने का होता है. बड़ा फ़र्क़ तब आता है, जब वे ख़बर में अपनी जगह तलाशने लगते हैं, बजाय इसके कि ख़बर उन्हें तलाश करे.

इसमें कोई शक़ नहीं कि आईपीएल पार्टियों के शौक़ीन लोगों के दिमाग़ की उपज है, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में निजी स्तर पर इससे बड़ी पार्टी का आयोजन नहीं हुआ. इसमें प्रवेश पाने वाले लोगों की संख्या सीमित है, लेकिन जिन्हें प्रवेश मिल जाता है, उन्हें मानो लॉटरी का टिकट मिल जाता है. जैसा कि लॉटरी में होता है, पैसा जनता का लगता है, लेकिन ईनाम कुछ गिने–चुने लोगों को ही मिलता है. आईपीएल के मामले में ऐसे लोगों की संख्या और भी कम है और उनके नाम

पहले से ही तय हैं. इस पार्टी में हर मेहमान की हैसियत एक जैसी नहीं होती, लेकिन सभी ख़ुश हैं.

पैसों के लेनदेन के कई तरीक़े होते हैं, मसलन असाधारण वेतन और हम केवल उस पैसे की बात नहीं कर रहे, जो खिलाड़ियों को मिलता है. सबसे ज़्यादा फ़ायदे की हालत में होते हैं फ्रेंचाइज़ी एवं प्रमोटर्स और उनके गिने–चुने लोग, जिन्हें दोहरा लाभ मिलता है. एक तो उन्हें टीमों के बहाने अपने उत्पादों को प्रचारित करने का मौक़ा मिलता है और दूसरा उनकी कंपनियों के शेयरों के दामों में उम्मीद से भी ज़्यादा वृद्धि होती है. वैसे भी, सीधे रास्ते से चलें तो बिजनेस के इस मॉडल में इतनी जल्दी मुनाफे की उम्मीद नहीं की जा सकती. कोच्चि टीम के फ्रेंचाइज़ी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि भविष्य के फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए अभी उन्हें हर साल सौ करोड़ का घाटा सहना होगा. टीम के मालिकों के नाम गुप्त रखे गए हैं, ताकि मुनाफे को उनके खातों में स्थानांतरित किया जा सके, जबकि पैसा लगाने के लिए कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है.

थरूर कुछ तो अपनी करनी और कुछ बदक़िस्मती की मार झेल रहे हैं. उनकी ग़लती यह थी कि वह पार्टी में बिना बुलाए ही घुस आए. उन्होंने सोचा कि दुबई और गुजरात के पैसों से वह प्रवेश का अधिकार ख़रीद लेंगे और कोच्चि के साथ जुड़कर राजनीतिक फ़ायदा उठाने में कामयाब होंगे. कोच्चि को टीम फ्रेंचाइज़ी मिलते ही इसका राजनीतिक श्रेय लेने में उन्होंने थोड़ी भी देर नहीं लगाई. उन पर आरोप है कि आर्थिक फ़ायदे हासिल करने के लिए उन्होंने छुपा हुआ रास्ता चुना. उनकी मित्र सुनंदा पुष्कर का यह दावा कि वह थरूर की प्रतिनिधि मात्र नहीं हैं, में वजन नहीं दिखता. दुबई की किसी साधारण कंपनी में एक्ज़ीक्यूटिव का काम करने वाले किसी इंसान को शुरुआत में ही 70 करोड़ रुपये की क़ीमत वाले स्वेट इक्विटी जीवन भर के लिए वैसे ही नहीं मिल जाते. 1981 में ए आर अंतुले की मुख्यमंत्री पद से विदाई के बाद अब तक ऐसा मामला देखने को नहीं मिला. क़रीब 30 साल पहले कांग्रेस ने बेवजह उन्हें बचाने की कोशिश की, जबकि उनके बचाव के पक्ष में कोई भी तर्क नहीं था. बाद में जब उसे अंतुले को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तो अंतुले का राजनीतिक जीवन ही अवसान के रास्ते पर आगे बढ़ने को मजबूर हो गया. आज फिर वैसे ही हालात पैदा हो गए हैं.

थरूर की बदक़िस्मती यह थी कि उनका प्रतिद्वंद्वी ऐसा निकला, जो आईपीएल के रणक्षेत्र में आधी रात के बाद भी ट्विटर के हथियार से उन्हें चुनौती दे सके. अच्छे कपड़ों, वाकपटुता और टेलीविज़न पर दिखते रहने की चाहत के अलावा भी कई ऐसी चीजें हैं, जिनमें मोदी और थरूर के बीच समानताएं हैं. थरूर प्रकरण ऐसे समय में उभरा है, जबकि कांग्रेस विवादों को न्योता देने का ख़तरा मोल नहीं ले सकती. थरूर सोनिया गांधी–मनमोहन सिंह सरकार के पहले ऐसे मंत्री भी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है.

अब उन्होंने श्रीमती गांधी और डॉ. सिंह को अजब उलझन में फंसा दिया है–सीधी रेखाओं के बीच स्पेगैटी के लिए जगह बने तो कैसे.

feedback@chauthiduniya.com

मियो समुदाय और तबलीगी जमात

योगी सिकंद

भौगोलिक विस्तार और कार्यकर्ताओं की संख्या के नज़रिए से तबलीगी जमात (टीजे) आज की तारीख़ में दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक आंदोलन है. तबलीगी जमात के ऐतिहासिक अध्ययन के लिए ज़रूरी है कि हम पहले उन लोगों के बारे में जानें, जहां इसका सबसे पहले प्रसार हुआ. देश के सुदूर उत्तर–पश्चिम में स्थित मेवात इलाक़े के मियो किसान, टीजे की अनोखी कार्य प्रणाली, ख़ासकर तबलिग या इस्लामिक मिशनरी कार्य और इस्लामीकरण के प्रति इसका रवैया एवं समझ काफी हद तक 20वीं शताब्दी में मेवात इलाक़े के सामाजिक परिदृश्य पर आधारित है. मेवात का यह इलाक़ा बदलते सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्य का एक रोचक उदाहरण भी पेश करता है, जहां स्थानीय स्तर पर टीजे अपनी जड़ें गहरी करने में कामयाब रहा है.

मेवात में तबलीगी जमात के शुरुआती विकास पर ख़ासतौर से ध्यान देने की ज़रूरत है. तबलीग की दुनिया में मेवात को इस आंदोलन की सबसे सफल प्रायोगिक ज़मीन (इस्साक 1972:4) के रूप में देखा जाता है, लेकिन समाजशास्त्रीय रूप से यह एक विरोधाभास है, जिसका हल शायद ही निकल पाए. मुस्लिम उलेमाओं द्वारा पारंपरिक तौर पर मियो समुदाय को ऐसी जमात के रूप में देखा जाता था, जिनकी इस्लाम के प्रति आस्था उतनी गहरी नहीं थी. तीन दशकों के तबलीगी प्रयासों के बाद इसमें काफी बदलाव आ चुका है. कम से कम ताज़ा जानकारियां तो यही कहती हैं और कई उलेमाओं का भी कहना है कि इस्लामिक सिद्धांतों के प्रति उनके नज़रिए में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं. (फलाही 1996:301) इस आलेख में हम इसी विरोधाभास पर नज़र डालेंगे. मेवात क्षेत्र में सामाजिक बदलावों के बीच तालिबानी जमात के शुरुआती दिनों, इन बदलावों के परिप्रेक्ष्य में टीजे की बदलती सामाजिक भूमिका एवं उन्नीसवीं शताब्दी से लेकर अब तक मेवात के सामाजिक परिदृश्य में आए बदलावों पर एक विस्तृत चर्चा होगी.

पृष्ठभूमि

दिल्ली से क़रीब 65 मिलोमीटर दूर दक्षिण–पश्चिम में स्थित सोहना के दक्षिण में मौजूद हरियाणा राज्य के गुड़गांव एवं फरीदाबाद ज़िलों के अधिकांश हिस्सों में फैला मेवात मियो किसानों का क्षेत्र है. पहले यह क्षेत्र अलवर और भरतपुर रियासतों का हिस्सा हुआ करता था. मियो मुस्लिम धर्मावलंबी समुदाय है और इसने अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को काफी सहेज कर रखा है. 1983 के एक आंकड़े के मुताबिक़, इनकी कुल जनसंख्या क़रीब आठ लाख थी, जिनमें लगभग एक चौथाई मौजूदा पाकिस्तान में रहते हैं, जबकि बाक़ी भारत में. (शम्स 1983:17)

मियो लोगों का एक बड़ा हिस्सा हिंदुओं की राजपूत या क्षत्रिय जाति से संबंधित होने का दावा करता है. यह संभव हो भी सकता है कि कुछ लोग इस समुदाय से जुड़े हों, लेकिन ज़्यादा संभावना यही लगती है कि अधिकांश मियो छोटी जातियों से धर्मांतरित हुए और इस्लामीकरण की इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने अपनी सामाजिक हैसियत बढ़ाने के लिए राजपूतों से अपने संबंध के दावे किए. (हैरिस 1901:23, चेनिंग 1882:28) उनके कई देवताओं के नाम इस इलाक़े में रहने वाले हिंदुओं की छोटी जातियों–जैसे मीणा, जाट और गुर्जर से मिलते–जुलते हैं, जो इसी तथ्य की ओर इशारा करते हैं. ऐसा लगता है कि मियो लोगों का जुड़ाव राजपूतों के अलावा कई अन्य जातियों से भी था.(अग्रवाल 1978:338)

यह अंदाज़ा लगाना काफी मुश्किल है कि मेवात इलाक़े में इस्लाम अपनी जड़ें जमाने में कैसे कामयाब हुआ. दिल्ली से सटे इलाक़ों में रहते हुए मियो बारहवीं शताब्दी के बाद मुस्लिम राजाओं के ख़िलाफ़ लगातार लड़ते रहे. सूखे और महामारियों से परेशान मियो अक्सर लूटपाट के इरादे से दिल्ली की ओर रुख़ करते थे और इसके चलते उन्हें सल्तनत के कहर का शिकार होना पड़ता था. शाही सेना से पराजित होने के बाद अक्सर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने को मजबूर होना पड़ता था. मेवात दिल्ली के मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में आया तो सूफियों के अलग–अलग संप्रदाय भी इस इलाक़े में सक्रिय हुए. इसका नतीजा मियो समुदाय के क्रमिक इस्लामीकरण के रूप में सामने आया. उन्होंने इस्लामिक रीति–रिवाजों को अपनाया, लेकिन अपनी पुरानी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं से भी पूरी तरह दूर नहीं हुए. समय–समय पर उलेमाओं और सूफियों ने इन हिंदूवादी परंपराओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई. उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में वलीउल्लाही संप्रदाय के कई उलेमाओं ने इसे बदलने के प्रयास किए, लेकिन उनका प्रभाव अपने अनुयायियों के छोटे समूह तक ही सीमित रहा. ऐसा लगता है कि मियो समुदाय लोकप्रिय धार्मिक परंपराओं को छोड़ शरीयत आधारित इस्लामिक परंपराओं को अपनाने के लिए अब तक पूरी तरह तैयार नहीं था. सूफी संतों के प्रभाव और राजनीतिक बाध्यताओं के चलते मियो समुदाय का इस्लामीकरण ज़रूर हुआ, लेकिन यह आंशिक ही रहा. उन्नीसवीं शताब्दी के आख़िरी दिनों में अलवर रियासत के सेटलमेंट अफसर रहे मेजर पॉलेट इसकी चर्चा करते हुए लिखते हैं, मियो लोग नाम के लिए तो मुसलमान बन चुके हैं, लेकिन वे अभी भी हिंदू देवी–देवताओं को मानते हैं और हिंदुओं के पर्व–त्योहारों को भी मनाते हैं. होली का पर्व उनके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना ईद, शबेबारात या मुहर्रम. वे जन्माष्टमी, दशहरा और दीवाली जैसे त्योहार भी उत्साहपूर्वक मनाते हैं. शादी की तारीख़ें तय करने के लिए ब्राह्मणों–पंडितों की मदद लेते हैं. उनके नाम भी हिंदुओं जैसे हैं और अक्सर नाम के साथ वे सिंह उपनाम जोड़ते हैं. हिंदू अहीर और गुर्जरों की तरह वे हर महीने की अमावस्या को शारीरिक श्रम नहीं करते और नया कुआं खोदने पर हनुमान जी का एक छोटा मंदिर बनाना नहीं भूलते. सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से मियो अभी भी आधे हिंदू हैं. उनके गांवों में मस्जिद नज़र नहीं आती और हिंदुओं के पूजास्थल ही उनके भी पूजास्थल हैं–जैसे पंचपीरा, भैया और चहुंद. (पॉलेट 1878:38)

अपनी पोशाक में भी मियो मेवात इलाक़े की अन्य कृषक जातियों से अलग नहीं थे. मियो महिलाएं परंपरागत राजस्थानी घाघरा–चोली के साथ चांदी के भारी–भरकम जेवरात पहनती थीं और पुरुष धोती पहनते थे. हिंदुओं की तरह अधिकांश मियो पुरुष चुटिया भी रखते थे. मियो समुदाय में इस्लामी परंपराएं पुरुषों के खतना, निकाह और मृतकों को ज़मीन के नीचे दफन करने तक ही सीमित थीं. हालांकि इस पर भी हिंदुओं का असर स्पष्ट नज़र आता था. (अग्रवाल:339) मियो समुदाय का एक बड़ा तबका इस्लामिक परंपराओं से पूरी तरह अनभिज्ञ था. पॉलेट लिखते हैं, मियो अपनी धार्मिक परंपराओं में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते. कुछ ही लोग कलीमा या नियमित नमाज के बारे में जानते हैं.

एक अन्य लेखक ने कहा है कि कुरान के मुक़ाबले रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथ ज़्यादा लोकप्रिय थे. हिंदू पूजास्थलों की संख्या भी मस्जिदों से ज़्यादा थी. इस्लामी परंपराओं के विपरीत मियो नमाज से ज़्यादा हिंदुओं की तरह मंदिरों में जाकर पूजा करते थे. (अग्रवाल : 339) प्रचलित धार्मिक परंपराओं के साथ जुड़े रहना मियो समुदाय के लिए फ़ायदे का सौदा था. मेवात क्षेत्र में इनकी अच्छी–खासी आबादी थी और अधिकांश ज़मीन पर खेती भी वही करते थे. छोटी जातियों के साथ छुआछूत और अन्य ग़ैर इस्लामी परंपराओं को मानते रहने का परिणाम यह हुआ कि इस्लामीकरण के बावजूद स्थानीय सामाजिक परिदृश्य में उनकी हैसियत अच्छी बनी रही. फ़सलों में हिस्सेदारी के लोभ में ब्राह्मणों सहित अन्य ग़ैर मुस्लिम जातियां मियो लोगों के साथ जुड़ी रहीं. एक मियो विद्वान के मुताबिक़, मियो अपनी संदेहास्पद धार्मिक पहचान को लेकर फ़िक्रमंद नहीं थे, क्योंकि मेवात इलाक़े में उनकी सामाजिक हैसियत सुरक्षित थी. अन्य जातियां उनकी इस हैसियत पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहती थीं.(शम्स:35)

इसके विपरीत दिल्ली के मुस्लिम शासकों के साथ मियो समुदाय लगातार संघर्ष करता रहा. इस समुदाय की धार्मिक भावनाएं हिंदुओं के ज़्यादा क़रीब थीं और यह पहचान उन्हें मुस्लिम शासकों के ख़िलाफ़ खड़ी करती थी. रोचक तथ्य यह है कि मेवाती सामंतों का वर्ग जिसे खानजादा के नाम से जाना जाता था, इस्लामिक भावनाओं के प्रति ज़्यादा प्रतिबद्ध था. वे अपनी महिलाओं को पूरी तरह परदे में रखते थे. मेवात के इतिहास में खानजादा और मियो के बीच ख़ूनी संघर्षों के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं और कोई आश्चर्य नहीं कि बीसवीं शताब्दी के शुरुआती दिनों तक, जबकि खानजादा वर्ग का प्रभाव कम होने लगा था, मियो उनकी धार्मिक परंपराओं की ओर ज़्यादा आकर्षित नहीं हुए. वास्तविकता तो यह है कि मियो सामंतों के इस वर्ग को अपने दुश्मन के रूप में देखते थे.

मियो समुदाय की प्रचलित धार्मिक परंपराओं को उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक कोई ख़ास चुनौती नहीं मिली, लेकिन इसके बाद मेवात इलाक़े में आए सामाजिक बदलावों से इनकी धार्मिक पहचान प्रभावित होने लगी. बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में इस इलाक़े में सामाजिक परिवर्तन का ऐसा दौर आया कि उसने एक सामाजिक समस्या का रूप अख्तियार कर लिया. और, मियो समुदाय के बीच तबलीगी जमात के उदय की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होने लगी.

feedback@chauthiduniya.com

धर्म का व्यापार बंद हो

आज धर्म एक व्यापार का रूप ले चुका है. धर्म अय्याशी, नशा, धनार्जन एवं अपराध का माध्यम बन गया है और सत्ता–संपत्ति हासिल करने का भी. सभी धर्मगुरु अचानक अरबपति कैसे हो गए? यह एक विचारणीय प्रश्न है. पत्रकार बंधु धर्म के नाम पर हो रहे अधर्म को दुनिया के सामने लाएं.

–रजत कुमार, *बरेली, उत्तर प्रदेश.*

एक पत्थर तो तबियत से...

12–18 अप्रैल के अंक की कवर स्टोरी–प्रधानमंत्री पद की दौड़ में बाबा रामदेव खोजपूर्ण है और किसी जासूसी कहानी से कम नहीं. आपने तथ्यों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि बाबा रामदेव या उनके सहयोगी राजनीति की शतरंजी चालों में माहिर हो गए हैं और जो चाहें कर सकते हैं. संपादकीय–अमिताभ को अपमानित मत करो सच्ची पत्रकारिता का एक आईना है. पत्रकारिता से संबंध रखने वाले सभी बंधुओं से मेरा आग्रह है कि इस आईने में झांकें और देखें कि वे किसी के लिए क्या कर रहे हैं. इस आलेख के कुछ तथ्य दिल को छू जाने वाले हैं. मैं आपके विचारों से इत्तेफाक रखता हूं, आपके जज्बे की तारीफ करता हूं और हृदय से धन्यवाद देता हूं. आसमां में सुराख हो सकता है, सिर्फ एक पत्थर तबियत से उछालने की जरूरत है.

–रामदास धुसिया, *अधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश.*

शिक्षा का अधिकार

चौथी दुनिया के 8–14 मार्च के अंक में प्रकाशित शिक्षा का अधिकार विषयक लेख यद्यपि मैं पढ़ तो नहीं सका, लेकिन उसके बाद के अंक में प्रकाशित राजेश वर्मा–पटना और प्रीति लखेड़ा–साहिबाबाद के विचारों–सुझावों से इत्तेफाक रखता हूं. वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन जरूरी हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत एवं अंग्रेजी निहायत जरूरी और नियमित विषय हैं, ठीक वैसे ही उर्दू को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए. इससे दो फायदे हैं. पहला तो यह कि एक बहुत अच्छी तहजीब की भाषा हमारे मुल्क को मिलेगी और दूसरा यह कि इस भाषा को अपनाने वाले अपनापन महसूस करेंगे.

–विष्णु प्रसाद शर्मा, *दुर्ग, छत्तीसगढ़.*

कलई खोल दी

19–25 अप्रैल के अंक में प्रकाशित आवरण कथा–मेरे ख़िलाफ़ लिखना मना है ने बिहार सरकार की कलई खोलकर रख दी है. जो काम यहां चार सालों से कोई नहीं कर पाया, वह चौथी दुनिया ने कर दिखाया. इसके पहले भी चौथी दुनिया में रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पर छपे लेख को लेकर संसद में हंगामा हो चुका है. चौथी दुनिया वाकई एक लाजवाब अख़बार है.

–सुनील कुमार सिंह, *पटना, बिहार.*

सर्कस

लोकतंत्र के सर्कस में
आजकल/बड़े
अजीब-अजीब से
खेल दिखाए जाते हैं,
नोट, वोट और लट्ठ के जोर पर
जनता रूपी/ खूंखार सिंहों की पीठ पर
बगुला भगत, मरियल-सड़ियल
मेमने बैठाए जाते हैं.
संविधान का रिंग मास्टर
बहुत हैरान है,
सिंहों से ज़्यादा/ मेमनों से परेशान है.

–हलीम आईना, *कोटा, राजस्थान.*

पत्रकारिता का मतलब

19–25 अप्रैल की कवर स्टोरी–मेरे ख़िलाफ़ लिखना मना है, लाजवाब है. वाकई पत्रकारिता किसी सरकार की मर्ज़ी से नहीं, सच के लिए होनी चाहिए और आम लोगों के हित में. आपके साहस की प्रशंसा करता हूं.

–विकास जैन, *दरभंगा, बिहार.*

ख़बर देने का अंदाज़

चौथी दुनिया का ख़बरें देने का अंदाज़ काफी बेहतर है. वास्तव में सच कभी नहीं हारता और झूठ के लिए कहीं कोई जगह नहीं है. मेरी तरफ़ से आपको बहुत बधाई. निश्चित रूप से यह अख़बार एक दिन जनसामान्य में अपनी जगह बनाने में सफल होगा.

–गगन विश्वकर्मा, *अलीगढ़, उत्तर प्रदेश.*

मुंबई में प्रसार बढ़े

चौथी दुनिया मुंबई में किसी स्टॉल पर सहज उपलब्ध नहीं है. पूछने पर अक्सर कह दिया जाता है कि इस नाम का कोई अख़बार नहीं आता. मुंबई में इसका प्रसार बढ़ाएं. आपके अख़बार का अंदाज बिंदास है. यह एक नया पाठक वर्ग तैयार कर सकता है.

–दिनेश सिंह, *वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र.*

सब कुछ फिक्स्ड

5–11 अप्रैल के अंक की आवरण कथा–सब कुछ फिक्स्ड है, वास्तव में चिंता पैदा करने वाली है. वैसे तो पैसे का खेल पैसे से शुरू होता है, जनसाधारण क्यों चिंता करे? लेकिन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं. सरकार की ज़िम्मेदारी है प्रजा के सुख की चिंता करना. अगर करोड़ों रुपया मुट्ठी भर लोगों में ही बंट जाए और सरकार चुपचाप देखती रहे तो यह सरासर प्रजातंत्र का अपमान है. हां, कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि क्रिकेट अमीरों का खेल है. अमीर खेलें, पैसा कमाएं और पैसा लुटाएं, ग़रीबों को इससे क्या लेना–देना.

–नवीन कुमार शर्मा, *हुगली, पश्चिम बंगाल.*

आईपीएल खेल नहीं, व्यवसाय

भारतीय क्रिकेट में तहलका मचाने वाला आईपीएल क्रिकेट खेल नहीं, बल्कि एक व्यापार है. इससे जुड़े अधिकारियों, खिलाड़ियों, नेताओं एवं अभिनेताओं को सिर्फ़ पैसा कमाने से मतलब है, उन्हें खेल से कुछ लेना–देना नहीं है. आईपीएल सिर्फ़ तमाशा बनकर रह गया है. लेख में बिल्कुल सही जानकारी दी गई है कि इन मैचों का संचालन सट्टेबाज़ों द्वारा लंदन, हांगकांग एवं शारजाह जैसे शहरों से होता है. अब तो इन मैचों के दौरान लड़कियों का भी प्रदर्शन होता है. सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन खेल से जुड़े लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सभी लोग इस मेले में शामिल हैं.

–शंकर शर्मा, *बेगूसराय, बिहार.*

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इसी पते पर भेजें.
संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

30वें अहले हदीस सम्मेलन के समापन पर धार्मिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित 30 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए.

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

मुंबई में पाकिस्तानी मंत्री

सत्रह अप्रैल की शाम छह बजे हैदराबाद से मुंबई आने वाली फ्लाइट डॉ. फिरदौस आशिक अवान को लेकर मुंबई आई. डॉ. फिरदौस हैदराबाद में सानिया मिर्ज़ा की शादी में शामिल होने गई थीं. डॉ. फिरदौस स्यालकोट की रहने वाली हैं जहां के शोएब इक़बाल हैं. वे पाकिस्तान के लोगों की तरफ़ से एक ताज लेकर आई थीं जिसे उन्होंने सानिया मिर्ज़ा को पहनाया. लेकिन डॉक्टर फिरदौस मुंबई क्यों आईं, इस सवाल का जवाब हमें तलाशना चाहिए.

डॉ. फिरदौस आशिक़ अवान के कार्ड पर लिखा है फेडरल मिनिस्टर, पॉपुलेशन वेलफेयर, गवर्मेंट ऑफ पाकिस्तान. वे वहां हमारे स्वास्थ्य मंत्री गुलाब नबी आज़ाद की समकक्ष हैं. डॉ. फिरदौस का मुंबई आना एक महत्वपूर्ण घटना थी. वे पाकिस्तान की पहली केंद्रीय मंत्री हैं जो छब्बीस नवंबर की घटना के बाद मुंबई आई हैं. डॉ. फिरदौस उसी ओबेराय होटल में ठहरीं, जहां दहशतगर्दों ने ताज के साथ ही हमला किया था. यह फ़ैसला डॉ. फिरदौस का अपना फ़ैसला था क्योंकि वे मुंबई हमले के शिकार, शहर के ज़ख्म पर मरहम लगाना चाहती थीं. पाकिस्तान सरकार नहीं चाहती थी कि वे मुंबई आएं. उन्हें सलाह दी गई थी कि मुंबई में उन पर हमले हो सकते हैं, बम और मिसाइलें चल सकती हैं. इस सलाह के बाद भी उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद से अपनी इच्छा बताई तो उन्होंने मुंबई में डॉ. फिरदौस को एक एड्स नियंत्रण केंद्र देखने की दावत दी.

डॉ. फिरदौस सत्रह अप्रैल की शाम से अठ्ठारह अप्रैल की शाम तक मुंबई में रहीं, घूमी फिरीं, खाना खाया, लोगों से बात की, एड्स नियंत्रण केंद्र में दो घंटे बिताए तथा मुंबई के सेक्स कर्मियों के बीच एड्स नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को जाना तथा पाकिस्तान में भी ऐसे ही कार्यक्रम चलाए जाने की इच्छा प्रगट की.

मैं डॉ. फिरदौस के साथ लगभग पांच घंटे रहा. उन सभी विषयों पर बातें हुई. जिन पर हो सकती थीं. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ बात किए बिना रह ही नहीं सकता. उनका भी मानना है कि बिना कश्मीर का मुद्दा हल किए स्थायी शांति हो ही नहीं सकती. जब मैंने तर्क दिया कि कश्मीर हमारे लिए धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा सवाल है, क्योंकि अगर मुस्लिम बहुमत के तर्क पर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा तो हिंदुस्तान के हर गांव से मुसलमानों को निकालने की मांग उठेगी क्योंकि वे वहां बहुमत में हैं और तब सारे हिंदुस्तान में दंगा फैल जाएगा. डॉ. फिरदौस ने कहा कि हम कहां कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि कश्मीर के लोगों की इच्छा जानी जाए तथा वैसा ही हल निकाला जाए.

अगर कश्मीर की बात छोड़ दें तो डॉ. फिरदौस पाकिस्तान की मुहब्बत की, पाकिस्तान की ममता की, नुमाइंदगी कर रही थीं. उनका कहना था कि जिन्होंने मुंबई पर हमला किया वे पाकिस्तानी नहीं, और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं वे हिंदुस्तानी नहीं है. ये एक अलग तरह का दिमाग़ है जो किसी भी मुल्क से रिश्ता नहीं रखता. इसके ख़िलाफ़ दोनों ही मुल्कों को खड़ा होना होगा. डॉ. फिरदौस को चिंता है कि बातचीत शुरू होने में जितनी देर होगी उतना ही फ़ायदा दहशतगर्दों को होगा. डॉ. फिरदौस ने मुझसे साफ कहा कि चाहे जितनी देर लड़ाई चले, न आप हमें जीत सकते हैं और न हम आपको. जब मसला बात से ही हल होना है तो बात क्यों न अभी शुरू हो.

डॉ. फिरदौस का मीडिया पर बहुत भरोसा है. उनका मानना है कि मीडिया चाहे तो दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल बना सकता है. उनकी राय है कि सही ढंग के पत्रकारों को दोनों देशों में ज़्यादा आना जाना चाहिए तथा दोनों देशों के लोग क्या सोचते हैं, क्या जानना चाहते हैं, बताना चाहिए. उन्हें इस बात का दुख है कि पाकिस्तान के जंग और हिंदुस्तान के टाइम्स ऑफ इंडिया की अमन की आशा अभियान, आगे नहीं बढ़ पाया. उन्होंने पाकिस्तान की मीडिया पर गुस्सा भी दिखाया जिसने सानिया मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ा है क्योंकि सानिया ने कह दिया था कि वे पाकिस्तान की नहीं, शोएब की बीवी हैं.

मैं डॉ. फिरदौस के साथ लगभग पांच घंटे रहा. उन सभी विषयों पर बातें हुई. जिन पर हो सकती थीं. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिस पर कोई भी पाकिस्तानी राजनीतिज्ञ बात किए बिना रह ही नहीं सकता. उनका भी मानना है कि बिना कश्मीर का मुद्दा हल किए स्थायी शांति हो ही नहीं सकती.

मैंने उनसे जानना चाहा कि वे ओबेराय होटल में ही क्यों रुकीं तो उनका कहना था कि वे मुंबई के दर्द में अपने को शामिल करना चाहती थीं. मैंने उनकी यह ग़लतफहमी दूर की कि मुंबई बमों या मिसाइलों का केंद्र है और उन पर हमला हो सकता है. कुछ उपद्रवी तो हर जगह होते हैं पर मुंबई के लोग उतने ही शांतिप्रिय और मेहमान नवाज़ हैं जितने कराची या लाहौर के. एड्स नियंत्रण सेंटर में कुछ पत्रकारों से बातचीत में डॉ. फिरदौस को इस बात का अहसास भी हुआ. किसी भी पत्रकार ने उनसे मुंबई हमलों, या फिर उन हमलों में पाकिस्तान के शामिल होने जैसे सवाल नहीं पूछे.

डॉ. फिरदौस के साथ मुंबई में रहना एक सुखद अनुभव रहा, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता अगर यह दौरा थोड़ा प्रचारित होता. तब मुंबई के लोग भी उनसे मिल पाते और डॉ. फिरदौस को पता चलता कि मुंबई में रहने वाले लोग कितने ज़िंदादिल हैं. उनसे मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि भी मिलते और बताते कि ऐसे हमले भारत में रहने वालों का मनोबल नहीं तोड़ सकते और उन्हें यह बताते कि वे दुआ करेंगे कि पाकिस्तान के लोगों का मनोबल भी दहशतगर्दों के सामने मज़बूत बना रहे.

जिस एक बात ने मुझे हैरान किया वह यह कि, मुंबई हमलों के बाद पहली बार पाकिस्तान की एक केंद्रीय मंत्री मुंबई आईं और सरकार ने उनकी सुरक्षा में केवल एक सादी वर्दी में सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराया. मुझे न सीआईडी दिखाई दी, न सादी वर्दी में सुरक्षा कर्मी, न कोई पायलट कार और न ही हथियार बंद सुरक्षा कर्मी. वे बिल्कुल एक आम इंसान की तरह मुंबई में रहीं. अगर कहीं कोई हादसा हो जाता तो, या शैतान दिमाग़ लोग उन पर कहीं हमला कर देते तो हमारे ऊपर यही आरोप लगता कि हम अपने मेहमान की हिफाज़त भी नहीं कर सकते. उन्हें हवाई अड्डे पर भी सामान्य प्रोटोकॉल नहीं मिला. यह केंद्र सरकार की ग़लती है या मुंबई सरकार की, यह हम नहीं जानते लेकिन यह ग़लती, बड़ी ग़लती है.

डॉ. फिरदौस में मुझे दो तरह के व्यक्तित्व नज़र आए. एक ओर वे पाकिस्तान की सरकार की मंत्री थीं वहीं वे पाकिस्तान के आम आदमी की इच्छाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रही थीं. मुझे उनके आम आदमी की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करना अच्छा लगा. काश हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राजनीति का बोझ उतार कर आम आदमी की इच्छाओं को अपनी मंज़िल बना सकते. आशा करनी चाहिए कि आज नहीं तो कल, ऐसा होगा.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

नेकी के दूत

खुरशीद आलम

मानवीय मूल्यों और आदर्शों की मृत्यु कभी नहीं होती है. यह मूल्य एवं आदर्श चाहे जिस काल के हों, सदाबहार रहते हैं. यही कारण है कि 1400 साल गुज़र जाने के बाद भी पैगंबर मोहम्मद के महान साथी आज भी चर्चा का विषय एवं प्रेरणास्रोत बने हुए हैं. उन्होंने जो जीवन व्यतीत किया और समाज को जो आदर्श दिया, वह आज भी प्रासंगिक है. इन्हीं बातों पर विचार-विमर्श करने हेतु 10-11 अप्रैल 2010 को मुसलमानों की सबसे पुरानी संस्था मरकज़ी जमीअत अहले हदीस हिंद द्वारा 30वां अहले हदीस अधिवेशन सहाबा की महानता शीर्षक से किया गया. ज्ञात रहे कि पैगंबर मोहम्मद के साथियों को सहाबा इकराम के नाम से जाना जाता है.

यह बात सर्वविदित है कि पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के अंतिम पैगंबर हैं. वह अपने समय में जो संपूर्ण क्रांति लाए, उसमें उनके आसपास के व्यक्तियों में दस वर्षीय चचेरे भाई हज़रत अली से लेकर 40 वर्षीय हज़रत अबुबकर तक शामिल थे. उन्होंने इन सभी को ईशवानी अर्थात कुरआन शरीफ़ एवं अपने उपदेश अर्थात हदीस द्वारा प्रशिक्षित किया. कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद एवं उनके सहाबा इकराम ने जिस समाज का निर्माण किया, वह आदर्श मानव समाज के तौर पर उभरा. इसमें मात्र इबादत करने वाले व्यक्ति ही नहीं, बल्कि ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी पैदा हुए. इन व्यक्तियों में जो भी प्रशिक्षण के बाद सामने आया, वह संपूर्ण मानव था. उसकी संपूर्णता का विशेष कारण यह था कि पैगंबर मोहम्मद ने अपनी शिक्षाओं द्वारा पूर्ण रूप से समाज परिवर्तन की बात की थी और संपूर्ण जीवन व्यवस्था समाज को दी थी. यही कारण है कि सहाबा के प्रशिक्षित लोगों में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है, जिन्हें आदर्श मानव कहा जा सकता है. इस महान टोली ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था दी, जो एक ओर सोशलिस्टों एवं कम्युनिस्टों की वह व्यवस्था नहीं थी, जो समाज को जकड़े हुए होती है. दूसरी ओर पूंजीवाद की वह व्यवस्था नहीं थी, जो खुले बाज़ार होने के कारण बहुत सी समस्याएं पैदा करती है. सहाबा इकराम की अर्थव्यवस्था

में ब्याज का नाम व निशान तक नहीं था. वह ब्याज जो धनी को ज़्यादा धनी बनाकर और ग़रीब को ज़्यादा ग़रीब बनाकर समाज का संतुलन बिगाड़ देता है.

जो शिक्षा आज हमारे देश में अनिवार्य एवं मुफ्त घोषित की गई है, वह पैगंबर मोहम्मद और उनके सहाबा के समय में भी अनिवार्य एवं मुफ्त घोषित की जा चुकी थी. 30वें अखिल भारतीय अहले हदीस सम्मेलन के संयोजक मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी सलफी कहते हैं कि मक्का से मदीना हिज़रत करने के बाद पैगंबर मोहम्मद ने अपने साथियों को लेकर मदीना में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विश्व की जो प्रथम साझा सरकार बनाई थी, उसने अपने गठन के दूसरे वर्ष ही शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त घोषित कर दिया था. उन लोगों के समक्ष शिक्षा को अनिवार्य और मुफ्त घोषित करने के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु जैसी कोई सीमा नहीं थी. किसी भी आयु का व्यक्ति आदर्श मानव बनने के लिए संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकता था.

मौलाना सलफी की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के रूप में आए शोभित यूनिवर्सिटी के प्रो. चांसलर कुंवर शेखर विजेंद्र कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद और उनके सहाबा इकराम की शिक्षा की विशेषता ही यही है कि यह संपूर्ण है एवं एक मानव को संपूर्ण मानव बनाती है. उनका कहना था कि आज विशिष्टता के नाम पर जिस तरह एक-एक गुण वाले व्यक्तियों का निर्माण हो रहा है, उससे समाज का पूरा संतुलन बिगड़ गया है. इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, विज्ञान, साहित्य, इतिहास एवं अन्य ज्ञान हासिल करने वाला व्यक्ति जीवन के उन मूल्यों से अनभिज्ञ है, जो एक इंसान को इंसान बनाते हैं. दूसरी ओर धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति उपरोक्त विशिष्ट शिक्षा से वंचित हैं. यही कारण है कि वह समाज में रहकर भी समाज से कटे रहते हैं. शिक्षा शास्त्री कुंवर शेखर विजेंद्र को आशा है कि वर्तमान में गौरवमय अतीत की बातें कर समाज को टुकड़े-टुकड़े में बांटने से बचाया जा सकेगा.

पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय, जो हिंदी साप्ताहिक चौथी दुनिया के मुख्य संपादक हैं, ने कहा कि किसी भी सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति के लिए युवा शक्ति निर्णायक भूमिका निभाती है. यही कारण है कि पैगंबर मोहम्मद के महान साथियों में अधिकांश युवा वर्ग के थे. उनके अनुसार, युवा वर्ग तभी सकारात्मक एवं क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है, जब वह शिक्षित एवं जीवनयापन के लिहाज़ के संपन्न हो. उन्होंने कहा कि चौथी दुनिया ने रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट के कुछ भागों को सर्वप्रथम छापकर संसद में धूम मचा दी और फिर सरकार को उसे संसद पटल पर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा. उस क़दम का भी एकमात्र लक्ष्य यही था कि आज मुस्लिम एवं दबे-कुचले समाज का युवा वर्ग शिक्षा और नौकरी प्राप्त करने में आरक्षण जैसी सुविधा से लाभांवित होकर सुखी-संपन्न हो और फिर समाज को सही दिशा देने एवं परिवर्तन लाने में अपनी सकारात्मक एवं क्रांतिकारी भूमिका निभाए. उन्होंने कहा कि आज के नौजवानों के लिए भी सहाबा इकराम आदर्श के रूप में मौजूद हैं. उनकी शिक्षाओं पर अमल करके नई पीढ़ी को समाज के नवनिर्माण के लिए तैयार किया जा सकता है.

विख्यात समाज सुधारक एवं आर्यसमाजी नेता स्वामी अग्निवेश ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने एक लंबे काल के बाद एकेश्वरवाद की धारणा को पुनर्जीवित किया और दासता, बंधुआ-बाल मजदूरी एवं महिला उत्पीड़न को समाप्त किया. उन्होंने कहा कि पैगंबर और उनके साथी महिलाओं के सबसे बड़े हितैषी थे. आज इस सभा में एक भी महिला न देखकर निराशा हो रही है. किसी भी समाज का नवनिर्माण किसी भी काल में नर-नारी दोनों को लेकर ही संभव है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि जमीअत अहले हदीस महिलाओं के प्रति अपनी सोच में परिवर्तन लाएगी और उन्हें बराबर की हिस्सेदारी देगी.

सभा के संयोजक एवं मरकज़ी जमीअत अहले हदीस हिंद के सचिव मौलाना मुकीम फैजी ने कहा कि समाज की संरचना में नर-नारी दोनों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए इस्लाम ने उनकी ज़िम्मेदारियां निश्चित की हैं. नारी की यह बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह घर-परिवार को पूर्ण रूप से सुखी-संपन्न बनाए एवं नई पीढ़ी को इस तरह प्रशिक्षित करे कि वह समाज की आदर्श इकाई बनकर उभरे. इस्लाम नर-नारी दोनों की शिक्षा पर बल देता है. सहाबा इकराम के दौर में भी महिलाओं ने पैगंबर मोहम्मद की हदीसों को जमा करने और अपने कर्तव्य निभाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई. राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का विचार था कि भारत के 104 वर्षीय सबसे पुराने मुस्लिम संगठन मरकजी जमीअत अहले हदीस हिंद ने पैगंबर इस्लाम एवं उनके सहाबा इकराम को समाज के आदर्श एवं मॉडल के रूप में एक ऐसे समय प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, जब पूरा समाज दिशाहीन होता जा रहा है. इसलिए संगठन बधाई का पात्र है कि वह देश के नवनिर्माण के बारे में सोचता है.

नेकी के निगहबानों के नाम पर इस दो दिवसीय सम्मेलन की विशेषता यह थी कि इसमें विभिन्न धर्मों, समुदायों, क्षेत्रों एवं देशों के लोग आए और अपने विचार व्यक्त किए. इनमें अयोध्या के स्वामी जुगल किशोर शास्त्री, धार्मिक उपदेशक ओंकार नंद श्रीवास्तव, विश्व धर्मों के विशेषज्ञ डॉ. एम एम वर्मा, धार्मिक विद्वान एवं कार्यकर्ता पंडित एन के शर्मा, सांसद मोहम्मद अदीब, विधायक शोएब इकबाल, देवबंद स्थित जामिया अनवर शाह कश्मीरी के उप कुलपति मौलाना अहमद शाह खिज़र, मस्जिद के इमामों के संगठन के अध्यक्ष मौलाना उमर इलियासी, जमीअत इस्लामी हिंद के सचिव मौलाना रफीक अहमद कासमी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना अताउर रहमान कासमी और अन्य मुस्लिम संगठनों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि विशेष रूप से शामिल हैं.

30वें अहले हदीस सम्मेलन के समापन पर धार्मिक, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित 30 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए. हाल में तुर्की के मरदीन शहर में 14वीं सदी के इमाम इब्ने तैमिया जैसे महान विद्वान के फतवा को पुनः परिभाषित करने की चेष्टा का बिना नाम लिए कहा गया कि आज अनावश्यक तौर पर इमाम इब्ने तैमिया जैसी सुलझी एवं पवित्र इस्लामी हस्ती की छवि धूमिल की जा रही है, जो कि दुःखद है. मीडिया प्रभारी शीश तैमी के अनुसार, यह सम्मेलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिहाज़ से पूरी तरह सफल रहा. जमीअत महासचिव के निजी सचिव एवं कार्यकर्ता मोहम्मद रईस फ़ैजी ने कहा कि सम्मेलन में शामिल हुए लोग यही पैगाम लेकर गए कि धर्म एवं समुदाय से ऊपर उठकर सहाबा इकराम आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं और रब के वफ़ादार एवं इंसानियत के सच्चे अलमबरदार हैं. उनके जीवन एवं मिशन को आदर्श और मॉडल के रूप में लेना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

चीन में ज़्यादातर महिलाएं ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहती हैं, जिनके माता-पिता के पास अकूत दौलत हो.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सरकारी दस्तावेज़ देखना आपका अधिकार है

आरटीआई क़ानून में कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग की फाइल, किसी भी विभाग द्वारा कराए गए काम का निरीक्षण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आपके क्षेत्र में कोई सड़क बनाई गई है और आप उसके निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री से संतुष्ट नहीं हैं या सड़क की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं तो आप निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस बारे में और विस्तृत जानकारी हम अगले अंक में देंगे. इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि सरकारी फाइल का निरीक्षण कैसे किया जा सकता है और यह क्यों ज़रूरी है. कई बार जब आप किसी सरकारी विभाग से सूचना मांगते हैं तो आपसे कहा जाता है कि अमुक सूचना हज़ार पृष्ठों की है और इसके लिए आपको एक ख़ास शुल्क अदा करना होगा.

कुछ मामलों में तो आवेदक से लाखों रुपये मांगे गए. मालूम हो कि पिछले दिनों बिहार के एक आवेदक से सूचना उपलब्ध कराने के बदले कई लाख रुपये जमा कराने को कहा गया था. लेकिन, यह सब कुछ सिर्फ़ आवेदक को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है. इसके पीछे सरकारी अधिकारियों की यह मंशा होती है कि ऐसा करने से आवेदक सूचना की मांग नहीं करेगा. लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. हालांकि इस मामले में थोड़ी सी सावधानी की भी ज़रूरत है. सावधानी, आवेदन बनाने और सवाल पूछने के तरीक़ों में. मसलन, अगर किसी

ख़ास फ़ाइल में से कुछ ख़ास सूचनाएं ही चाहिए तो आवेदक को पूरी सूचना मांगने के बजाय फ़ाइल निरीक्षण के लिए आवेदन करना चाहिए. बिहार के पूर्णिया ज़िले से राममूर्ति तिवारी ने हमें पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि उन्होंने बिहार राज्य भंडार निगम से कुछ सूचनाएं मांगी थीं, लेकिन विभाग ने उन्हें काग़ज़ातों का एक पुलिंदा थमा दिया, जिसमें उनके द्वारा मांगी गई सूचना थी ही नहीं. ज़ाहिर है, इस समस्या से आवेदकों को अक्सर दो-चार होना पड़ता है. इस कॉलम के ज़रिए हम राममूर्ति जी और आरटीआई क़ानून का इस्तेमाल करने वाले सभी आवेदकों को सलाह देना चाहेंगे कि जब कभी उन्हें किसी फ़ाइल से कोई सूचना मांगनी हो तो अपने आरटीआई आवेदन में एक सवाल फ़ाइल निरीक्षण को लेकर भी जोड़ें. या फिर आप चाहें तो उक्त फ़ाइल के निरीक्षण के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं.

आरटीआई एक्ट की धारा 2 (जे) (1) के तहत आप इसकी मांग कर सकते हैं. इस अंक में हम फ़ाइल निरीक्षण से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं.

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश
पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

सरकारी फाइल के निरीक्षण से संबंधित आवेदन का प्रारूप

सेवा में, दिनांक....

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय का नाम....
पता....

विषय : सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

मैं सूचना का अधिकार कानून 2005 की धारा 2(जे)(1) के तहत अमुक फाइल.....का निरीक्षण करना चाहता/चाहती हूं. इस संबंध में आप मुझे एक तय तिथि, समय और जगह के बारे में सूचित करें, ताकि मैं आकर उक्त फाइल का निरीक्षण कर सकूं. साथ ही इस बात की भी व्यवस्था करें कि मुझे उक्त फाइल का जो भी हिस्सा चाहिए, उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध कराई जा सके. इसके लिए नियत शुल्क का भुगतान मैं कर दूंगा/दूंगी.

मैं इस आरटीआई आवेदन के साथ दस रुपये का आवेदन शुल्क जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम....
हस्ताक्षर....
पता....

ज़रा हट के

सदियों पुरानी ममियों की खोज

मिस्र के पुरातत्वविदों ने राजधानी काहिरा से तीन सौ किलोमीटर दूर रेगिस्तान में एक नक्काशीदार प्लास्टर में 14 ताबूत खोज निकाले हैं. इनमें से एक ताबूत महिला का है. खुदाई का नेतृत्व करने वाले महमूद अफीफी का कहना है कि यह बहरिया ओएसिस में पाई गई रोमन शैली की पहली ममी है. यह ग्रीको रोमन समय की 14 कब्रों की खोज का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि यह एक अनोखी खोज है. यह ताबूत केवल 3 फुट यानी एक मीटर लंबा है. यह एक ऐसी महिला को दर्शाता है, जिसने एक लंबा अंगरखा, सिर पर स्कार्फ, कंगन, मोतियों का हार और जूते पहन रखे हैं. ताबूत में आंखों की जगह पर जड़े रंगीन पत्थरों की उपस्थिति से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे वह महिला जाग रही हो.

उन्होंने कहा कि दफ़नाने की यह शैली इस बात का संकेत देती है कि इसे मिस्र के रोमन शासन के समय दफ़नाया गया था. यह शासन ईसा पूर्व 31वीं शताब्दी से शुरू होकर कई सौ सालों तक चला था. यह ताबूत ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का हो सकता है.

ताबूत के छोटे होने के कारण यह संदेह जताया जा रहा था कि यह किसी बच्चे का हो सकता है, लेकिन ताबूत पर की गई सजावट और गहनों को देखकर तो यही लगता है कि यह किसी महिला का है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर मरने के बाद ममी अपना आकार बदलती है और छोटी हो जाती है. यह भी हो सकता है कि यह महिला बेहद छोटी थी. फ़िलहाल यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह ताबूत किस महिला का है, लेकिन यह निश्चित है कि यह महिला किसी बड़े घराने की थी. इसीलिए उसके ताबूत पर इतनी मेहनत से नक्काशी की गई है. उन्होंने यह भी बताया कि छोटे क़द के लोगों की ममियां पहले भी मिस्र में पाई गई हैं. वे स्थानीय धर्मों के महत्वपूर्ण लोगों की रही हैं. पुरातत्वविदों को सोने का एक टुकड़ा भी मिला है, जिस पर मिस्र के भगवान होरस के चार बेटों की तस्वीरें बनी हैं. इसके अलावा कई कांच-मिट्टी के बर्तन और कुछ धातु के सिक्के भी पाए गए हैं. इन सिक्कों की जांच की जा रही है. इससे इस बात की पुष्टि हो सकेगी कि यह किस समय के हैं.

पैसा-पैसा करती है...

पैसा-पैसा करती है, क्यों पैसे पर तू मरती है...यह गाना तो आपको याद ही होगा. चीन में महिलाएं इस गाने को अपनी निजी ज़िंदगी में उतारने पर आमादा हैं. चीन में ज़्यादातर महिलाएं ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहती हैं, जिनके माता-पिता के पास अकूत दौलत हो. इसका ख़ुलासा एक सर्वे में हुआ है. समाचारपत्र चाइना डेली ने एक अध्ययन के हवाले से इस संबंध में ख़बर प्रकाशित की है. उसके मुताबिक़, कॉलेज जाने वाली चीन की 60 प्रतिशत लड़कियां धनी युवकों से विवाह करना चाहती हैं, जो अपने माता-पिता की अकूत संपत्ति के वारिस हों.

वूमेंस फेडरेशन ऑफ गुआंगजौ ने गुआंगडोंग प्रांत में एक सर्वेक्षण किया था. सर्वेक्षण में पाया गया कि 59.2 प्रतिशत महिलाएं 80 के दशक में जन्मे पुरुषों से विवाह करने को प्राथमिकता देती हैं और 57.6 प्रतिशत महिलाएं अच्छी क्षमता वाले पुरुषों को अपना जीवनसाथी चुनना चाहती हैं. गुआंगजौ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर लियू शूकेन कहती हैं कि ज़्यादातर कॉलेज छात्राएं एक आरामदायक जीवन जीना चाहती हैं. साथी से विश्वासघात के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में 20 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि वे अपने साथी द्वारा कभी-कभार की गई बेवफ़ाई बर्दाश्त कर सकती हैं. इस बीच केवल 10 प्रतिशत महिलाओं ने ही यह स्वीकार किया कि वह अपने जीवन में सिर्फ़ एक ही व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहेंगी.

सर्वेक्षण में 992 महिलाओं के साक्षात्कार लिए गए. उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और वास्तविकता से रूबरू कराया. इस सर्वेक्षण के ज़रिए पारस्परिक संबंधों जैसे मुद्दों पर कॉलेज छात्राओं के मूल्यों का भी आकलन किया गया.

राशिफल

दिल्ली, 03 मई-09 मई 2010

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र में सक्रिय रहना होगा, वरना अपने विरोधियों की साजिश का सामना करना पड़ सकता है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. आप कुछ नए दोस्त बनाएंगे, जो आगे चलकर मददगार साबित होंगे.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
कुछ चीज़ों पर काफी ख़र्चा होगा. यात्रा आपके लिए सफल रहेगी और आपको कई नए अवसर भी मिलेंगे. परिवार से जुड़े कुछ मामले सिर उठाएंगे, जो आपके लिए तनाव का कारण बनेंगे. लेकिन कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन ख़ुशियों से भरा रहेगा.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
योजनाबद्ध तरीक़े से प्रयास करने पर व्यवसायिक सफलता मिलने की संभावना है. आप सांस से जुड़ी दिक़्क़त से गुज़र सकते हैं. इस सप्ताह यात्रा न करें, क्योंकि वह आपके लिए हानिकारक हो सकती है. मांगलिक कार्यों के लिए किया जा रहा प्रयास सफल होगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
कार्यक्षेत्र में सच के रास्ते पर चलकर अपनी दिक़्क़तों से बाहर निकलना आसान रहेगा. रचनात्मक दिशा में किया जा रहा प्रयास सफल होगा. स्वास्थ्य को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे. अपने होम टाउन या कहीं और घूमने का कार्यक्रम बनाएंगे. सप्ताह के अंत में कुछ तनाव भरे पलों से गुज़रेंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए सफल होगी. आप परिवार के लोगों को उनके मुताबिक़ काम करने के लिए फ्री छोड़ देंगे. परिवार का कोई बच्चा आपके लिए तनाव की वजह बनेगा. कुछ चीज़ों पर काफी ख़र्च होगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
आपके लिए यह सप्ताह काफी अच्छा साबित होगा. व्यवसायिक तौर पर भी अच्छा रहेगा और उम्मीदों के मुताबिक़ परिणाम देगा. व्यवसाय से संबंधित यात्रा आपके कामों को आसान बना देगी. परिवार से जुड़े मामलों पर नियंत्रण करने के लिए आपको चतुराई से काम लेना होगा.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
किसी नए प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च होगा. अपनी खुराक ठीक रखें, नहीं तो स्वास्थ्य धोखा दे सकता है. यही समय है, जब आप अपने जीवन में मनचाहा बदलाव ला सकते हैं. परिवार का कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति आपके लिए तनाव की वजह बनेगा. आय के नए रास्ते खुलेंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस हफ्ते कुछ व्यवसायिक बदलाव होंगे. कुछ दिक़्क़तें अचानक सिर उठाएंगी और आपको उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी. स्वास्थ्य ठीक रहेगा. यात्रा आपके लिए फ़ायदे से भरपूर रहेगी. हफ्ते के अंत में आप अपनी दिक्कतों से बाहर निकल आएंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
समय मध्यम रहेगा. सोच-विचार कर काम करने की आवश्यकता होगी. परिवार की ज़िम्मेदारियां बढ़ेंगी. व्यर्थ की उलझनों एवं विवाद से दूर रहना बेहतर होगा. संतान के संबंध में कोई सुखद समाचार मिल सकता है. आर्थिक क्षेत्र में किया जा रहा प्रयास सफल साबित होगा.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
धैर्य और कूटनीतिक प्रयासों से आपके लिए कई प्रोजेक्ट पूरे करना आसान होगा. स्वास्थ्य को लेकर अतिरिक्त सजगता की ज़रूरत है, नहीं तो हड्डियों से जुड़ी दिक़्क़त हो सकती है. व्यवसायिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आएगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
आर्थिक बदलाव अच्छे रहेंगे और आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा. साझीदारी से जुड़ी किसी गतिविधि में बैलेंस बनाकर चलें. परिवार का सहयोग मिलेगा. यात्रा आपके लिए निराशा से भरी साबित हो सकती है, उससे ख़ास फ़ायदा नहीं होगा.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
व्यवसायिक मामलों में देरी होगी, लेकिन आगे चलकर चीजें ठीक हो जाएंगी. किसी अधीनस्थ कर्मचारी का सहयोग मिल सकता है. स्वास्थ्य पर ध्यान अवश्य दें. शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता के योग हैं.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

फाटा (फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज) के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में सीटें रखी गई हैं, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों जैसी कोई व्यवस्था नहीं है.

चुनौतियां अभी शेष हैं...

लंबी प्रतीक्षा के बाद संवैधानिक सुधारों को नेशनल एसेंबली और सीनेट की मंज़ूरी भले मिल गई हो, लेकिन चुनौतियां अभी बाक़ी हैं. सुधार प्रस्तावों पर काम करने के लिए सीनेटर रजा रब्बानी और समिति के दूसरे सदस्य तारीफ़ के क़ाबिल ज़रूर हैं. हालांकि प्रस्तावित सुधार पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन भविष्य में स्पष्ट दिशानिर्देश के लिए यह बुनियाद अच्छी है.

ख़ैर, सुधार की राह में मुश्किलें आ सकती हैं. इसकी कमज़ोरियों की वजह से नहीं, बल्कि इसके मज़बूत पक्षों की वजह से. इसकी तीन मुख्य वजहें हो सकती हैं–लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मज़बूती, प्रांतों के अधिकार और दो नए मौलिक अधिकारों (सूचना और प्राथमिक शिक्षा के अधिकार) का विस्तार. अधिकारों की मूल अवधारणा के नज़रिए से उक्त सुधार कहीं–कहीं असंगत और अतार्किक दिखते हैं. उद्देश्य प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समिति ने स्वतंत्रता शब्द को फिर से जोड़ा, लेकिन प्रस्ताव के कई दूसरे हिस्से सहनशीलता के इस जज़्बे के ख़िलाफ़ हैं. 1973 के संविधान की तर्ज पर 18वें संविधान संशोधन के बाद प्रधानमंत्री के लिए मुसलमान होना अनिवार्य है. हालांकि ग़ैर मुस्लिम नेशनल एसेंबली का चुनाव लड़ सकता है, हो सकता है कि उसे बहुमत का समर्थन भी हासिल हो जाए, लेकिन वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता. परिणामस्वरूप अब कोई मुस्लिम ही संसदीय दल का नेतृत्व कर सकता है. हमारे राजनीतिक नेतृत्व को एक बार अपना निर्णय स्पष्ट करना होगा. या तो वह अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपातरहित नीतियों को लेकर वचनबद्ध हो जाए या फिर कट्टरपंथी नीतियों को खुलेआम स्वीकार करे.

हमेशा की तरह फाटा (फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज) के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में सीटें रखी गई हैं, लेकिन महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों जैसी कोई व्यवस्था नहीं है. इसके दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो इन इलाक़ों में महिलाएं रहती ही नहीं या फिर पीड़ित होने के लिए मजबूर हैं. क्या दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह यहां की महिलाएं असुरक्षित नहीं हैं और क्या उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने की ज़रूरत नहीं है?

समिति ने संविधान के अनुच्छेद 62 और 63 क़ायम रखे हैं, जो सांसदों की योग्यता और अयोग्यता को स्पष्ट करते हैं. इनमें कुछ ओछे बदलाव किए गए हैं, लेकिन उनसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला. संसद के सदस्यों और उम्मीदवारों को स्वाभाविक तौर पर बुद्धिमान, नेक चरित्र वाला और ईमानदार समझा जाता है, जब तक कि क़ानून की कोई अदालत ऐसा मानने से इंकार न कर दे. दूसरे शब्दों में कहें तो संसद के किसी सदस्य के चरित्र पर तब तक उंगली नहीं उठाई जा सकती, जब तक कि उसके ख़िलाफ़ आरोप प्रमाणित न हो जाएं. समिति ने ऐसे संसद सदस्यों के लिए अयोग्यता के सिद्धांत को हटा दिया है, जो आपराधिक मामलों या झूठे साक्ष्य देने के दोषी रहे हैं.

देश की राजनीतिक पार्टियां सामंतवादी चरित्र की हैं और नफ़रत की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र हैं. दलबदल क़ानून के प्रावधानों का चरित्र भी दमनकारी है, क्योंकि वे उन्हें पार्टी आलाकमान के निर्णय को मानने के लिए बाध्य करते हैं. पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सत्तर महिलाओं और अल्पसंख्यकों को चुनता है. उनके चुने जाने का कोई और पैमाना नहीं है, सिवाय इसके कि वे आलाकमान के लिए स्वीकार्य हों. पार्टी के भीतर चुनाव अब अनिवार्य नहीं रह गया है. राजनीतिक दलों को धार्मिक, सामुदायिक या प्रांतीय विद्वेष की भावना फैलाने से रोकने वाले प्रावधान हटा दिए गए हैं. अब लश्कर और अन्य अलगाववादी संगठन न केवल घृणा फैलाने के लिए स्वतंत्र हैं, बल्कि चुनाव भी लड़ सकते हैं.

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री युसूफ़ रज़ा गिलानी और राष्ट्रपति आसिफ़ अली ज़रदारी

तमाम कमियों के बावजूद समिति ने कई क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रशंसनीय पहल की है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की देखरेख में संघीय इकाइयों को घरेलू या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क़र्ज़ हासिल करने की सुविधा और उसके लिए राष्ट्रीय कंसोलिडेटेड फंड को जमानत के रूप में पेश करने की सुविधा. इसके अलावा यदि किसी प्रांत या उसकी जलीय सीमा के आसपास खनिज पदार्थ, तेल या प्राकृतिक गैसों के भंडार मिलते हैं तो उन्हें संघ और प्रांतों के बीच बराबर बांटा जाएगा. इस प्रस्ताव को लागू करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह केंद्र के पैसों पर पलने वाली संस्थाओं के हितों पर चोट पहुंचाता है. 18वें संविधान संशोधन विधेयक को व्यवस्था की ओर से असली विरोध का सामना इन्हीं मुद्दों पर करना पड़ सकता है, न कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नाम बदलने या शीर्ष अदालतों में जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव के मुद्दों पर.

काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट (सीसीआई) एवं एनईसी को मज़बूती प्रदान की गई है और उनकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश किए जाने का प्रावधान किया गया है. प्रांतों और केंद्रीय सरकार के बीच किसी विवाद को पहले सीसीआई के स्तर पर सुलझाने की कोशिश की जाएगी. अब तक इसके लिए धारा 184 का सहारा लिया जाता था, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को एकतरफ़ा फ़ैसला लेने का अधिकार हासिल था. चुनाव आयोग को अब स्थाई संस्था बना दिया गया है और वर्तमान जज अब राज्यों के चुनाव आयुक्त भी नहीं हो सकते. ऐसा कोई व्यक्ति कामचलाऊ कैबिनेट का हिस्सा नहीं हो सकता, जिसकी पत्नी या निकट संबंधी चुनाव में प्रत्याशी हो. आपातकाल की घोषणा का अधिकार अब प्रांतीय असेंबलियों के पास होगा, न कि केंद्र द्वारा मनोनीत राज्यपालों के पास. संशोधन के प्रावधानों के मुताबिक़, राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर जनमत संग्रह का आदेश नहीं दे सकता. अब यह अधिकार संसद के पास होगा और इसके लिए प्रधानमंत्री की अनुशंसा अनिवार्य होगी. बेवजह अध्यादेशों को लागू करने से रोकने के लिए भी कुछ कड़े प्रावधान किए गए हैं.

उच्चतर अदालतों में जजों की नियुक्ति सामान्यत: मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के साथ वकीलों के एक प्रतिनिधि के हाथों में होगी. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक समिति इन नामों को संसदीय समिति के पास भेजेगी. संसदीय समिति द्वारा इसे ख़ारिज करने के लिए तीन–चौथाई बहुमत अनिवार्य होगा. किसी प्रांत में राज्यपाल न हो तो न्यायाधीश के पद पर रहते हुए कोई कार्यकारी राज्यपाल की भूमिका नहीं निभा सकता. यदि कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद कोई और सरकारी पद स्वीकार करता है तो उसे उसकी एवज में कोई पारिश्रमिक या अन्य फ़ायदे नहीं मिलेंगे. अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल के पद पर रहते हुए निजी प्रैक्टिस की छूट भी नहीं मिलेगी. पूर्व के प्रावधानों के मुताबिक़, शरीयत अदालत में कम से कम तीन जज ऐसे होते थे, जिनके लिए इस्लामिक क़ानून का अच्छा जानकार होना अनिवार्य था. अब इसमें बदलाव किया गया है. नई व्यवस्था में उनके पास इस्लामिक क़ानून एवं शोध आदि के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्षों का अनुभव होना चाहिए.

एक बार फिर से कमियों पर ग़ौर करें तो यह स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार अभी भी कमज़ोर हैं. यहां तक कि यंत्रणा और घोर यातना को भी पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं किया गया है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और कहीं भी आने–जाने पर छूट संबंधी अधिकारों पर अभी भी कई प्रतिबंध हैं. सबसे ख़राब हालत तो आरक्षित सीटों पर मनोनयन की प्रक्रिया का है, क्योंकि इसके चलते अपना निर्वाचन क्षेत्र तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती. एक शीर्ष न्यायिक आयोग का गठन कर मुख्य न्यायाधीश को इसके दायरे में लाए जाने संबंधी प्रावधानों में भी स्पष्टता का अभाव है. फाटा और पाटा मामलों पर भी यह संशोधन एकदम चुप है. हम यही उम्मीद करते हैं कि संविधान को सही स्वरूप देने की प्रक्रिया एक बार में ही ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि लगातार जारी रहेगी. पाकिस्तान में लोकतंत्र तभी मज़बूत हो सकता है, जबकि पहले व्यवस्थागत ख़ामियों को दूर किया जाए. अच्छी सरकार के लिए सुदृढ़ क़ानूनी ढांचे की ज़रूरत से इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ती रहे, इसके लिए योग्यता का विकास और नैतिक शुचिता का कोई विकल्प नहीं है.

आस्मा जहांगीर

(लेखिका पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

दयालु साई बाबा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. इसलिए दुर्घटना में तात्या को अधिक चोट नहीं लगी.

भक्ति की शक्ति

साई बाबा की आज्ञा न मानने का परिणाम

श्री साई सच्चरित्र के नौवें अध्याय में साई बाबा की आज्ञा की अवहेलना करने पर भक्त की कैसी दुर्दशा होती थी, इसका उल्लेख किया गया है. एक बार साई बाबा द्वारकामाई की अपनी गद्दी पर बैठे थे, तभी तात्या कोते पाटिल बहुत जल्दी में उनके पास आए और कहने लगे, मैं कोपरगांव जा रहा हूं. और, फिर बिना बाबा की आज्ञा लिए वह मुड़कर चल पड़े. बाबा ने उन्हें आवाज़ देकर रोका और जल्दी न करने की चेतावनी देते हुए सुझाव दिया कि शामा को साथ लेते जाओ, पर जाने की जल्दी में तात्या साई बाबा की आज्ञा सुनी-अनसुनी करके निकल गए. वह दो घोड़े वाले तांगे पर बैठकर कोपरगांव की तरफ़ बढ़ रहे थे, पर अभी शिरडी की सीमा समाप्त भी नहीं हुई थी कि अचानक एक घोड़ा जो काफी महंगा और चंचल था, तेज़ी से दौड़ने लगा. दूसरा घोड़ा उसकी जैसी गति से नहीं दौड़ पा रहा था. इस भागदौड़ से उसकी कमर में मोच आ गई और वह गिर पड़ा. बाबा के मना करने पर भी तात्या जल्दबाज़ी में निकले थे, पर दयालु साई बाबा हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं. इस दुर्घटना में तात्या को अधिक चोट तो नहीं लगी, परंतु उस घड़ी उन्होंने जीवनपर्यंत साई आज्ञा मानने का निश्चय कर लिया.

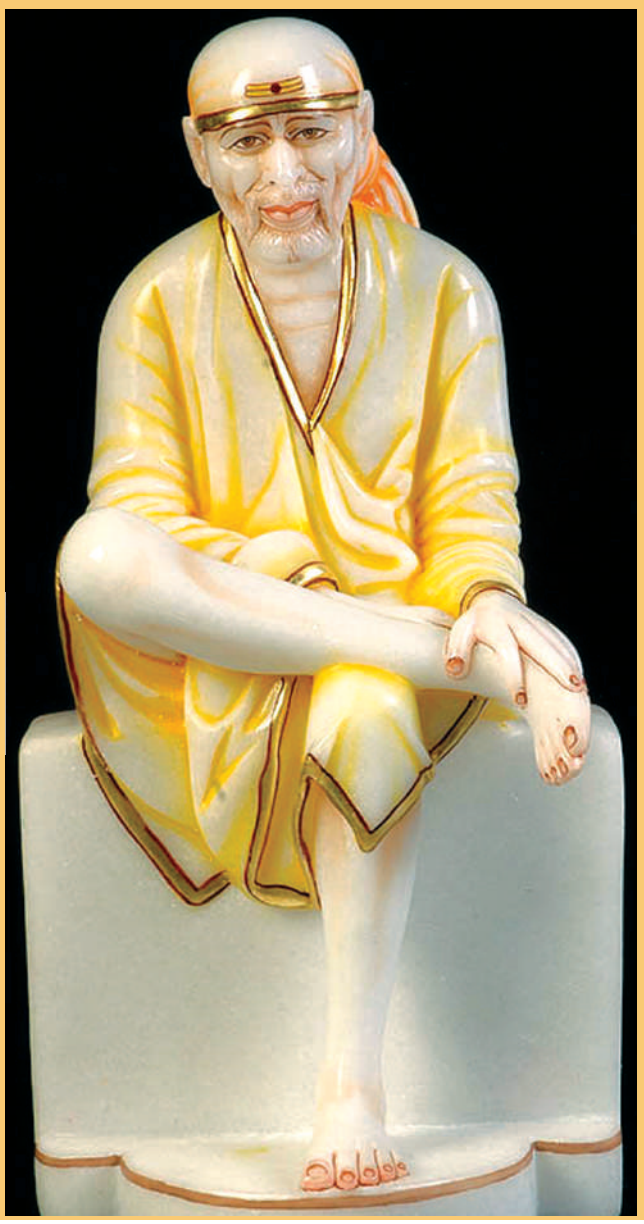

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

ज्ञानोदय

▶ जंज़ीरें, जंज़ीरें ही हैं, चाहे वे लोहे की हों या सोने की, वे समान रूप से तुम्हें गुलाम बनाती हैं.
स्वामी रामतीर्थ

▶ चाहे गुरु पर हो या ईश्वर पर, श्रद्धा अवश्य रखनी चाहिए. क्योंकि बिना श्रद्धा के सब बातें व्यर्थ होती हैं.
समर्थ रामदास

▶ केवल वही व्यक्ति बेकार नहीं , जो बैठा रहता है. बल्कि वह भी बेकार है , जिसकी योग्यता का पूर्ण लाभ नहीं लिया जाता .
सुकरात

▶ कष्ट ही तो वह प्रेरक शक्ति है जो मनुष्य को कसौटी पर परखती है और आगे बढ़ाती है.
सावरकर

▶ मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता.
चाणक्य

▶ हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है. उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनता है.
वाल्मीकि

हमारी भक्ति

साई बाबा के जीवन एवं सच्चरित्र और आपकी अपनी भक्ति से संबंधित किसी एक विषय पर यहां परिचर्चा की जाएगी और श्रेष्ठ विचार भेजने वाले साई भक्त के विचार यहां प्रकाशित किए जाएंगे.

साई बाबा ने फ़कीरी का चोला ही क्यों धारण किया?

आपके जवाब

1. (सर्वश्रेष्ठ विचार)
साई बाबा हमेशा से ही दीन दुखियों की मदद करते रहे हैं. वह चाहते तो ऐशोआराम की ज़िंदगी बिताते पर अपने ग़रीब और ज़रूरतमंद भक्तों के क़रीब रहने के लिए उन्होंने फकीरी का चोला पहना.
रवि कुमार, अलीगढ़

2. बाबा का कोई घर नहीं था, वह जहां चाहते वहीं बसेरा कर लेते थे. इसके अलावा फकीर की भेष में वह सभी भक्तों के घर पहुंचकर उनका हालचाल जानते थे. इसलिए हर दरवाज़े पर पहुंचकर लोगों के कष्टों का समाधान करने के लिए उन्होंने इस चोले को पहना.
कुमार महेंद्र, झारखंड बिहार

3. साई बाबा पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते थे कि जब देश में कई लोग अन्न, पानी के लिए तरस रहें हो तो ऐसे वह कैसे आराम कर सकता है. लोगों में समानता और सद्भाव का संदेश प्रचारित करने के लिए साई ने फकीरी का चोला पहना था.
रमन कुमार, सतना, मध्य प्रदेश

आप अपने विचार sai4world@gmail.com पर मेल करें अथवा शिरडी साई बाबा फाउन्डेशन, पोस्ट बॉक्स नम्बर-17517, मोतीलाल नगर नम्बर-1, गोरेगाँव (पश्चिम), मुम्बई-58 पर डाक द्वारा भेजें या 09999313918 पर एसएमएस करें.

साई बाबा का सभी धर्मों के प्रति क्या दृष्टिकोण था?

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious Studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Fumished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

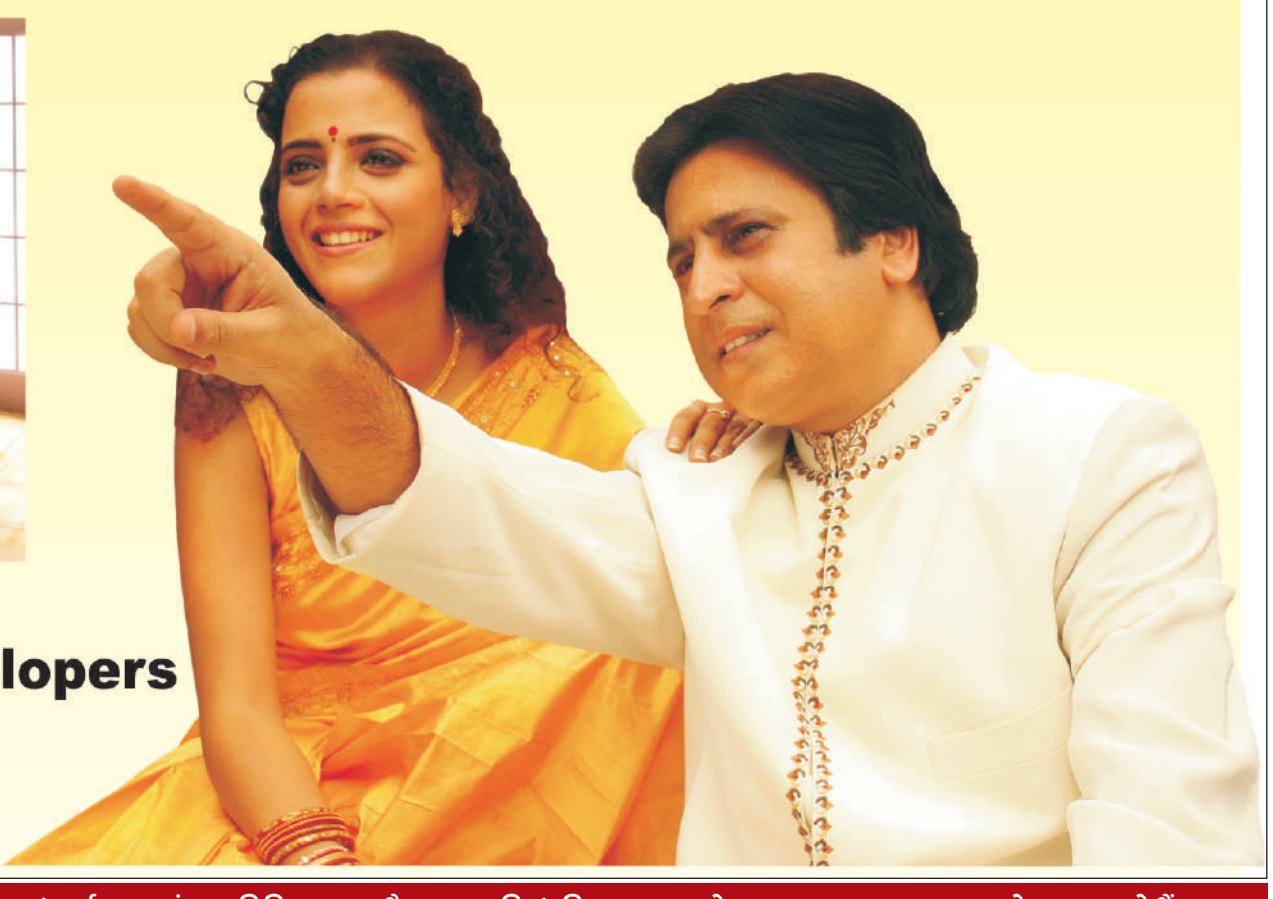

AUM Infrastructure & Developers

Aum Infrastructure & Developers
Tel: 011-46594226 / 46594227
www.girirajsaihills.in

समस्याएं बहुत थीं और अब भी हैं. गंगातट पर गंगा चिंतन की कोशिशें दिखीं, पर वे सारी कोशिशें राजनीतिक दांव-पेंच बनकर रह गईं.

स्त्री के विद्रोह की कहानियां

अनंत विजय

बात अस्सी के शुरुआती दशक की है. उस वक़्त मैं बिहार के जमालपुर के रेलवे हाईस्कूल का छात्र था. यह वह दौर था, जब टेलीविज़न सुदूर शहरी और ग्रामीण इलाक़ों में नहीं पहुंच पाया था. ख़बरों के लिए हम लोग आकाशवाणी के पटना और दिल्ली केंद्र पर निर्भर रहते थे. शाम साढ़े सात बजे पटना आकाशवाणी से प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण होता था, जिसे हमारे घर में नियमित सुना जाता था. इसके अलावा रात पौने नौ बजे राष्ट्रीय समाचार आते थे, जिन्हें सुनकर हम लोग सो जाते थे. लेकिन आकाशवाणी से ज़्यादा हमारा भरोसा उस वक़्त बीबीसी की हिंदी प्रसारण सेवा पर था. वक़्त ठीक से याद नहीं है, लेकिन अगर मेरी स्मृति ठीक है तो शाम सात बजकर चालीस मिनट पर बीबीसी से हिंदी में ख़बरों का प्रसारण होता था. ओंकार नाथ श्रीवास्तव, रमा पांडे आदि की आवाज़ में ख़बरों का जब प्रसारण होता था तो उनके बोलने के अंदाज़ से ख़बरों में गहराई आ जाती थी. आकाशवाणी के समाचारवाचकों की आवाज़ भी बेहद अच्छी थी और उच्चारण एकदम साफ होता था, लेकिन बीबीसी में प्रसारण के तरीक़े और बैकग्राउंड म्यूज़िक से प्रस्तुतिकरण जानदार हो जाता था. तो, हमारी शाम ख़बरों को सुनकर बीतती थी. बीबीसी की हिंदी सेवा से एक और रोचक याद जुड़ी हुई है. साल के अंत और नए वर्ष की शुरुआत में प्रसारण के वक़्त समाचारवाचक यह ऐलान करता था कि अगर आपको बीबीसी का कैलेंडर चाहिए तो अमुक पते पर हमें लिखें. यह दिल्ली का पता होता था और पोस्ट बॉक्स नंबर लिखना होता था. मैंने भी जब इसे सुना तो सोचा क्यों न एक पोस्टकार्ड लिख दिया जाए. उस वक़्त पोस्टकार्ड पांच पैसे का आता था. मैंने बेहद विनम्रता से कैलेंडर भेजने का अनुरोध पत्र बीबीसी के बताए पते पर भेज दिया. लगभग दस दिनों के बाद ए फोर साइज़ का एक ख़ूबसूरत लिफ़ाफ़ा मेरे पते पर आया, जिसमें प्रेषक की जगह बीबीसी हिंदी सेवा लिखा था. जब मैं स्कूल से लौटा तो अपने कमरे में वह लिफ़ाफ़ा देखकर बेहद ख़ुश हुआ. जल्दबाज़ी में उसे खोला तो एकदम चमकदार काग़ज़ पर एक पन्ने का कैलेंडर था. ऊपर एक ग्रुप फोटो था, जिसमें बीबीसी हिंदी सेवा से जुड़े लोगों की तस्वीर थी. लगभग तीन दशक बाद स्मृति में अब दो ही नाम हैं–ओंकार नाथ श्रीवास्तव और रमा पांडे. तत्काल लिफाफे से निकालकर उसे स्टडी टेबल के सामने लगा लिया. लेकिन फिर एक ख़ुराफात सूझी कि अगर एक पांच पैसे का पोस्टकॉर्ड भेजने पर इतने ख़ूबसूरत काग़ज़ पर छपा कैलेंडर मिल सकता है तो क्यों न कुछ और अनुरोध पत्र भेजकर और कैलेंडर मंगवा लिए जाएं तथा दोस्तों में बांटकर रौब ग़ालिब किया जाए. फिर तो मुझे याद है कि मैंने अपने परिवार के हर व्यक्ति के नाम से अनुरोध पत्र बीबीसी हिंदी सेवा को भेज दिया. चूंकि अनुरोध पत्र एक साथ न भेजकर थोड़े अंतराल पर भेजे गए थे, इसलिए उसी हिसाब से कुछ अंतराल के बाद कैलेंडर मिलने शुरू हो गए. पहले तो डाकिया भी चौंका कि हर एक–दो दिन बाद लंदन के पते से मेरे घर क्या आ रहा है. दबी ज़ुबान से वह यह दरियाफ्त भी करने की कोशिश करने लगा कि इस लिफ़ाफ़े में होता क्या है. एक दिन मैंने उसकी जिज्ञासा ख़त्म करते हुए उसके सामने ही लिफ़ाफ़ा खोलकर उपहार स्वरूप वह कैलेंडर उसे ही दे दिया. अब तो यह हर साल का नियम सा बन गया था. कैलेंडर में चश्मा लगाए ओंकार नाथ श्रीवास्तव और बेहद ख़ूबसूरत रमा पांडे अपने बोलने के अंदाज़ की वजह से भी याद हैं.

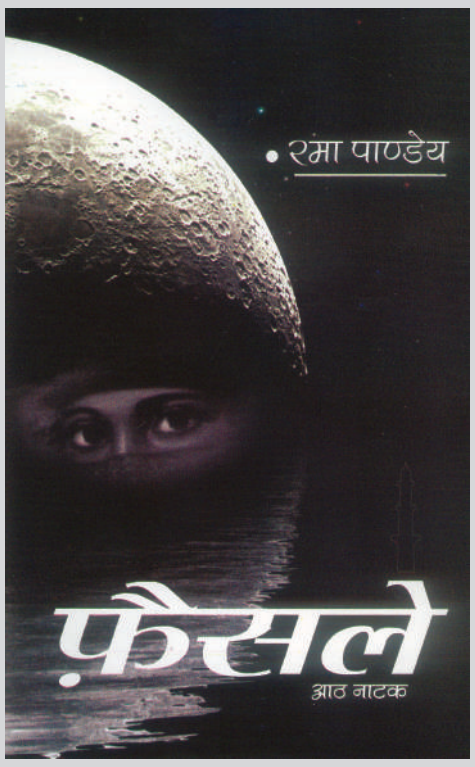

अभी जब मित्र जयप्रकाश पांडे ने बताया कि रमा पांडे के कथा संग्रह की डीवीडी लंदन के नेहरू ऑडिटोरियम में जारी हुई है तो मैं चौंका, कहानी संग्रह की डीवीडी! बातों–बातों में ही जयप्रकाश जी ने यह भी बताया कि रमा पांडे गायिका इला अरुण और पीयूष पांडे की बहन हैं. बात आई–गई हो गई. लेकिन अभी कुछ दिनों पहले किसी संदर्भ के लिए एक किताब ढूंढने में जुटा था तो अचानक *फ़ैसले* पर नज़र गई, जिसकी लेखिका रमा पांडे थीं और दिल्ली के मंजुलिका प्रकाशन से छपी थी

किताब. उसे निकाल कर अलग रख लिया. फिर उसे पढ़ना शुरू किया. स्त्री विमर्श के इस दौर में पिछले वर्ष प्रकाशित इस किताब की साहित्य जगत में नोटिस ली जानी थी, लेकिन अफसोस कि हिंदी के कर्ताधर्ताओं की नज़र इस अहम किताब पर नहीं गई. मुस्लिम महिलाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानियां इनके संघर्ष और व्यवस्था के ख़िलाफ़ उठ खड़े होने की कहानी है. रमा पांडे बहुआयामी प्रतिभा की धनी हैं. वह देश की पहली महिला प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने लंबे अरसे तक दूरदर्शन के लिए काम करते हुए अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी.

जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि *फ़ैसले* देश की मुस्लिम महिलाओं की संघर्ष की दास्तां है. इसकी एक कहानी *दौड़ती हिरणी* की नायिका रमा पांडे की दोस्त हैं. रमा पांडे बताती हैं कि स्कूल के दिनों में राबिया उनकी दोस्त थी और बेहद प्रतिभाशाली एथलीट थी, लेकिन नवीं कक्षा में जाते ही राबिया के परिवार वालों ने उसके खेल में भाग लेने पर इसलिए रोक लगा दी, क्योंकि वे राबिया का निकाह करना चाहते थे. रमा पांडे को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने राबिया की अम्मी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ नाकामी लगी. राबिया के परिवार वाले टस से मस होने को तैयार नहीं थे और परिवार के दबाव में राबिया कोई भी क़दम उठाने को तैयार नहीं थी. जब रमा ने उसे अपने पांव पर खड़े होने की सलाह दी तो उसका जवाब था, जब दौड़ नहीं सकती तो अपने पांव पर क्या खड़ी हो पाऊंगी. लेकिन फिर भी राबिया ने हौसला नहीं छोड़ा और उसने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया. कई वर्षों तक रमा और राबिया नहीं मिलीं, लेकिन वर्षों बाद जब वे मिलीं तो राबिया की उम्र बयालिस की हो चुकी थी और उसने शादी न करने का फ़ैसला कर लिया था. यह एक ऐसी लड़की का विद्रोह था, जो एक पारंपरिक मुस्लिम परिवार से आती थी. लेखिका पर इस बात का गहरा असर पड़ा और दौड़ती हिरणी इसी असर के परिणामस्वरूप सामने आई. *फ़ैसले* में और भी कई कहानियां हैं, जिन्हें लेखिका ने बेहद क़रीब से अपनी आंखों के सामने घटते हुए देखा है. चाहे वह उनके ख़ुद के रिश्तेदार के पैरा जंपर से एक स्कूल के हेडमिस्ट्रेस बनने की कहानी हो या फिर हैदराबाद की शाइस्ता की दास्तां. *फ़ैसले* संग्रह की अमूनन सारी कहानियां यथार्थ का चित्रण हैं. इस कहानी संग्रह में जो एक बात रेखांकित की जा सकती है, वह है नायिकाओं का समाज और व्यवस्था के प्रति विद्रोह. रमा पांडे की भाषा में शास्त्रीयता नहीं है, जो इसे बोझिल बनाने के बजाय पठनीय बनाती है. स्त्री विमर्श के झंडाबरदारों के लिए रमा की कहानियां एक चुनौती की तरह हैं और मुझे लगता है कि देर–सबेर उन्हें इस संग्रह का नोटिस लेना ही पड़ेगा.

(लेखक आईबीएन–7 से जुड़े हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक अंश मुन्नी मोबाइल

गतांक से आगे

प्रदीप सौरभ

नहीं सूफी रोज़–रोज़ की तकरार को अपनी आंख से गुज़रते देखती. आनंद का तेज़ गुस्सा देख वह सहमी सी रहती. एक बार कुछ ऐसी ख़ास घटना हो गई, जिससे दरार और बढ़ गई और शिवानी ने अपना सामान बांध मायके जाने का निश्चय कर लिया. आनंद भारती ने कभी किसी को मनाना सीखा ही नहीं था. ऐसी परिस्थिति में वह कभी पहल नहीं करते, भले ही उनका दिल चाहता हो कि यह पल थम जाए. आनंद शायद उस दिन शिवानी को रोक लेते तो घर के सपने कभी नहीं बिखरते, पर न उन्होंने रोका, न वह रुकी. एक बार मायके जाने के बाद शिवानी दोबारा नहीं आई. जाने से पूर्व भी उसने काफी बखेड़ा खड़ा किया. आनंद भारती के ट्रेड यूनियन के विरोधियों को उसने अपना हथियार बना लिया था. उन लोगों एवं अपने घरवालों के साथ मिलकर उसने आनंद भारती पर प्रताड़ना और दहेज का मुक़दमा दर्ज़ करा दिया. उन्हें उनके विरोधियों ने जेल में बंद कराने की योजना बना डाली. आनंद भारती पीड़ा और दु:ख से भर उठे थे. अपने सुंदर से घर परिवार के इस तरह तहस–नहस होने की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी.

आनंद भारती बाहर से जितने भी गुस्सैल रहें, पर अपनों के प्रति स्नेह का झरना उनमें सदैव रहता है. शिवानी को भी वह भीतर से बेहद प्रेम करते थे...लंबे समय तक यह प्रेम उनके भीतर रहा... सूखा तो शायद कभी नहीं...बस सूना सा कोने में निष्क्रिय रह गया. यादें एक बार फिर आनंद को टीस से भर देती हैं. आनंद सोचने लगते हैं कि उन दिनों वह भीतर से कितने परेशान हो उठे थे, पर जीवन में हर लड़ाई का खुलकर सामना करने वाले आनंद ने हर रणनीति का तोड़ निकाला. रोज़–रोज़ की खटपट के चलते उन्होंने दिल्ली छोड़ने का मन बना लिया. इसी बीच वह जिस साप्ताहिक पत्रिका में काम करते थे, वह बंद हो गई. उनके सामने दो प्रस्ताव थे. एक–दिल्ली में रहना है तो दैनिक अख़बार के डेस्क पर काम करना होगा. दूसरा–रिपोर्टिंग करनी है तो दिल्ली छोड़नी पड़ेगी. रिपोर्टिंग वाले प्रस्ताव में आर्थिक लाभ भी था. रिपोर्टर को कनवेंस के नाम पर ठीकठाक पैसे मिलते थे,

जबकि डेस्क पर काम करने वाले को यह लाभ नहीं मिलता. वैसे भी आनंद भारती घरेलू कलह के चलते दिल्ली छोड़ना चाहते थे, तिस पर आर्थिक लाभ. उन्होंने मैनेजमेंट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और दिल्ली सीमा से जुड़े हरियाणा के सोनीपत ज़िले में पोस्टिंग ले ली. मैनेजमेंट परेशान था कि आनंद भारती ने इतनी आसानी से कैसे प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. वास्तव में मैनेजमेंट की उन्हें बाहर भेजने की यह सोची–समझी चाल थी. वह उनकी ट्रेड यूनियन गतिविधियों से परेशान था. सोनीपत में आनंद भारती रहने लगे. दिल्ली के मकान में ताला लग गया. इस बीच उन्होंने तलाक की अर्जी भी कोर्ट में लगा दी. वह मकान बेचने की कोशिशों में जुट गए. रोज़–रोज़ पत्नी के हमलों से भी वह निजात पा गए. कानपुर से हमेशा आकर उन्हें परेशान करना उनकी पत्नी को भी भारी पड़ने लगा. जो ट्रेड यूनियन के विरोधी उनका जुलूस निकलवाने पर तुले थे, उनके सोनीपत चले जाने के बाद ढीले पड़ गए. धीरे–धीरे उनका सहयोग भी उनकी पत्नी को कम हो गया. लड़ते–लड़ते दोनों थक चुके थे. साथ–साथ रहने की सभी संभावनाओं पर विराम लग चुका था.

अगले अंक में जारी

महाकुंभ तो हमेशा ऐसे ही भरता रहेगा

डॉ. कमलकांत बुधकर

14 से 19 अप्रैल 2010 के कुंभनगर हरिद्वार में भगदड़, गंगा में डूबने और ऐसे ही अन्य कारणों से 45 लोगों की मौत हो चुकी है. सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं. 22 अप्रैल तक यानी कुंभ निबट जाने के एक सप्ताह बाद भी 500 से अधिक लोग लापता हैं. इन पांच सौ लोगों को उनके परिजन हरिद्वार के थानों, घाटों, आश्रमों, अखाड़ों, होटलों, धर्मशालाओं, स्टेशन–बस अड्डों, पार्किंगों एवं गलियों–बाज़ारों में ढूंढ–ढूंढ कर थक चुके हैं. ये सब आंकड़े सरकारी हैं. जिस कुंभ को बसाने, सजाने एवं संवारने में तीन महीने से अधिक लग गए, वह शाही स्नान होते ही तीन दिन में उजड़ गया है. यह स्तंभ लिखे जाने तक बैरागी कैंप, दक्षद्वीप, गौरशंकर द्वीप, लीलधारा द्वीप एवं महामंडलेश्वर नगर आदि उजाड़ और वहराने में तब्दील हो चुके हैं. जिनके आश्रम हरिद्वार में हैं, ऐसे साधु–संत कुंभनगर के अस्थायी शिविर छोड़कर अपने–अपने आश्रमों–मठों में लौट गए हैं. बाहर से आए संतों ने भी कुंभनगर से विदाई ले ली है.

भीड़ एवं शोर दोनों काफ़ी कम हो चुके हैं. पुण्यनगर हरिद्वार लाखों लोगों के मल–मूत्र से भरा एक विराट कूड़ेदान और बदबूनगर बन चुका है. जगह–जगह सैकड़ों क्विंटल कूड़े–कचरे के बड़े–बड़े ढेर और गली–मुहल्लों–घाटों पर फैली गंदगी किसी महामारी को न्यौता देती लग रही है. आवागमन के बंधन ढीले होने से हरिद्वार का आम नागरिक प्रसन्न तो है, पर उसने जितनी परेशानियां पिछले दिनों झेली हैं, उन्हें याद कर वह बेचैन हो उठता है. हरिद्वार के इस कुंभ में सब कुछ हुआ, पर वही नहीं हुआ, जिसके लिए हमारे पुरखों ने कुंभ जैसे महापर्व की शुरुआत की थी. अर्थात विचार मंथन ही नहीं हुआ. कहने को सैकड़ों शिविरों में सुबह–शाम प्रवचन हुए, गीता–भागवत हुई, मानस पारायण हुए, रासलीलाएं हुईं, बड़े–बड़े पेशवाई और शाही जुलूस एवं शोभायात्राएं आयोजित हुईं, पर सबमें एक ही बात परिलक्षित हुई. वह यह कि सब तरफ़ सभी लोग अपनी–अपनी डफली पर अपना–अपना राग अलापते रहे. व्यष्टि पूजन का ज़ोर रहा, पर समष्टि चिंतन कहीं पिछड़ गया. साधुगण केवल समष्टि भंडारों और दक्षिणा के लिफ़ाफ़ों तक सिमट कर रह गए. अपने–अपने मंच से हर साधु–संन्यासी ने विश्व शांति और राष्ट्र कल्याण की चर्चा की, लेकिन कोई एकीकृत या समन्वित प्रयास पूरे कुंभ में नहीं दिखाई पड़ा. विश्व हिंदू परिषद के गुप्त राजनीतिक एजेंडे के तहत प्रायोजित प्रयासों को छोड़ दें तो साधु–संत और विभिन्न मुनिवृंद मंचों की शोभा तो बनते रहे, लेकिन कोई ठोस निर्णय या कोई समन्वित संदेश इस महाकुंभ के माध्यम से नहीं दे सके.

समस्याएं बहुत थीं और अब भी हैं. गंगातट पर गंगा चिंतन की कोशिशें दिखीं, पर वे सारी कोशिशें राजनीतिक दांव–पेंच बनकर रह गईं. अखाड़ा परिषद ने गंगा पर बांध न बनाने और चल रही विद्युत परियोजनाओं को बंद करने की मांग उठाई. वरना शाही स्नान न करने की धमकी दी. सरकार ने आश्वासनों में तथास्तु कहा और परिषद नहाने के लिए हरकी पौड़ी की ओर चल दी. कन्या भ्रूण हत्या, ग्लोबल वार्मिंग, नक्सलवाद, आतंकवाद, बलात धर्म परिवर्तन, दहेज, नारी सशक्तिकरण, सामाजिक छुआछूत, दलितोत्थान, पेयजल समस्या, स्वच्छता एवं साक्षरता आदि अनेक मुद्दे थे, जिन पर समाज के इन चिंतक और मनीषी माने जाने वाले साधु–संतों को चिंतन–मनन करना चाहिए था, दिशा देनी चाहिए थी, पर उन्हें अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने थे. मसलन एक–दूसरे को नीचा दिखाना, अपना वैभव प्रदर्शित करना, नक़ली–असली शंकराचार्यों के विवाद उभारने थे, किसी से सार्वजनिक माफ़ी मंगवानी थी, किसी को संगठन से निकालना था, किसी को पदवीदान देकर उच्चासन पर बैठाना था तो किसी के नीचे से आसन

चर्चा कुंभनगर की

खींच लेना था. कह सकते हैं कि हरिद्वार 2010 का महाकुंभ पहला महाकुंभ था, जिसमें भारी संख्या में महामंडलेश्वर बने और बनाए गए. महामंडलेश्वर का बनना अर्थात एक ओर एक व्यक्ति को छत्र–चंवर का मान देकर रथ पालकी में बैठाना और दूसरी ओर उससे अखाड़ों को भारी धनागम होना होता है. सो, इस बार अखाड़े इस धनक्रीड़ा में व्यस्त रहे, मस्त रहे.

अखाड़ों का सारा समष्टि चिंतन भू–आवंटनों से आरंभ होकर नागाओं को दीक्षा दिलवाने, भंडारे करवाने, दान–दक्षिणाओं, शोभायात्राओं और शाही स्नानों तक सिमट कर रह गया. न कोई महामंडलेश्वर सम्मेलन हुआ और न ही कोई आचार्य सम्मेलन. ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसमें सारे महामंडलेश्वर या सारे आचार्यगण एकत्र होकर किसी मुद्दे पर अपनी प्रेरक राय या समन्वित संदेश समाज को दे सकते. जो हुआ, वह सब अपनी–अपनी शैली में अलग–अलग हुआ. हां, जूना पीठ के आचार्य अवधेशानंद गिरि, निरंजनी के स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि, तुलसी पीठ के अर्जुन पुरी, सोहम बाबा, पायलट बाबा, बैरागियों में रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य, मातृसदन के स्वामी शिवानंद, ज्योतिर्मठ एवं द्वारिका मठ के स्वामी स्वरूपानंद, पुरी पीठ के स्वामी निश्चलानंद आदि बीसेक साधु अलबत्ता मीडिया में छाए रहे.

कुंभ जैसे महापर्वों पर सभी कुंभस्थलों पर प्राय: विशिष्ट एवं अति विशिष्ट लोगों के आने की मनाही होती है. ऐसा सरकारी फ़रमान केंद्र और राज्य सरकारें ही जारी करती हैं. लेकिन, इस कुंभ में इस आदेश की धज्जियां उड़ाई गईं. राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल का कार्यक्रम तो खैर बना और निरस्त हो गया, पर उसके बाद वीआइपियों के इतने दौरे हुए कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए. ऐन कुंभ के स्नान वाले दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री डॉ. निशंक ही सपत्नीक गंगा नहाने हरिद्वार आ गए. उनके स्नान का वही समय था, जब भगदड़ में सात व्यक्ति कुचल कर मौत को गले लगा रहे थे.

साढ़े पांच सौ करोड़ रुपये के इस सबसे महंगे महाकुंभ में जितने काम होने थे, उतने सब अभी तक नहीं हुए हैं. अब भी अनेक काम शेष हैं. जो काम हुए, उनमें से कुछ अनुपयोगी सिद्ध हो गए. जो रह गए, सो रह गए. अभूतपूर्व संख्या में आए कुंभ स्नानार्थियों को देखकर अब कहा जा रहा है कि हरकी पौड़ी का विस्तार ज़रूरी था. पर जब उसे होना था, तब अवरोध पैदा किए गए और शासन–प्रशासन दृढ़ इच्छाशक्ति नहीं दिखा सका. जिस तीर्थ प्राधिकरण की मांग बार–बार करके कुंभ व्यवस्थाओं पर पूरे पांच वर्षों तक चिंतन, मनन, कार्यान्वयन और निगरानी करने की बात हर बार कही जाती है, वह अब फिर उठाई जा रही है. पुलिस महकमा एक स्थायी कुंभ अथॉरिटी बनाने के लिए कह रहा है. अभी तो मेला प्रशासन की रिपोर्ट आनी है. सलाह एवं सुझाव पहले भी आते रहे हैं और यह प्रशासन भी देगा. पर उन पर अमल न पिछली सरकारों ने किया और न वर्तमान और न ही आने वाली सरकारों से ऐसी कोई उम्मीद है. ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा. कहने वाले कहते रहेंगे, लिखने वाले लिखते रहेंगे और कुंभ यूं ही आते–जाते रहेंगे. हां, जनता का पैसा सरकारी पैसा बनकर अलबत्ता आधा–अधूरा सार्वजनिक कार्यों में लगेगा और अधिकांश बड़ी–बड़ी जेबों में जाता रहेगा. कुंभ हमेशा से भरता रहा है, कुंभ आगे भी हमेशा भरता ही रहेगा. सरकारों का कुंभ अलग से मनेगा और जनता का कुंभ अलग ही मनता रहेगा! चलिए, मिलते हैं अब 2013 में प्रयाग, 2016 में उज्जैन एवं नासिक और ग्यारह साल बाद 2021 में फिर इसी गंगाद्वार हरिद्वार में!

kk@budhkar.in

लो एंड टॉर्क देने वाली एयरकूल फोर स्ट्रोक एसओएचसी इंजन के साथ वाईबीआर वन टेन बाइक में 4 स्पीड स्लिक गियर बॉक्स है.

जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल द्वारा राजधानी में आयोजित फैशन शो में ज्वेलरी का डिजाइन पेश करती सुपर मॉडल इंद्राणी दासगुप्ता

वाकमैन और फोन टू-इन-वन

युवाओं में मोबाइल के बढ़ते क्रेज़ को देखते हुए कंपनियां आए दिन किसी न किसी नए ऑफर द्वारा उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की कोशिश में लगी रहती हैं. इसी क्रम में सोनी एरिक्सन ने भी सोनी एरिक्सन जाइलो एवं सोनी एरिक्सन स्पायरो नामक नए हैंडसेट मार्केट में उतारे हैं. ख़ास बात यह है कि उक्त दोनों हैंडसेट वॉकमैन की ख़ूबियों से लैस हैं. कुछ नया करने की चाहत में सोनी ने इसके पोर्टफोलियो में दो अफोर्डेबल वॉकमैन जोड़े हैं. सोनी एरिक्सन जाइलो एवं सोनी एरिक्सन स्पाइरो की ख़ास बात यह है कि इनके द्वारा आप संगीत का भरपूर आनंद ले सकते हैं. मतलब यह कि आप फोन और वॉकमैन टू-इन-वन का मज़ा एक साथ ले सकते हैं.

आज की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस फोन में सोशल नेटवर्किंग से संबंधित साइटों जैसे ट्विटर एवं फेसबुक आदि सुविधाएं भी हैं. उक्त हैंडसेट ख़ूबसूरत होने के साथ ही समय की भी बचत करते हैं. इनके की-पैड आधुनिक तकनीक से बने हैं, जो इसके इस्तेमाल को काफी आसान बना देते हैं. इन पर चैटिंग के साथ-साथ आप बैकग्राउंड में अपनी पसंदीदा ट्यून का मज़ा भी ले सकते हैं. उक्त हैंडसेट प्री लोडेड साउंड के साथ भी उपलब्ध हैं. इनका एफएलएसी फॉर्मेट आपको उच्चतम ध्वनि का अहसास कराएगा. इसके अलावा इनमें ब्लूटुथ, स्टीरियो एवं एफएम जैसी ख़ूबियां भी मौजूद हैं. दोनों ही फोन आधुनिक तकनीक से बने हैं और इनमें कई ख़ूबियां हैं.

> सोनी एरिक्सन स्पायरो कंट्रास्ट ब्लैक, सनसेट पिंक, स्प्रिंग ग्रीन एवं स्टेल्थ ब्लैक जैसे आकर्षक रंगों में उपलब्ध है. इसमें 2.0 मेगा पिक्सल एवं डिजिटल जूम वाला कैमरा है. साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी.

सोनी एरिक्सन स्पायरो कंट्रास्ट ब्लैक, सनसेट पिंक, स्प्रिंग ग्रीन एवं स्टेल्थ ब्लैक जैसे आकर्षक रंगों में उपलब्ध है. इसमें 2.0 मेगा पिक्सल एवं डिजिटल जूम वाला कैमरा है. साथ ही वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा भी. यह ब्लूटुथ, स्टीरियो, एमएमएस, साउंड रिकॉर्डर, टच स्क्रीन, जावा एवं कैलकुलेटर जैसी ख़ूबियों से लैस है. इसका साइज़ 92/48/16.75 मिलीमीटर और वज़न 90 ग्राम है. इसका मेमोरी कार्ड 16 जीबी का है.

वहीं सोनी एरिक्सन जाइलो जाज ब्लैक, सिल्वर और स्विंग पिंक जैसे रंगों में उपलब्ध है. इसमें 3.2 मेगा पिक्सल और डिजिटल जूम वाला कैमरा है. साथ ही गूगल सर्च, फेसबुक, ट्विटर, वीडियो कॉलिंग, ईमेल, एमएमएस, साउंड रिकॉर्डिंग, पिक्चर वॉल पेपर, वॉल पेपर एनिमेशन, गेम्स, एफएम, जावा, यूट्यूब, कैलेंडर, टाइमर, गूगल मैप एवं ब्लूटुथ जैसी ढेर सारी ख़ूबियां भी मौजूद हैं.

तकनीक के नए रूप

लांच के मौके पर हायर एप्लायंसेज इंडिया के अध्यक्ष एरिक ब्रैगेंज़ा

होम एप्लायंसेज़ और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड हायर ने वर्ष 2010 के लिए नई योजनाओं का ख़ुलासा करते हुए रेफ्रिजरेशन एवं लॉन्ड्री एप्लायंसेज श्रेणी में अपनी स्थिति मज़बूत करने का ऐलान किया है. हायर ने अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजना के तहत रेफ्रिजरेशन एवं लॉन्ड्री एप्लायंसेज के 25 नए मॉडल पेश किए हैं. इनमें 1.2 इंच की चौड़ाई वाले अल्ट्रा स्लिम फुल एचडी एलईडी बैकलिट टीवी और मोशन गेमिंग टेक्नोलॉजी वाले एलसीडी टीवी की विस्तृत रेंज भी शामिल है. इसमें यूएसबी की मदद से किसी भी प्रोग्राम फीचर को रिकार्ड और प्ले किया जा सकता है. हायर एकमात्र ब्रांड है, जिसने 24 इंच का एलईडी टीवी मॉडल पेश किया है और जल्द ही यह 24 एवं 32 इंच के मॉडलों को लाने जा रहा है. कंपनी के एलसीडी टीवी 16 इंच से 42 इंच आकार में उपलब्ध हैं. कंपनी के बॉटम माउंटेड रेफ्रिजरेटर (बीएमआर) की नई रेंज-बीएमआर प्लस, एंप्रेस सीरीज़ रेफ्रिजरेटर के नए मॉडल, डीप फ्रीज़र, 5 स्टार स्प्लिट एसी और टॉप लोड वॉशिंग मशीनों की रेंज भी बाज़ार में हैं. हायर एप्लायंसेज इंडिया के अध्यक्ष एरिक ब्रैगेंज़ा कहते हैं कि कंपनी के एलईडी टीवी की नई रेंज भारतीय बाज़ार में निरंतर आविष्कार और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उत्पाद पेश करने के हमारे प्रयासों को दर्शाती है. आविष्कारिता, उपयोगिता, टिकाऊपन, पर्यावरण अनुकूलता और प्रयोग में आसान आदि ख़ूबियों को ध्यान में रखकर कंपनी ने उक्त अल्ट्रा स्लिम रेंज वाले एलईडी टीवी तैयार किए हैं. कंपनी भारतीय ग्राहकों के लिए 125 से अधिक एसकेयू उपलब्ध कराती है, जिन्हें उनकी ज़रूरतों और जीवन पद्धति को ध्यान में रखकर ख़ासतौर से डिज़ाइन किया गया है.

बाइक की मस्त राइड

भारत के बाइक लवर्स के लिए यामाहा इंडिया मोटर ने बिल्कुल नई और स्मार्ट मोटरसाइकिल वाईबीआर वन टेन (वाईबीआर-110) बाज़ार में उतारी है. यह मोटरसाइकिल ख़ासतौर से उन मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए बनाई गई है, जो रोज़ाना की ज़रूरत के लिए एक स्टाइलिश और सुविधाजनक सवारी चाहते हैं. लो एंड टॉर्क देने वाली एयरकूल फोर स्ट्रोक एसओएचसी इंजन के साथ वाईबीआर वन टेन बाइक में 4 स्पीड स्लिक गियर बॉक्स है. इससे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में बार-बार गियर बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं. चलाने में आसान इस बाइक में इलेक्ट्रिक स्टार्ट है. इसमें स्टाइलिश एवं चमकदार मल्टी रिफ्लेक्टर हेडलाइट भी है, जिससे रात के वक़्त बेहतर दिखाई देता है. वाईबीआर वन टेन में आधुनिक फिटिंग एवं फिनिशिंग के साथ आसान राइडिंग इंस्ट्रुमेंट कनसोल है. इसके ग्राफ़िक्स एवं ग्रैब रेल इसे स्पोर्टी लुक देते हैं. वाईबीआर वन टेन का सस्पेंशन भारतीय सड़कों के हिसाब से श्रेष्ठ है. इसका ट्विन क्रैडल डाउन ट्यूब टाइप फ्रेम काफी मज़बूत है.

यामाहा इंडिया मोटर के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक युकीमीने सूजी कहते हैं कि 150 सीसी सेगमेंट में अपनी मोटरसाइकिलों की सफलता के बाद कंपनी ने कंप्यूटर सेगमेंट के लिए वाईबीआर वन टेन मोटरसाइकिल प्रस्तुत की है, जो स्टाइलिश और ट्रेंडी है. यह बाइक दैनिक सफ़र के लिए काफ़ी सुविधाजनक है. वाईबीआर वन टेन की एक्स शोरूम क़ीमत 41 हज़ार रुपये है. यह मोटरसाइकिल तीन रंगों में उपलब्ध होगी, जिनमें काला, लाल एवं काला-लाल का संयोजित रूप शामिल है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कैमरा और डीवी कैमकार्डर की नई सीरीज़ को लांच करते कैनन इंडिया के प्रेसिडेंट एवं सीईओ केनसाकूकोनिशी

दिलचस्प फोटोग्राफी

बच्चों की परीक्षाएं ख़त्म होने वाली हैं और छुट्टियों का मौसम आने वाला है. घरों में लंबी यात्राओं पर जाने की तैयारियां होने लगी हैं. छुट्टियों के इस मौसम में घूमने-फिरने के हसीन पलों को क़ैद करने के लिए डिजिटल इमेजिंग कंपनी कैनन इंडिया ने अपने इमेजिंग कम्युनिकेशन प्रॉडक्ट डिवीज़न के लिए तकनीकी रूप से आधुनिक नई पीढ़ी के 20 नए कैमरों और डीवी कैमकार्डर की नई सीरीज़ बाज़ार में लाने की घोषणा की है. इसी क्रम में उसने अत्याधुनिक ख़ूबियों से भरपूर टच स्क्रीन कैनन आईएक्सयूएस-210 डिजिटल कैमरा लांच किया है. इसमें पावर शॉट सीरीज़ के अंतर्गत पांच, आईएक्सयूएस श्रेणी के तीन, हाई डेफिनिशन के छह एवं स्टैंडर्ड डेफिनिशन के दो कैमरे और बहुप्रतीक्षित ईओडी-550 डी डिजिटल एसएलआर, उच्च गुणवत्ता के तीन लेंस संस्करण एवं दो प्रो डीवी शामिल हैं.

इस अवसर पर कैनन इंडिया के प्रेसिडेंट एवं सीईओ केनसाकू कोनिशी ने कहा कि अत्याधुनिक, स्टाइलिश, ख़ूबसूरत एवं पेशेवर कैमरों और कैमकार्डरों की श्रेणी में श्रेष्ठ तकनीक से लैस लांच किए गए उत्पाद उपभोक्ताओं को उनके सर्वश्रेष्ठ पलों को तस्वीरों के रूप में संजोने के लिए प्रेरित करते हैं. इस श्रेणी के कैमरों का लुक और 3.5 इंच लंबी स्क्रीन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है. सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आलोक भारद्वाज कहते हैं कि कंपनी ने कैमरों में जो तकनीक इस्तेमाल की है, वह और भी आधुनिक एवं स्मार्ट हो गई है. स्मार्ट लेंस एक्सपोज़र और स्मार्ट शटर कैमरे के ऑटोमैटिक फंक्शन में नई ख़ूबियां जोड़ी गई हैं. एक बच्चा भी तस्वीर लेते समय फिश आई और ब्लर इफेक्ट खोलकर अच्छी फोटोग्राफी कर सकता है. उन्होंने कहा कि कैनन में वाइड एंगल एवं हाई ऑप्टिकल ज़ूम अत्याधुनिक तकनीक का है. इसका प्रोसेसर तेज़ है और इसमें हाई डेफिनिशन वीडियो बनाने की ख़ास ख़ूबियां हैं. इन उत्पादों की लांचिंग के साथ कंपनी के डिजिटल कैमरों, कैमकार्डरों, डी-एसएलआर और प्रो-डीवी के उत्पादों की संख्या बढ़कर 42 हो गई है.

लांच किए गए रोमांचकारी कैमकॉर्डर मॉडलों में एफएस-306, एचएफ-आर-16, एचएफ-आर-18, एचएफ-एम-300, एचएफ-एम-31, एचएफ-एस-200 एवं एचएफ- एस-21 आदि शामिल हैं, जिनमें एक बटन क्लिक करने से जीवंत घटनाएं असाधारण गुणवत्ता के साथ समेट लेने की ख़ूबियां हैं. कैनन ने दो प्रो-डीवी मॉडलों एक्सएफ-305 और एक्सएफ-300 भी लांच किए हैं. कंपनी का नवीनतम एफएस-305 अब तक का सबसे हल्का एवं सबसे छोटा डिजिटल कैमकार्डर है. कैनन आईएक्सयूएस-210 आधुनिक टच स्क्रीन तकनीक वाला है, जिसके 14 मेगा पिक्सल रिज़ॉल्यूशन से फोटो को पोस्टर साइज़ तक बड़ा किया जा सकता है. इन कैमरों की क़ीमत 6995 रुपये से शुरू होती है.

एक ख़ास टीवी

कितना अच्छा हो, अगर घर पर ही थिएटर का आनंद मिले. वैसे होम थिएटर ने इस अहसास को अब तक जीवंत किया है, पर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज कंपनी पैनासोनिक ने टीवी देखने का एक नया अनुभव पेश किया है. 50 इंच के फुल एचडी थ्री डी पीडीपी प्लाज़्मा टीवी लांच कर कंपनी ने लोगों को घर बैठे मूवी थिएटर के अनुभव का मौक़ा दिया है. युवाओं के स्टाइल आइकन बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर ने इस थिएटर एक्सपीरियंस प्रोडक्ट को लांच किया. बॉलीवुड में थ्री डी मूवीज़ का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, पर इस तरह की अच्छी क्वालिटी की मूवी का भरपूर आनंद तो उच्च तकनीक वाले टीवी से ही मिल सकता है. 50 इंच पीडीपी में पैनासोनिक ने थ्री डी ड्राइव तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो बिल्कुल साफ़ और सजीव तस्वीरें दिखाती है. इस टीवी में डराने वाली हॉरर फ़िल्में या टेली सीरियल देखना भी दिलचस्प होगा, क्योंकि ऐसे शो में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डबल और वाइब्रेशन इमेज इस टीवी में बिल्कुल साफ नज़र आती है. इसके एक्टिव शटर ग्लास तकनीक से हाई-क्वालिटी और हाई रिज़ोल्यूशन पिक्चर देखने का अनुभव भी मिलता है. इस टीवी में चलती हुई तस्वीरों में भी बढ़िया रिज़ोल्यूशन और कलर रि-प्रोडक्शन देखा जा सकता है. साथ ही इस ख़ास टीवी में ब्लू रे डिस्क प्लेयर्स भी हैं. इसके स्क्रीन ग्लास इतनी सावधानी से तैयार किए गए हैं कि ये बच्चों और बड़े-बूढ़ों दोनों की आंखों को सूट करते हैं और इनसे आंखें ख़राब होने की आशंका कम ही रहती है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

महिलाओं के वर्ग में सायना नेहवाल के अलावा केवल अदिति मुतातकर ही अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करने में कामयाब रहीं.

शायद ही इनका जलवा देखने को मिले

नए सीज़न में खिलाड़ियों की नए सिरे से ख़रीद-फरोख्त होगी और कुछ उम्र, कुछ ख़राब प्रदर्शन एवं कुछ इंज्युरी के चलते इन्हें लीग से बाहर रहना पड़ सकता है. और, शायद क्रिकेट के मैदान से भी...हमेशा के लिए...

आईपीएल का तीसरा सीज़न भी ख़त्म हो गया. पिछले दो सालों की तरह विवादों ने इस बार भी क्रिकेट और ग्लैमर के इस कॉकटेल का पीछा नहीं छोड़ा. तमाम तरह के आरोप-प्रत्यारोप लगे, एक केंद्रीय मंत्री को अपने पद से हाथ धोना पड़ा और इन सबके बीच थोड़ी देर के लिए ही सही, गेंद और बल्ले के बीच का यह मज़ेदार खेल पृष्ठभूमि में जाने को मजबूर हुआ. बंगलुरू में मैच से ठीक पहले हुए बम विस्फोट के बाद आतंक की काली छाया ने भी इसे अपने आगोश में लिया. एकबारगी तो लीग का भविष्य ही ख़तरे में पड़ता नज़र आने लगा. लेकिन इसमें कोई शक़ नहीं कि केवल तीन साल के अंदर क्रिकेट के खेल का चेहरा बदलने का दावा करने वाला यह टूर्नामेंट वापस लौटेगा. हां, नहीं लौटेंगे तो कुछ खिलाड़ी, जिन्हें हम सालों से क्रिकेट के मैदान पर अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए देखने के आदी हो चुके हैं. कभी गेंद और कभी बल्ले के साथ मैदान पर जलवे बिखेरने वाले इन जांबाज़ों को अब हम शायद फिर कभी ऐसा करते हुए नहीं देख पाएंगे.

मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट, मुथैया मुरलीधरन, शेनवार्न, सौरव गांगुली एवं हर्शेल गिब्स क्रिकेट के मैदान के कुछ ऐसे नाम हैं, जिन्होंने पिछले दो दशकों में अपने प्रदर्शनों से हमें न जाने कितनी बार वाह-वाह करने को मजबूर किया. क्रिकेट की किताब के न जाने कितने रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज़ हैं, लेकिन अब इन किताबों में शायद ही कोई नया अध्याय जुड़े. इनमें से अधिकतर ऐसे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही दूर हो चुके हैं. मैदान पर इन्हें देखते रहने का एकमात्र ज़रिया आईपीएल ही बचा था, लेकिन उम्र और परफॉरमेंस के हालिया स्तर को देखें तो ज़्यादा संभावना इसी बात की है कि लीग के अगले सीजन में इन्हें ख़रीदने के लिए शायद ही कोई तैयार हो.

आईपीएल के पहले सीज़न में विजेता रही राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान शेनवार्न इस साल सितंबर में 41 साल के हो जाएंगे. अरसा पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके वार्न की फिरकी का जादू अभी भी कमज़ोर नहीं हुआ, लेकिन उनकी उम्र एक बड़ी रुकावट है. हालांकि युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने की अपनी अनोखी क्षमता के बल पर वह कोच के रूप में अभी भी टीम के साथ जुड़े रह सकते हैं. वार्न की ही तरह डेक्कन चार्जर्स टीम को लीग के दूसरे सीज़न में खिताबी जीत दिलाने वाले एडम गिलक्रिस्ट की उम्र भी 38 साल से ज़्यादा हो चुकी है. फिर आईपीएल के तीसरे सीज़न में उनके बल्ले की धार भी कुंद होती दिखी. अक्सर अपनी आतिशी पारियों से टीम को मज़बूत शुरुआत देने में कामयाब रहने वाले गिलक्रिस्ट अपनी टीम से तो अच्छा प्रदर्शन कराने में कामयाब रहे, लेकिन ख़ुद उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. गिलक्रिस्ट की ही डेक्कन चार्जर्स टीम के लिए खेलने वाले दक्षिण अफ्रीका के हर्शेल गिब्स हालांकि अभी 37 साल के ही हैं, लेकिन लचर बल्लेबाज़ी के चलते उन्हें अगले साल टीम से बाहर होना पड़ सकता है. इस कड़ी में अगला नाम श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन का हो सकता है. टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेटों का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले मुरलीधरन अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए अभी भी खेलते हैं, लेकिन लीग के तीसरे सीज़न में उनका प्रदर्शन भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए शुरुआती मुक़ाबलों में तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बाद के मैचों में उनकी फिरकी का पैनापन लगातार मंद पड़ता गया और हालत यह हो गई कि आख़िरी कुछ मुक़ाबलों में उन्हें टीम से बाहर रहना पड़ा. कमोबेश यही हाल श्रीलंकाई टीम के एक और पूर्व खिलाड़ी सनत जयसूर्या का भी है. अपनी आक्रामक बल्लेबाज़ी से किसी भी मुक़ाबले का रुख़ बदलने का माद्दा रखने वाले जयसूर्या के प्रदर्शन में उम्र का असर साफ़ झलकता है. लीग के तीसरे सीज़न में उनका प्रदर्शन इतना ख़राब रहा कि मुंबई इंडियंस के शुरुआती कुछेक मुक़ाबलों के बाद उन्हें टीम में जगह नहीं मिली. वैसे भी जयसूर्या खेल के मैदान से राजनीति के रणक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हैं और अब उन्हें बल्लेबाज़ी करते हुए हम शायद ही देख पाएं.

शाहरुख ख़ान की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के कप्तान सौरव गांगुली का मामला थोड़ा अलग है. लीग के पहले दो सीज़न के मुक़ाबले इस बार का प्रदर्शन अच्छा था और यदि क़िस्मत ने साथ दिया होता तो टीम सेमी फाइनल में जगह बना सकती थी. ख़ुद गांगुली ने अपनी बल्लेबाज़ी के दम पर कई बार टीम की जीत का रास्ता तैयार किया, लेकिन लगातार तीन सालों की असफलता के बाद टीम के मालिक नए सीज़न में नए खिलाड़ियों को मौक़ा देने का फ़ैसला ले सकते हैं. अब इसमें गांगुली के लिए जगह कहां बनती है, यह देखना रोचक होगा.

इसके अलावा एंड्रयू सायमंड्स, डेमियन मार्टिन, एंड्रयू फ्लिंटॉफ जैसे कुछ और नाम हैं, जिन्हें आईपीएल के अगले सीज़न में ख़रीदार मिलना मुश्किल हो सकता है. इसकी संभावना इसलिए ज़्यादा है, क्योंकि नए सीज़न में खिलाड़ियों की नए सिरे से ख़रीद-फरोख्त होगी और कुछ उम्र, कुछ ख़राब प्रदर्शन एवं कुछ इंज्युरी के चलते इन्हें लीग से बाहर रहना पड़ सकता है. और, शायद क्रिकेट के मैदान से भी...हमेशा के लिए...

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप
भारतीय खिलाड़ियों का जादू नहीं चला

बीते 12-18 अप्रैल के बीच नई दिल्ली के सिरीफोर्ट स्टेडियम में खेली गई एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को एक बार फिर निराशा ही हाथ लगी. देश की सरजमीं पर आयोजित हुए इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन वे खरे उतरने में नाकाम रहे. महिलाओं के सिंगल्स मुक़ाबलों के लिए शीर्ष वरीयता प्राप्त सानिया नेहवाल ने सेमी फाइनल तक का सफर तय किया तो खिताबी जीत की आस बंधी, लेकिन सेमी फाइनल में उन्हें जेरुन ली के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा और भारत की सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं. सायना के लिए मौक़ा अच्छा था, क्योंकि विश्व रैंकिंग में शीर्ष पांच स्थानों पर क़ाबिज़ महिला खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले रही थीं.

टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारतीय कोच पुलेला गोपीचंद ने दावा किया था कि भारतीय खिलाड़ी इस बार कुछ कमाल कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा उम्मीदें सायना और मिक्स्ड डबल्स में ज्वाला गट्टा एवं वी दीजू की जोड़ी से थीं, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद सारे खिलाड़ी लड़खड़ा गए और खिताबी दौड़ से बाहर हो गए. हालांकि महिलाओं से ज़्यादा पुरुष खिलाड़ियों ने निराश किया. टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले चोट के कारण अपना नाम वापस लेने को मजबूर हुए चेतन आनंद के बाद सारा दारोमदार अरविंद भट्ट, अनूप श्रीधर, पी कश्यप एवं आनंद पवार पर था, लेकिन कश्यप के अलावा कोई भी खिलाड़ी अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाया. अरविंद भट्ट, अनूप श्रीधर, आरएमवी गुरुसाइदत्त, अजय जयराम एवं के नंदगोपाल जैसे खिलाड़ी चीन और कोरियाई खिलाड़ियों के सामने पूरी तरह बेबस दिखे.

महिलाओं के वर्ग में सायना नेहवाल के अलावा केवल अदिति मुतातकर ही अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन करने में कामयाब रहीं. पहले दो मुक़ाबलों में बेहतरीन जीत हासिल करने के बाद अदिति तीसरे मुक़ाबले में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हुईं. जबकि तृप्ति मुरगुंडे, नेहा पंडित एवं सयाली गोखले पहले राउंड में ही बाहर हो चुकी थीं.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया
दिल्ली, 03 मई–09 मई 2010

जब विजय माल्या अपनी व्यस्त दिनचर्या से वक़्त निकाल कर टीम का मैच देखने आ सकते हैं तो कैटरीना क्यों नहीं?

अच्छे लोगों का साथ ज़रूरी है : फेरेना वजीर

मेरे लिए यह अनुभव बहुत ख़ास था. मैं जिन अभिनेत्रियों की फ़िल्में देखकर बड़ी हुई थी, उनके साथ काम करना मेरे लिए बेहद आश्चर्यजनक था. नई अभिनेत्री होने के नाते सबका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा रहा.

फ़िल्म *सदियां* से एक और विदेशी बाला ने बॉलीवुड में अपने क़दम रखे हैं. नाम है फेरेना वजीर. स्कॉटलैंड में जन्मी एवं लंदन में पली-बढ़ी फेरेना *सदियां* में बतौर हीरोइन नज़र आईं. इसमें शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा उनके अपोजिट थे. वह केतन मेहता की बहुचर्चित फ़िल्म *रंग रसिया* में भी नज़र आएंगी. पिछले दिनों फेरेना ने **चौथी दुनिया** की संवाददाता **रीतिका सोनाली** से लंबी बातचीत की. पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश:

आपका जन्म कहां हुआ, परिवार में कौन-कौन है और शिक्षा-दीक्षा कहां हुई?

मेरा जन्म स्कॉटलैंड में हुआ. मेरे माता-पिता मूल रूप से लोहरीन (कश्मीर) के निवासी हैं. मैंने अपनी पढ़ाई स्कॉटलैंड एवं लंदन में पूरी की.

आपने बतौर करियर अभिनय का क्षेत्र ही क्यों चुना और पहला ब्रेक कब मिला?

जब मैं लंदन में थी, तभी मुझे उर्दू और पंजाबी में थिएटर और वॉयसओवर के ऑफर मिलने लगे थे. उसके बाद कम्युनिटी थिएटर का ऑफर मिला. तब मैं पॉकेटमनी और एक्टिंग का पैशन बरक़रार रखने के उद्देश्य से यह काम करती थी. जब मैं छुट्टियों में भारत आई, उस दौरान एक फोटोग्राफर से मिली. उसने मुझे इंडस्ट्री के कुछ लोगों से मिलाया, इस तरह पहचान बढ़ती गई और आज मैं यहां हूं.

अभिनय के अलावा आपकी कोई और हॉबी, जैसे समाजसेवा या कुछ और?

मैं इस बात में विश्वास करती हूं कि आपसे सोसाइटी को अवश्य कुछ न कुछ मिलना चाहिए. समाजसेवा में मेरी शुरू से रुचि रही है. उसी से प्रेरित होकर मैंने साउथ अफ़्रीका में समाजसेवा प्रोजेक्ट पर काम भी किया.

एक नए कलाकार के रूप में आपने इंडस्ट्री के लोगों और माहौल के बारे में कैसा महसूस किया?

जब आप इंडस्ट्री में बहुत तरह के लोगों से मिलते हैं तो उनमें कुछ अच्छे तो कुछ अजीब किस्म के होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमेशा अच्छे और ऊर्जावान लोगों के आसपास रहें.

इंडस्ट्री में वे ख़ास लोग कौन हैं, जिनके साथ आप काम करने की इच्छुक हैं?

मैं विधु विनोद चोपड़ा एवं राजकुमार हिरानी से बेहद प्रभावित हूं और भविष्य में उनके साथ काम भी करना चाहती हूं.

बॉलीवुड के साथ-साथ क्या क्षेत्रीय फ़िल्मों में भी काम करना चाहेंगी?

हां, अगर मुझे मौक़ा मिला तो मैं क्षेत्रीय फ़िल्में भी अवश्य करूंगी.

फ़िल्म सदियां में आपने रेखा और हेमामालिनी जैसी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ काम किया. कैसा रहा अनुभव?

मेरे लिए यह अनुभव बहुत ख़ास था. मैं जिन अभिनेत्रियों की फ़िल्में देखकर बड़ी हुई थी, उनके साथ काम करना मेरे लिए बेहद आश्चर्यजनक था. नई अभिनेत्री होने के नाते सबका व्यवहार मेरे प्रति बहुत अच्छा रहा.

अपनी आने वाली फ़िल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगी?

केतन मेहता के निर्देशन में मेरी अगली फ़िल्म *रंग रसिया* जल्द ही रिलीज़ होने वाली है. यह राजा रवि वर्मा पर आधारित है.

कोएना का प्रवचन

कोएना मित्रा आजकल स्क्रीन से ग़ायब हो गई हैं, न जाने वह किधर हैं और क्या कर रही हैं. पिछले दिनों पता चला था कि वह छुट्टियां मनाने टर्की गई थीं, जिसके लिए वह काफी एक्साइटेड थीं. पर अब कहां हैं बंगाली बाला? लैटिन डांस, स्ट्रीट हिप-हॉप डांस एवं एक्शन ट्रेनिंग आदि करने के बाद भी उन्हें इन दिनों न किसी टीवी डांस शो में देखा जा रहा है और न किसी एक्शन लाइव शो या विज्ञापन में. फ़िल्मों से तो वह जैसे ग़ायब ही हो गई हैं. लगभग तेरह फ़िल्मों में छोटी-बड़ी भूमिकाएं निभाने के बावजूद बॉलीवुड में उनकी स्थिति अच्छी नहीं बन पाई. अनिल कपूर एवं सलमान ख़ान के साइकिल प्रेम के बाद पिछले वर्ष कोएना ने भी इंपोर्टेड साइकिल की सवारी करके मीडिया में धूम मचाई और फिर वह गुमनाम हो गईं. हालांकि बार-बार यह पूछे जाने पर कि वह क्या कर रही हैं, आजकल फ़िल्मों में क्यों नहीं नज़र आ रही हैं, खाली बैठी एक्ट्रेस की तरह उनका जवाब होता है कि कुछ स्क्रिप्ट्स पर काम चल रहा है. चलिए, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वह अपनी अगली फ़िल्मों की तैयारी कर रही होंगी, पर आजकल वह किन चीज़ों से अपना मन बहला रही हैं, इसका जवाब मुश्किल है. लेकिन, आजकल वह लोगों को उपदेश देने का काम कर रही हैं. नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर वह अपने प्रशंसकों को जीने का सलीका सिखा रही हैं और प्रवचन दे रही हैं. कभी वह लाफ्टर थेरेपी के बारे में बताती हैं तो कभी अध्यात्म के बारे में. वैसे अच्छा है, अपने काम के ज़रिए न सही, प्रवचन के ज़रिए तो प्रशंसकों के क़रीब रह सकेंगी कोएना. आश्चर्य की बात नहीं, अगर वह आपको आने वाले दिनों में किसी ज्ञान शिविर में दिख जाएं.

क्रिकेटर कैटरीना

बॉलीवुड में टॉप पर चल रही कैटरीना कैफ इन दिनों भारतीय क्रिकेट फीवर इंडियन प्रीमियर लीग में विजय माल्या की टीम रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की ब्रांड एंबेसडर हैं. पिछले तीन सालों से वह इस टीम के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करती आ रही हैं. इस बार भी, चाहे वह किसी फ़िल्म की शूटिंग में कितनी भी व्यस्त क्यों न हों, पर वक़्त निकाल कर अपनी टीम का मैच देखने ज़रूर पहुंच जाती हैं. कैटरीना कहती हैं कि ब्रांड एंबेसडर होने के नाते उनका फ़र्ज़ है कि वह अपनी टीम का हौसला बढ़ाने ज़रूर आएं. जब विजय माल्या अपनी व्यस्त दिनचर्या से वक़्त निकाल कर टीम का मैच देखने आ सकते हैं तो वह क्यों नहीं? यानी उन्हें यहां आने की प्रेरणा टीम के मालिक विजय माल्या से मिलती है. वह कहती हैं कि जब आप दिल से कुछ करना चाहें तो उस काम के लिए वक्त आसानी से निकल आता है. वह न सिर्फ़ क्रिकेट पसंद करती हैं, बल्कि क्रिकेटर बनना भी चाहती थीं. कैटरीना बताती हैं कि अगर वह बॉलीवुड में नहीं होतीं तो शायद क्रिकेटर होतीं. उसमें भी वह बैटिंग ही करतीं. भारत आने से पहले जब वह लंदन में थीं तो उनकी पसंदीदा टीम वेस्टइंडीज थी, पर अब उनकी पसंदीदा टीम आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स है और अंतरराष्ट्रीय खेल में भारत. कैटरीना बताती हैं कि आईपीएल से जुड़ने के बाद क्रिकेट में उनके ज्ञान और रुचि दोनों में वृद्धि हुई है. जब भी उन्हें शूटिंग के दौरान थोड़ा-बहुत समय मिलता है, तब वह क्रिकेट खेलती हैं और वहां भी बैटिंग ही करती हैं.

फिल्म रिव्यू

फुंक गई फूंक-2

रामगोपाल वर्मा की आग उनकी ही फ़िल्मों फूंक और फूंक-2 ने बुझा दी है. फ़िल्म फूंक के बॉक्स ऑफिस पर पिटने के बाद भी रामगोपाल वर्मा ने उसी का सीक्वल फूंक-2 बनाई और रिलीज़ की. यह पूछे जाने पर कि उन्होंने फूंक-2 क्यों बनाई? उनका जवाब था कि उन्होंने फ़िल्म अपने लिए बनाई है. पर अपने लिए बनाई गई फ़िल्म उन्होंने दर्शकों के लिए रिलीज़ क्यों की, मन में यह सवाल फ़िल्म देखने के बाद उठता है. कमज़ोर स्क्रिप्ट पर बनाई गई बेकार विजुअल ट्रीटमेंट की फ़िल्म फूंक-2 में देखने लायक़ कुछ भी नहीं है. फूंक-2 से पहले आई फ़िल्म फूंक की अगली कड़ी के रूप में इसे देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. रामगोपाल वर्मा की यह फ़िल्म लोगों को डराने के लिए हॉरर जॉनर बताई गई थी, मगर डरना तो दूर, फ़िल्म के कई दृश्य देखकर हंसी आती है. कहानी की कड़ियां इस तरह जोड़ी गई हैं कि उनका किरदार और दृश्य से कोई वास्ता नहीं दिखता. पूरी फ़िल्म में भूत का अपीयरेंस लगभग शून्य है. फ़िल्म सिवाय लोकेशन और कुछ नहीं दिखाती. कलाकारों ने मेहनत की है, मगर बच्ची (एहसास छन्ना) के किरदार को देखकर लगता है, जैसे उसे बेवजह डरने की ट्रेनिंग दी गई हो. सभी किरदार फ़िल्म की शुरुआत से ही सभी दृश्यों में यह अनुमान लगा लेते हैं कि उनके साथ होने वाली अनजानी घटनाएं भूत द्वारा ही होती हैं. ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से पता है कि एक भूत आने वाला है और उन्हें तंग करने वाला है. हद तो तब हो गई, जब फ़िल्म के अंत तक यह पता नहीं चल सका कि भूत कौन है, क्यों है और है भी या नहीं. दरअसल यह भूत पहले आई फ़िल्म फूंक में मरने वाली मधु का होता है, पर इस सीक्वल में उस किरदार का कुछ अता-पता नहीं हैं. यानी फूंक-2 देखने वालों के लिए फूंक देखना ज़रूरी है. फ़िल्म में सबसे अच्छा विजुअल ट्रीटमेंट आख़िरी दस मिनट के दृश्य में दिया गया है, जो बेहद भावनात्मक और दिल को छू लेने वाला है. लगता है, रामगोपाल वर्मा को हॉरर छोड़ कर अब इमोशनल फ़िल्में बनाने के बारे में सोचना चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 03 मई–09 मई 2010

www.chauthiduniya.com

धमासान

सरोज सिंह

बात ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अभी तो शुरू हुई है. मेरे ख़िलाफ़ लिखना मना है शीर्षक से छपी ख़बर के बाद सूबे का सियासी पारा अचानक काफी चढ़ गया है. नेताओं को यह यकीन ही नहीं हुआ कि बिहार में कोई अख़बार इस तरह की ख़बरें छापने का साहस कर सकता है, लेकिन सच के सामने आते ही कोई बेचैन है तो कोई गला फाड़-फाड़कर कह रहा है कि देखो, मैं कहता था न कि सरकारी दबाव ने सच पर पहरा लगा दिया है, लेकिन चौथी दुनिया ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया. सत्तापक्ष हो या विपक्ष, दोनों तरफ से बात कही जा रही है और हम दोनों का स्वागत करते हैं, क्योंकि चौथी दुनिया की यह पक्की समझ है कि जिस राज्य में लोकतंत्र ने जन्म लिया हो और जिस देश में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र फल-फूल रहा हो, वहां विचारों पर बंधन बेमानी है. सियासी दुनिया से बाहर समाज के अलग-अलग तबकों ने भी चौथी दुनिया की पहल पर अपनी बेबाक राय रखी और देश से बाहर रहने वाले बिहारियों ने भी अपनी भावनाओं से हमें अवगत कराया है. देखें तो देश-दुनिया में एक बेहद गंभीर एवं संवेदनशील मुद्दे पर बहस छिड़ गई है. इस लेख में हमारी कोशिश कुछ इन्हीं विचारों एवं भावनाओं को आप तक पहुंचाना है.

बात सत्ताधारी एनडीए के नेताओं से ही शुरू करते हैं. जदयू के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी कहते हैं कि अख़बारों में सरकार की तारीफ़ इसलिए हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह राज्य रोज विकास का नया इतिहास लिख रहा है. विज्ञापन देने या न देने से इसका कोई नाता नहीं है. विपक्ष हताश है, इसलिए उसे लगता है कि पक्षपात हो रहा है. विपक्ष कुछ कर ही नहीं रहा है तो उसकी बातों को अख़बार वाले कैसे छापेंगे. चौधरी कहते हैं कि दुनिया भर के लोग बिहार आकर सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं. उन पर तो कोई दबाव नहीं है. जदयू के प्रवक्ता श्याम रजक विपक्ष को कुंठाग्रस्त बताते हुए कहते हैं कि वे सोए हुए हैं तो अख़बार वाले क्या करेंगे. इतने सालों में विपक्ष ने कोई बड़ा आंदोलन छेड़ा है क्या? दरअसल सरकार की उपलब्धियों को कुछ विपक्षी नेता पचा नहीं पा रहे हैं और दोष सरकार एवं मीडिया पर मढ़ रहे हैं. बिहार में मीडिया पूरी तरह आज़ाद है और अपना दायित्व निभा रहा है. जदयू नेता एवं विधान पार्षद शिवप्रसन्न यादव की राय है कि मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप जैसी कोई बात नहीं है. चुनाव में अपनी संभावित हार देख विपक्षी नेताओं के होश उड़ गए हैं. इसलिए वे यह आरोप लगा रहे हैं कि मीडिया पर दबाव बनाकर सरकार का गुणगान कराया जा रहा है. भाजपा नेता संजय मयूख का कहना है कि बिहार में विपक्ष को सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य नजर नहीं आते. भाजपा-जदयू गठबंधन की सरकार ने राज्य में एक अलग कार्य संस्कृति को जन्म दिया, जिसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है. मीडिया अपना दायित्व बखूबी निभा रहा है और दबाव जैसी कोई बात नहीं है. जदयू नेता सतीश यादव का कहना है कि नीतीश कुमार ने विकास की जो रेखा खींच दी है, उसे देखकर विपक्ष के पैरों तले ज़मीन खिसक रही है. अब विकास ज़्यादा हो रहा है तो इसमें मीडिया का क्या दोष? लेकिन विपक्षी दल के नेता कुछ सुनने को तैयार नहीं हैं. उनका साफ़ कहना है कि विकास हुआ नहीं, पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है. इन नेताओं का आरोप है कि नीतीश सरकार ने मीडिया पर दबाव की जो ग़लत परंपरा शुरू की है, उससे लोकतंत्र को गंभीर ख़तरा है. राजद प्रमुख लालू प्रसाद कहते हैं कि नीतीश कुमार का इतना दबाव मीडिया पर है कि ग़रीबों की आवाज़ सामने नहीं आ पा रही है. गरीबों को न राशन मिल रहा है और न ही किरासन. बिजली और पानी की बात तो छोड़ ही दीजिए. नक्सलियों का प्रभाव रोज़ बढ़ रहा है और अख़बारों के माध्यम से सरकार कहती है कि सब कुछ नियंत्रण में है. चौथी दुनिया की तारीफ़ करते हुए लालू प्रसाद ने कहा कि इस अख़बार ने सच को सामने लाने का काम किया है. लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान कहते हैं कि झूठ की बुनियाद पर टिकी यह सरकार अब जाने ही वाली है. पासवान ने कहा कि जनता के पैसे से अपनी छवि चमकाने वाले नेता जल्द ही यह महसूस करेंगे कि जनता उन्हें नकार चुकी है. उन्होंने कहा कि मीडिया को पूरी आज़ादी से अपना काम करने देना चाहिए, ताकि कहीं कुछ ग़लत हो रहा है तो वह सबके सामने आ सके. राजद के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव की राय है कि अगर नीतीश कुमार ने अपना रवैया नहीं बदला तो पूरी दुनिया के सामने बिहार का सिर शर्म से झुक जाएगा. उन्होंने कहा कि मीडिया पर दबाव बनाकर नीतीश कुमार लोकतंत्र की हत्या करने का अपराध कर रहे हैं. जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो फिर कौन बचेगा? उन्होंने कहा कि जल्द ही जनता इस विज्ञापनी सरकार को उखाड़ फेंकेगी. राजद नेता छोटू सिंह एवं शक्ति सिंह ने कहा कि पत्रकार भाइयों पर से अगर दबाव नहीं हटाया गया तो नीतीश सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा. विधान पार्षद रोमा भारती के अनुसार, मीडिया पर दबाव लोकतंत्र के लिए गंभीर ख़तरा है. सभी संस्थाओं को पूरी ईमानदारी एवं आज़ादी से अपना काम करने देना चाहिए. एनसीपी के तारिक अनवर भी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में मीडिया पर दबाव है. उनका कहना है कि विज्ञापन का डर दिखाकर ज़मीनी सच्चाई को छिपाया जा रहा है, लेकिन सच पर ज़्यादा देर तक पहरा नहीं लगाया जा सकता है. विकास के ग़लत आंकड़े देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास जारी है, पर इतना तय है कि पाप का घड़ा ज़रूर फूटेगा. लोकमोर्चा के शंभू श्रीवास्तव मानते हैं कि बिहार में मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध है. उनकी राय में नीतीश सरकार ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है. न केवल मीडिया, बल्कि जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन्हें कमज़ोर करने का काम चल रहा है. नीतीश कुमार आलोचनाओं से घबराने लगे हैं. उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो व्यक्ति आलोचना नहीं सुन सकता, वह जनता का व्यक्ति नहीं हो सकता है. इन्हीं वजहों से नीतीश कुमार बिहार का काफी नुक़सान कर रहे हैं. कांग्रेस के समीर सिंह कहते हैं कि बिहार की छवि की क़ीमत पर नीतीश कुमार अपनी छवि चमकाने में लगे हैं. प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती पकड़ से घबरा कर मीडिया पर दबाव डाल सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है. चौथी दुनिया में ख़बर छपने के बाद पत्रकारों का भी एक बड़ा तबका यह महसूस करने लगा है कि चाहे वजह जो भी हो, पर अपना पत्रकारिता धर्म निभाने में कहीं न कहीं चूक ज़रूर हो रही है. पढ़ा-लिखा समाज पत्रकारिता की नई परिभाषा गढ़ने लगा है और यह समझने की कोशिश कर रहा है कि विज्ञापन के इस दौर में सरकार और पत्रकार के बीच खींची गई रेखा कहीं हमेशा के लिए तो नहीं मिट जाएगी. यह बहस अभी शुरू हुई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि निष्कर्ष निकलने तक जारी रहेगी, ताकि लोकतंत्र में मीडिया पूरी ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह कर सके और आगे कोई यह न कह सके कि मेरे ख़िलाफ़ लिखना मना है.

feedback@chauthiduniya.com

नीतीश कुमार का मीडिया पर इतना दबाव है कि ग़रीबों की आवाज़ सामने नहीं आ पा रही है. ग़रीबों को न राशन मिल रहा है और न ही किरासन.

लालू प्रसाद

झूठ की बुनियाद पर टिकी यह सरकार अब जाने ही वाली है. जनता के पैसे से अपनी छवि चमकाने वाले नेता जल्द ही यह महसूस करेंगे कि जनता उन्हें नकार चुकी है.

राम विलास पासवान

मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप जैसी कोई बात नहीं है. चुनाव में अपनी संभावित हार देख विपक्षी नेताओं के होश उड़ गए हैं.

शिवप्रसन्न यादव

बिहार में मीडिया पर दबाव है. विज्ञापन का डर दिखाकर ज़मीनी सच्चाई को छिपाया जा रहा है, लेकिन सच पर ज़्यादा देर तक पहरा नहीं लगाया जा सकता है.

तारिक अनवर

अख़बारों में सरकार की तारीफ़ इसलिए हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यह राज्य रोज़ विकास का नया इतिहास लिख रहा है.

विजय कुमार चौधरी

अगर नीतीश कुमार ने अपना रवैया नहीं बदला तो पूरी दुनिया के सामने बिहार का सिर शर्म से झुक जाएगा. मीडिया पर दबाव बनाकर वह लोकतंत्र की हत्या करने का अपराध कर रहे हैं.

रामकृपाल यादव

विपक्ष को सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य नज़र नहीं आते. भाजपा-जदयू गठबंधन की सरकार ने राज्य में एक अलग कार्य संस्कृति को जन्म दिया, जिसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है.

संजय मयूख

विपक्ष कुंठाग्रस्त है. वह सोए हुए हैं तो अखबार वाले क्या करेंगे. इतने सालों में विपक्ष ने कोई बड़ा आंदोलन छेड़ा है क्या? सरकार की उपलब्धियों को कुछ विपक्षी नेता पचा नहीं पा रहे हैं.

श्याम रजक

बिहार में मीडिया पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा है. मेरा मानना है कि नीतीश सरकार खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है.

शंभू श्रीवास्तव

बिहार की छवि की क़ीमत पर नीतीश कुमार अपनी छवि चमकाने में लगे हैं. प्रदेश में कांग्रेस की बढ़ती पकड़ से घबरा कर मीडिया पर दबाव डालकर सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है.

समीर सिंह

महापंचायत में दिग्विजय सिंह ने साफ़ कहा है कि किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है.

दलित बस्तियों में भ्रमण के दौरान लोगों ने चौथी दुनिया को बताया कि उन्हें एक घूंट ठंढा पानी के लिए इधर–उधर भटकना पड़ता है.

टिकट के लिए माथापच्ची

बायसी विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सुगबुगाहट तेज़ हो गई है. टिकट लेने के लिए अभी से ही माथापच्ची शुरू हो चुकी है. इस होड़ में जीते हुए उम्मीदवार से लेकर हारने वाले उम्मीदवार तक शामिल हैं. इस क्षेत्र के विधायक रुकनुद्दीन के साथ–साथ पिछले विधानसभा चुनाव में पराजय का मुंह देखने वालों एवं चुनाव लड़ने की मंशा पालने वालों की बेचैनी बढ़ गई है. नए परिसीमन के बाद क्षेत्र का समीकरण कुछ उलझता नज़र आ रहा है.

हर दल से नए एवं पिछली बार हारे प्रत्याशी, टिकट पाने की जुगाड़ में अपने चहेते नेताओं के दरबार में पहुंचने लगे हैं. जहां उन्हें आश्वासन तो मिलता है, फिर भी वे आश्वस्त नहीं हैं. कुछ ऐसे नेता भी हैं, जो टिकट नहीं मिलने की स्थिति में दूसरे दलों का दामन थाम लेंगे या बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने से गुरेज़ नहीं करेंगे. अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, जिससे क्षेत्र में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है और अंदर ही अंदर नेताओं के आपसी संबंधों में खटास आने लगी है. वर्तमान विधायक रुकनुद्दीन ने पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता था. इस चुनाव में उन्होंने राजद के हाज़ी सुवहान को हराया था.

विधानसभा क्षेत्र बायसी

बायसी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से टिकट चाहने वालों की इस बार लंबी फ़ेहरिस्त है. इनमें मो.शमीम, निसार अहमद, हाज़ी तौसिफ़, मो.इसराइल आज़ाद, ख्वाज़ा ग़रीब नवाज़ आदि शामिल हैं. जद (यू) के प्रत्याशी मो.इसराइल आज़ाद वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में लगभग ढाई हज़ार मतों के अंतर से राजद प्रत्याशी हाज़ी सुवहान से हारे थे. कल्हैया बिरादरी से आने वाले आज़ाद ने कांग्रेस के वर्तमान लोकसभा सांसद मौलाना असरारूल हक़ का साथ दिया था. वैसे भी इस क्षेत्र की जनता का मानना है कि आज़ाद साहब एक अच्छे वक्ता, बेदाग़ छवि वाले और निर्विवाद रूप से अपनी बातों को रखने वालों में से हैं. बायसी के सुरजापुरी बिरादरी से आने वाले नेता मो.शमीम भी कांग्रेस से टिकट पाने की जुगत में हैं. मो.निसार अहमद व्यवसायी हैं और वह भी यहां से कांग्रेस से टिकट पाने को लेकर ताल ठोंक रहे हैं. वैसे निसार इस बात पर भी अड़े हैं कि अगर उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं. वहीं चड़ैया के हाज़ी मो.तौसीफ उर्फ़ कुरवा भी अपने आप को कांग्रेस का सच्चा सिपाही बताते हैं. उनका मानना है कि वह वर्तमान सांसद एवं आलाकमान के पसंदीदा उम्मीदवार हैं, इसीलिए टिकट तो उन्हीं को मिलेगा. दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो युवा भाजपा नेता संतोष कुशवाहा प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. संतोष इस उम्मीद में हैं कि अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ तो हिन्दू वोट तो उन्हीं को मिलना है. अगर राजद एवं लोजपा में तालमेल हुआ तो पूर्व पुनर्वास मंत्री हाज़ी सुवहान को राजद से टिकट मिलना तय है. पूर्व मंत्री एवं तीन बार विधायक रहे हाज़ी सुवहान का दावा है कि इस क्षेत्र के मतदाताओं पर उनकी बेहतर पकड़ है. वैसे राजद एवं लोजपा से टिकट की चाह रखने वालों की भी लंबी कतार है. ग़ौरतलब है कि टिकट की मगजमारी भरी इस खेल में विभिन्न दलों के सभी इच्छुक उम्मीदवार खुश हो सकें, ऐसा नहीं हो सकता. अलग–अलग पार्टी अपने किसी एक उम्मीदवार को ही टिकट देकर खुश कर सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न दलों के बीच चुनाव से पहले टिकट पाने के इस खेल में बाजी कौन मारता है.

मोहम्मद इसराइल आज़ाद

हाज़ी सुवहान

मोहम्मद शमीम

हाज़ी तौसिफ़

संतोष कुशवाहा

मोहम्मद निसार अहमद

वीरेन्द्र कुमार सिंह
feedback@chauthidunya.com

अधर में लटकी जलाशय परियोजना

दे वघर ज़िले में चल रही दो बड़ी बहुप्रतीक्षित एवं बहुचर्चित जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य अनियमितता, भ्रष्टाचार, लापरवाही एवं राजनीतिक दावपेंच के चंगुल में फंस कर रह गया है. दोनों ही जलाशय परियोजनाओं पर अब तक अरबों रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं. फिर भी निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हुआ है. यह निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई प्रमंडल देवघर द्वारा किया जा रहा है. पुनासी जलाशय परियोजना का निर्माण कार्य 1977 में शुरू हुआ. इसकी अनुमानित लागत 56 करोड़ रुपये थी. 33 वर्ष बीतने के बाद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है. अब तक इस पर 117 करोड़ रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं. ग़ौरतलब है कि योजना राशि में चार बार संशोधन कर कुल अनुमानित राशि को बढ़ाकर 482 करोड़ रुपये कर दिया गया, फिर भी निर्माण कार्य अधूरा है.

सच तो यह है कि जो भी थोड़ा बहुत काम पहले हुआ था, वह भी ध्वस्त होने लगा है. इस योजना को पूरा करने में चार प्रमंडलीय एवं एक सर्किल कार्यालय कार्यरत हैं, जहां 200 कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों पर लगभग 35 लाख रुपये प्रतिमाह ख़र्च हो रहे हैं. सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अमरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार 2007–08 से आवंटन बंद है, जिसके कारण काम ठप है. पदाधिकारी एवं कर्मचारी सिर्फ़ अपनी उपस्थिति दर्ज़ करा रहे हैं. इस स्थिति में आश्चर्य वाली बात यह है कि परियोजना के कार्य हेतु स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो से विशेष गुणवत्ता वाली 700 मीट्रिक टन छड़ मंगवाई गई थी, जिसमें जंग लग रहा है. इसे बचाने की कोशिश नहीं की गई. छड़ की वर्तमान स्थिति के बारे में अभियंताओं कहना है कि छड़ परियोजना में लगने लायक नहीं रह गई है. इसकी नीलामी ही करनी होगी ताकि विभाग को बची–खुची राशि मिल सके. अभियंता के अनुसार विभागीय आलाधिकारियों को नीलामी हेतु पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है.

विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण आज सरकार को करोड़ों रुपये का नुक़सान हो रहा है, जिसे रोकने अथवा बचाने हेतु स्थानीय राजनीतिज्ञों ने भी कोई दिलचस्पी नहीं ली. वहीं दूसरी ओर, इस पर राजनितिक रोटियां ख़ूब सेंकी गईं. देवघर के ऐक चर्चित नेता, जिनका निवास स्थान परियोजना क्षेत्र के निकट है, इस परियोजना में उनकी भूमिका भी काफ़ी सक्रिय रही है. पिछले दो दशकों से उनकी राजनितिक धुरी पुनासी जलाशय परियोजना ही रही है. योजना हेतु अधिगृहीत ज़मीनों के विस्थापितों को मुआवजा का मामला उनका राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है. विभागीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 450 विस्थापितों को मुआवजे की राशि का भुगतान किया जा चुका है और 302 लोगों को भुगतान किया जाना है. दूसरी ओर ग्रामीणों की सूची में काफ़ी अंतर है तथा मुआवजे की राशि 10 लाख करने की मांग भी विवाद का कारण बनी हुई है, जिसके कारण ग्रामीण काम में बाधा उत्पन्न करते हैं. राज्य के मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन आज तक इस दिशा में सार्थक पहल नहीं हो पाई है. हालांकि उक्त चर्चित राजनीतिज्ञ हमेशा ही बैठकों व सभाओं में पुनासी जलाशय परियोजना को पूरा होने की बात करते हैं. मगर, सच्चाई जनता के सामने है. पिछले दो दशकों से देवघरवासियों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है और ज़िला प्रशासन पेयजल समस्या का समाधान करने में नाकाम साबित हो रहा है. पूरे इलाक़े का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है. पुनासी जलाशय योजना से ही पेयजल आपूर्ति कर शहर को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध किया जा सकता है. साथ ही आसपास के क्षेत्रों में कृषि हेतु सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी. वर्तमान हालातों में दूर–दूर तक इन समस्याओं का हल होता नहीं दिखता. दूसरी ओर अजय बराज परियोजना का भी कुछ ऐसा ही हाल है. नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से 8643.56 लाख रुपये की लागत से बनी अजय बराज परियोजना आज उद्घाटन की बाट जोह रहा है. परियोजना कार्य 10.08.2006 में ही पूरा हो चुका है, लेकिन विस्थापितों की समस्या आज तक लंबित है. यहां भी विस्थापितों की सूची एवं मुआवजे की राशि गले की हड्डी बनी हुई है. यहां भी स्थानीय दबंग राजनीतिज्ञ विस्थापितों के साथ हैं.

उक्त दोनों ही परियोजनाओं में सरकार की अरबों की राशि ख़र्च हो रही है, लेकिन स्थानीय राजनीतिज्ञों की इच्छाशक्ति की कमी एवं चुनावी मुद्रा बने रहने के कारण ज़िले की बहुचर्चित एवं बहुप्रतीक्षित जलाशय परियोजना अधर में लटक कर रह गई है. ज़िले में समुचित सिंचाई और पेयजल की समस्या से जनता कराह रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और मज़दूर पलायन कर रहे हैं. इस पूरे मामले में ज़िला प्रशासन के साथ सरकार भी मूकदर्शक बनी हुई है.

रणजीत झा
feedback@chauthidunya.com

चुनावी जंग में कोसी बनेगी मुद्दा

सहरसा में किसान महापंचायत में उमड़ी भीड़ को अगर पैमाना माना जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह समारोह न सिर्फ़ कोसी की राजनीतिक दिशा तय करेगी, बल्कि इस इलाके में होने वाली चुनावी जंग की पटकथा भी तैयार करेगा. गर्मी से बेपरवाह लोगों ने किसान महापंचायत में आकर यह जताने की कोशिश की कि नीतीश शासन में सब कुछ ठीक नहीं है. इस किसान महापंचायत में सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा ज़िले के वैसे किसान एवं ग़रीब–गुरुवा आए, जो नीतीश सरकार के विकास से आज भी महरूम हैं. नगर परिषद मैदान में आयोजित इस महापंचायत में सभी तबकों के लोगों की भागीदारी से यह भी साफ़ हो गया कि किसान महापंचायत की बात हर ओर की जा रही है.

वैसे इतिहास गवाह है कि कोसी की धरती सत्ता परिवर्तन में अहम भूमिका अदा करती रही है और जंगल राज कहे जाने वाले लालू–राबड़ी सरकार को भी इसी कोसी मुद्दे ने एक झटके में उखाड़ फेंकने में अपना योगदान दिया. कोसी की 14 विधानसभा सीटों में सभी सीटें बिहार की तत्कालीन सरकार के विरोध में गई और नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर आसीन हुए. अब एक बार फिर किसान महापंचायत के नेताओं ने नीतीश सरकार को बटाईदारी क़ानून एवं बंधोपाध्याय कमिटी की रिपोर्ट रद्द करने, किसानों को प्रमाणिक खाद–बीज उपलब्ध कराने जैसे हितकारी व बुनियादी सवालों को लेकर कठघरे में खड़ा कर दिया है. महापंचायत में दिग्विजय सिंह ने साफ़ कहा है कि किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है. उन्होंने कहा कि अभी बिहार में घोषणा करने वाली सरकार है जबकि बिहार को काम करने वाली सरकार की ज़रूरत है. अखिलेश सिंह और प्रभुनाथ सिंह ने भी कहा कि किसानों के हक़ के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ी जाएगी. इससे पहले मोतिहारी, समस्तीपुर, भागलपुर और पूर्णिया सहित कई ज़िलों में भी किसान महापंचायत के माध्यम से इन नेताओं ने जनता से अपील की है कि इस सरकार को बदलने का समय आ गया है. बटाईदारी क़ानून से सामाजिक माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है. इन जगहों पर भी जनता का पूरा समर्थन किसान महापंचायत को मिला. सहरसा में किसान महापंचायत का सफल आयोजन कर विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने कोसी में अपनी ताक़त का एहसास करा दिया. युवा नेता अजय सिंह ने भी इसमें उनका बखूबी साथ दिया. देवेंद्र यादव व अनावरुल हक़ की मौजूदगी से यह बात भी साफ़ हो गई कि किसान महापंचायत में हर एक वर्ग की आवाज़ सुनी और समझी जा रही है. इसके माध्यम से नेताओं ने यह संदेश भी दिया कि लोगों को एक कठिन राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए. बटाईदारी क़ानून की खामियां गिनाते हुए इन नेताओं ने कहा कि नीतीश सरकार समाज में बंटवारा चाहती है और हमलोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे. किसानों के सामने मुसीबतों का पहाड़ है और उन्हें और भी संकट में डालने की साजिश हो रही है. बहरहाल अब पूरा ध्यान पटना में 9 मई को होने वाली रैली पर टिकी है. किशोर कुमार मुन्ना का दावा है कि अकेले कोसी की जनता गांधी मैदान को भर देगी. देखना है कि कोसी की धार नीतीश सरकार के पाये को हिला पाती है या नहीं.

एस सोरी
feedback@chauthidunya.com

कोसी के लोग भर देंगे गांधी मैदान : मुन्ना

सहरसा में किसान महापंचायत के सफल आयोजन से उत्साहित विधायक किशोर कुमार मुन्ना का दावा है कि आगामी नौ मई को पटना में आयोजित किसान महापंचायत में कोसी के लोग बढ़–चढ़ कर भाग लेंगे और गांधी मैदान को भर देंगे. उन्होंने कहा कि सहरसा में प्रचंड गर्मी के बावजूद जुटी भीड़ से यह साफ़ हो गया कि बटाईदारी क़ानून को लेकर लोग किस कदर चिंतित हैं. मुन्ना का मानना है कि बटाईदारी क़ानून को लेकर नीतीश कुमार की नीयत साफ़ नहीं है और देर–सबेर वह इसे लागू करना चाहते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ राहत के नाम पर सरकार केवल घोषणाएं कर रही हैं. लिहाजा बाढ़ पीड़ितों का जीना दूभर हो गया है. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बाढ़ पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो वह कोसी क्षेत्र में व्यापक आंदोलन का शंखनाद करेंगे. मुन्ना ने कहा कि नीतीश का असली चेहरा जनता के सामने आ गया है और आगामी चुनाव में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी. उन्होंने कहा कि बिहार में इस बार जनता की सरकार बनेगी, जो सही मायनों में देश–दुनिया में बिहार का मान बढ़ाएगी.

कर्पूरी स्मृति भवन को कर्पूरी की प्रतिमा का इंतज़ार

विकास कुमार

समाजवादी चिंतक, ग़रीबों के मसीहा, गुदड़ी के लाल एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम में आज भी लोग पेयजल की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं. इंदिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कन्या विवाह योजना समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन नहीं हुआ है. हद तो यह है कि कर्पूरी स्मृति भवन में आज तक कर्पूरी की प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकी है.

पेयजल सुविधा के लिए कर्पूरी ग्राम ज़रूर ही ज़िले में एक आदर्श ग्राम के रूप में दिख रहा है, क्योंकि गांव में एक वर्ष पहले एक भव्य जलमीनार बनवाया गया है. लेकिन विडंबना यह है कि पंचायत में पर्याप्त पाइपलाइन एवं नलके की कमी के कारण गर्मी में पानी के लिए लोग मारे–मारे फिर रहे हैं. पूरे पंचायत में लगे तक़रीबन 1600 चापाकल में से आधे से अधिक ख़राब पड़े हैं. जलमीनार के निकट के दलित मोहल्ले के पांचू राम, सुशील राम, शिवकुमार, सुनीता देवी आदि का कहना है कि सरकारी स्तर पर तो गांववासियों की सुख–सुविधा हेतु काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर संबंधित विभागीय अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण लोग सरकारी घोषणानुसार योजनाओं के लाभ से वंचित हैं. सिर्फ़ कहने भर को है कि गांव में जलापूर्ति की सुदृढ़ व्यवस्था है, लेकिन गांव के दलित बस्तियों में इसकी घोर कमी है. ग्रामीणों का कहना है कि जब गर्मी के प्रारंभिक दिनों में ही पेयजल के लिए हाहाकार मचा है तो जून–जुलाई में क्या हालत होगी? यह सोच कर ही लोग परेशान हो रहे हैं.

दलित बस्तियों में भ्रमण के दौरान लोगों ने चौथी दुनिया को बताया कि उन्हें एक घूंट ठंडे पानी के लिए इधर–उधर भटकना पड़ता है. मौजूदा सरकार की अधिकांश योजनाओं के भव्य होर्डिंग्स गांव की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और ही है. यह सब दिखावा है. कन्या विवाह योजना का आवेदन देने के बाद आज भी लोग लाभान्वित होने के लिए शासन–प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं. कुल मिलाकर यह योजना जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव में हवा–हवाई साबित हो रही है. गांव के लोग ममाहत हैं कि नए परिसीमन के तहत ज़िले में दो (उजियारपुर एवं मोरवा) विधानसभा का गठन किया गया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर की पहचान और प्रतिनिधित्व वाले पूर्व ताजपुर विधानसभा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने को लेकर स्थानीय प्रतिनिधि से लेकर सरकार तक ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है. 1952 के प्रथम विधानसभा चुनाव में पूर्व के ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से कर्पूरी ठाकुर विधायक हुए और इसके बाद में कांग्रेस शासनकाल में ताजपुर विधानसभा क्षेत्र को समाप्त कर दिया गया. इसके बाद वह समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा में पहुंचने लगे. 1985 में कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर ज़िला को छोड़कर सोनवर्षा(सीतामढ़ी) से चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे.

कर्पूरी ठाकुर के परिजन.

जब जननायक के गांव में सरकारी योजनाओं की वास्तविकता का आकलन करने हम कर्पूरी ग्राम के कर्पूरी स्मारक पहुंचे, तो पता चला कि गुदड़ी के लाल की स्मृति अब एक भव्य स्मारक भवन में स्थापित कर दी गई है. एक बड़े से कमरे में उनकी भव्य तस्वीर लगी है. तस्वीर के नीचे *निर्भय होकर जियो स्वाधीन होकर चलो, लोकहित की राह पर स्वहित का विसर्जन कर दो* नारा अंकित है, जो आगंतुकों को जननायक का संदेश दे रहा है. कर्पूरी ठाकुर के छोटे भाई स्व.रामस्वार्थ ठाकुर की वयोवृद्ध पत्नी रेशमा देवी (75) एवं उनकी बहू निशा ठाकुर ने जननायक की स्मृतियों को ताज़ा करते हुए बताया कि धन्य है कर्पूरी की यह जन्मभूमि, जहां देश के हर हिस्से के दिग्गज राजनीतिज्ञ आकर उन्हें नमन करते हैं. उन्होंने बताया कि कर्पूरी स्मारक पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे दिग्गजों का आना–जाना लगा रहता है. निशा ठाकुर गांव के ही आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यरत हैं, जबकि उनके पति एवं कर्पूरी ठाकुर के भतीजा नित्यानंद ठाकुर कर्पूरी ग्राम में स्थित गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी महाविद्यालय में सहायक के रूप में कार्यरत हैं. गांव के विकास के मुद्दे पर कर्पूरी स्मारक भवन में मौजूद जननायक के परिजनों ने संतोष जताते हुए कहा कि सरकार कर्पूरी जी की जन्म एवं कर्मभूमि पर हर सुविधा देने के लिए प्रयासरत है, लेकिन वर्षों से कर्पूरी ग्राम को प्रखंड का दर्ज़ा दिए जाने एवं थाना की स्थापना जैसी लंबित मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. जब मुखिया रंजना देवी से पंचायत स्तर पर हुए विकास कार्यों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि योजनाओं एवं विकासात्मक कार्य के मामले में पीसीसी एवं सड़क निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं. पंचायत में कुल 450 लोगों को इंदिरा आवास उपलब्ध कराया गया है तथा 300 आवेदन विचाराधीन हैं. मनरेगा के अंतर्गत 4 पुलियों का निर्माण, ईंट सोलिंग एवं स्थानीय जमुआरी नदी की उड़ाही आदि के कार्य कराए गए हैं. ग्रामीण दबी ज़ुबान से यह भी कहना नहीं भूलते कि कर्पूरी के इस गांव का सरकार लाख ख्याल रखे पर सरकारी योजनाओं की आड़ में मंत्री जी को अंधेरे में रखकर बिचौलियों द्वारा व्यापक पैमाने पर लूट–खसोट की जा रही है. एपीएल/बीपीएल निर्धारण में गड़बड़ी से लोगों में गहरी नाराज़गी व्याप्त है. व्यथित ग्रामवासियों का कहना है कि 15,000 की मासिक आय वाले परिवार को बीपीएल का लाभ मिलने लगा है, लेकिन ज़रूरतमंद सैकड़ों ग़रीब मूकदर्शक बने हुए हैं.

कर्मी ठाकुर

जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम लोग बड़े ही उत्साह से आते हैं, लेकिन उनकी जन्मस्थली कर्पूरी स्मृति भवन पर पहुंचकर वे मायूस हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति भवन में आज तक कर्पूरी की प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकी है. इस बात को लेकर कर्पूरी ग्राम के लोग ममाहित हैं. आक्रोशित ग्रामीण बताते हैं कि 1942 में कर्पूरी जी गांव के ही विद्यालय में शिक्षक थे. उस समय गांधीजी के आह्वान पर पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था. 1942 में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण और सूरजनारायण सिंह भागलपुर जेल से भागकर समस्तीपुर आए थे और पितौंझिया (अब कर्पूरी ग्राम) स्थित विद्यालय में रातभर छिपकर रहे थे. जेपी के विद्यालय में छिपने की ख़बर अंग्रेज़ों को मिली तो जेपी एवं उनके साथी तो यहां से भाग निकले, लेकिन इधर इस मामले में कर्पूरी जी की नौकरी चली गई और उन्हें अंग्रेज़ों की यातनाएं सहनी पड़ी थीं. कर्पूरी जी शिक्षक होते तो आज गांव के लिए मात्र रिटायर्ड शिक्षक होते, लेकिन उन्होंने नौकरी को लात मार दी और स्वाधीनता संग्राम को गले लगाया तो आज दुनिया उन्हें जननायक के रूप में जानती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ज़िले में विश्वास यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित है. ऐसे में कर्पूरी ग्राम के लोगों को आशा है कि इस विश्वास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जननायक की जन्मस्थली कर्पूरी ग्राम का विश्वास भी हासिल करने की कोशिश अवश्य करेंगे.

feedback@chauthidunya.com

अरुण कुमार को जदयू में लाने की तैयारी

दिव्या कुमारी

बिहार की राजनीति में मौक़ा और लाभ–हानि के हिसाब से दल–परिवर्तन नेताओं का पुराना शगल रहा है. हालात यह हैं कि दलबदल, अवसरवादिता और मौक़ापरस्ती से शायद ही कोई अछूता रहा हो. इस इतिहास और परंपरा को फिर से दोहराया जा रहा है. इस परंपरा के नए ध्वजवाहक बने हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार. नीतीश के साथ साए की तरह चिपके रहने वाले अरुण कुमार उनसे इस कदर बिदके कि वह नीतीश के गढ़ नालंदा में ही उन्हें ललकारने लगे. लालू और रामविलास का सहयोग पाकर नीतीश कुमार को चुटकियों में मसलने का दंभ भरने वाले अरुण पचास हज़ार वोट तक पहुंचते–पहुंचते हांफने लगे थे. नालंदा में रामस्वरूप प्रसाद से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव हारने वाले अरुण कुमार बारसों लोजपा कांग्रेस में पहुंच गए. कारण यह रहा कि पिछले संसदीय चुनावों में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अरुण कुमार के लिए जहानाबाद सीट छोड़ने से यह कहते हुए इंकार कर दिया था कि अरुण सीट नहीं निकाल पाएगा. इससे पहले नालंदा में करारी शिकस्त खाने वाले अरुण कुमार पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने व्यंग्य करते हुए कहा था कि हम तो समझे थे कि कुछ दम होगा, लेकिन यह तो खोखला निकला. लोजपा में राष्ट्रीय महासचिव रह चुके अरुण कुमार चुनाव लड़ने के लिए इस कदर बेचैन हो उठे कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का दामन थाम लिया. क़िस्मत ने यहां भी अरुण का साथ नहीं दिया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने जब जम्बो कमेटी बनाई तो युवा समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके अरुण कुमार को प्रदेश महासचिवों की फ़ौज में शामिल किया गया. दो संसदीय चुनावों में शिकस्त का सामना कर राजनीतिक विद्यावान में पहुंच चुके अरुण कुमार अब फिर से राजनीति की मुख्यधारा में आने को बेचैन हैं. बेचैनी इस कदर बढ़ी हुई है कि अब अरुण कुमार उन्हीं नीतीश कुमार की सदारत कबूल कर रहे हैं. डॉ. अरुण कुमार के समर्थक कहते हैं कि नीतीश कुमार की ओर से पहल हुई थी, परंतु कुमार भी उनकी पार्टी में आना चाह रहे हैं. हालांकि मुंगेर के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ़ ललन सिंह की बग़ावत के बाद नीतीश कुमार को भी एक सशक्त भूमिहार नेता की ज़रूरत थी, जिसकी बिरादरी में अपनी पहचान हो. ललन सिंह के इस्तीफ़े के बाद भूमिहार बिरादरी के विजय चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया. परंतु चौधरी के अध्यक्ष घोषित होने के बाद जब लोगों ने उनकी जाति पूछी तो स्थिति हास्यास्पद हो गई. अब उसी गैप को भरने का प्रयास किया जा रहा है. बताया जाता है कि ललन सिंह के इस्तीफ़े के बाद नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य किंग महेंद्र के ज़रिए अरुण कुमार को पाले में लाने की कोशिश की थी. किंग महेंद्र के कई प्रयासों के बावजूद अरुण कुमार प्रस्ताव को नकारते रहे. अरुण कुमार और किंग महेंद्र न सिर्फ़ स्वजातीय हैं, बल्कि दोनों का गृह ज़िला भी एक ही है. महेंद्र पिछली बार जदयू के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे थे. बताया जाता है कि विगत विधानसभा चुनावों के दौरान जब जदयू का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ाया था तो किंग महेंद्र ने ही झोली खोली थी. उनके प्रस्तावों पर अरुण ने इसीलिए हामी नहीं भरी थी कि ललन के इस्तीफ़ा प्रकरण को वह मोलजोल का ड्रामा मान रहे थे. वैसे भी ललन के व्यवहार से आहत होकर ही अरुण बाग़ी हुए थे. विधानसभा चुनावों के बाद नीतीश कुमार ने अरुण कुमार को शपथ लेने के लिए तैयार रहने को कहा था. पूरी तैयारी के साथ अरुण कुमार गांधी मैदान पहुंचे तो अरुण के बदले उनके भाई अनिल कुमार को शपथ दिला दी गई. अपमानित अरुण पार्टी छोड़कर चले गए. दो बार बिहार विधान परिषद सदस्य और एक बार सांसद रह चुके अरुण कुमार को जदयू में सम्मान वापस लाने का ताना–बाना बुन रहे हैं विक्रमगंज के पूर्व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह. दादा के नाम से चर्चित वशिष्ठ नारायण ने मुख्यमंत्री से बात कर ली है. अंदर खाने की ख़बर रखने वाले बताते हैं कि नीतीश कुमार ने सैद्धांतिक सहमति जता दी है. अब सिर्फ़ औपचारिकता ही बाक़ी है. हालांकि अरुण की नज़र अभी राज्यसभा चुनाव पर है. जदयू में वापसी से पूर्व अरुण कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलने वाले हैं. सूत्र बताते हैं कि राज्यसभा चुनाव से पूर्व अरुण कुमार जदयू में आ जाएंगे. हालांकि जदयू में शामिल होने के मुद्दे पर जब उनसे पूछा गया तो वह इसे हंस कर टाल गए.

अरुण कुमार

feedback@chauthidunya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 03 मई–09 मई 2010

अगर यही काम मैडम श्रद्धा कर रही हैं तो इसमें बुरा क्या है. मैडम के सितारे इसलिए गर्दिश में क्योंकि उनकी फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर चारों खाने चित हो रही हैं.

ककोलत जलप्रपात
अस्तित्व पर ख़तरा

नवादा ज़िले से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक ऐसा जलप्रपात जो सुंदरता और प्राकृतिक सौंदर्य के लिहाज से देश के किसी भी जलप्रपात से कम नहीं है, लेकिन सरकारी महकमा इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के बजाय उसके अस्तित्व को मिटाने के लिए तत्पर हैं.

बिहार में कश्मीर के नाम से प्रसिद्ध नवादा ज़िले के गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले प्राकृतिक पर्यटन स्थल ककोलत जलप्रपात पर अस्तित्व मिटने का खतरा मंडराने लगा है, जबकि विकास के इस दौर में इसे सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन आलम यह है कि विकास कार्यों में इसका स्थान कहीं नहीं है. पिछले एक दशक से इस प्रसिद्ध जलप्रपात की सरकारी उपेक्षा ने स्थानीय लोगों को निराश किया है. यदि ककोलत जलप्रपात को सरकारी प्रयास से विकसित कर दिया जाए तो यहां विदेशी सैलानियों की भीड़ लगी रहेगी, जिससे सरकार के साथ-साथ यहां के लोगों को भी फायदा होगा. यह कहना है इसकी देखरेख कर रहे ककोलत विकास परिषद के लोगों का.

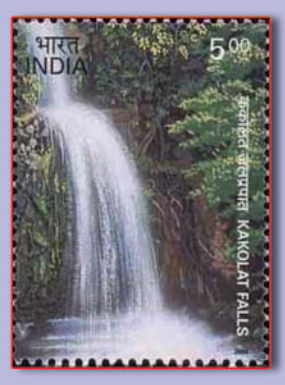

यह जलप्रपपात प्राचीन काल से प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है. आज़ादी से पूर्व घने जंगल और दुर्गम रास्तों के बावजूद यह जलप्रपात अंग्रेजों के लिए गर्मी में प्रमुख पर्यटक केंद्र हुआ करता था. प्रति वर्ष 14 अप्रैल को यहां पांच दिवसीय सतुआनी मेला पर लोगों का जमावड़ा लगता है. बावजूद यह उपेक्षित है. सरकार चाहे तो ककोलत जलप्रपात के विकास के रास्ते यहां के स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराके बेरोजगारी दूर कर सकती है, लेकिन अभी तक तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा है. झारखंड से अलग होने के बाद शेष बिहार में ककोलत अकेला ऐसा जलप्रपात है, जिसका पौराणिक और पुरातात्विक महत्व है. बिहार सरकार इस ऐतिहासिक जलप्रपात की महता को समझे या नहीं, लेकिन भारत सरकार के डाक एवं तार विभाग ने इस जलप्रपात की ऐतिहासिक महता को देखते हुए ककोलत जलप्रपात पर पांच रुपये मूल्य का डाक टिकट भी जारी किया है. इसका लोकार्पण भी डाक तार विभाग ने 2003 में ककोलत विकास परिषद के अध्यक्ष मसीहउद्दीन से पटना में कराया. 1995 में गया के तत्कालीन डीएफओ बाईके सिंह चौहान, नवादा के तत्कालीन ज़िलापदाधिकारी रामवृक्ष महतो तथा ककोलत विकास परिषद के अध्यक्ष मसीहउद्दीन की तिकड़ी ने इसका कायाकल्प कर दिया. ज़िलापदाधिकारी ने पचास लाख रुपये की राशि मुहैया कराई तो डीएफओ ने वन विभाग के तमाम नियमों में शिथिलता बरतते हुए ककोलत जलप्रपात को पूरी तरह एक अच्छे पर्यटन स्थल का रूप दे दिया. वहां वन विभाग की ओर से आकर्षक गेस्ट हाउस और दुकानों का निर्माण कराया. कुछ वर्षों तक यहां सब कुछ ठीक-ठाक रहा. बाद के वर्षों में आने वाले ज़िला पदाधिकारी, वन विभाग के पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस पर ध्यान नही दिया. जिसके कारण यहां की स्थिति दयनीय हो गई. ककोलत तक जाने वाली सड़क भी पूरी तरह जर्जर हो चुकी है. 1997 से ककोलत विकास परिषद की ओर से विसुआ मेला को ककोलत महोत्सव के रूप में विस्तृत रूप देकर आयोजन किया जाता है. 1997 में ककोलत महोत्सव की शुरुआत बिहार के प्रसिद्ध माउंटेनमैन दशरथ मांझी के हाथों कराया गया था. इस महोत्सव के माध्यम से मगध की सांस्कृतिक विरासत को बचाने तथा यहां की प्रतिभाओं को उभारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन आज सुशासन में भी ककोलत जलप्रपात के आसपास के क्षेत्रों में विकास के तमाम दावे फुस्स नज़र आ रहे है.

यह जलप्रपात नवादा ज़िला मुख्यालय से 35 किलोमीटर पूरब दक्षिण गोविंदपुर प्रखंड में स्थित है. सात पर्वत श्रृंखलाओं से प्रवाहित ककोलत जलप्रपात और इसकी प्राकृतिक छंटा बहुत सारे कोतुहलों को जन्म देता है. धार्मिक मान्यता है कि पाषाण काल में दुर्गा सप्तशती के रचयिता ऋषि मार्कंडे का ककोलत में निवास था. मान्यता यह भी है कि ककोलत जलप्रपात में वैशाखी के अवसर पर स्नान करने मात्र से सांप योनि में जन्म लेने से प्राणी मुक्त हो जाता है. यह भी कहा जाता है कि राजा नृप किसी ऋषि के श्राप के कारण अजगर के रूप में इस जलप्रपात में निवास कर रहे थे. तब ऋषि मार्कंडे के प्रसन्न होने पर उन्हें इस योनि से मुक्ति मिली. महाभारत में वर्णित कांयक वन आज का ककोलत ही है, अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना कुछ समय यही पर व्यतीत किया था तथा इसी स्थान पर श्रीकृष्ण ने उन्हे दर्शन दिया था. इस क्षेत्र में कोल जाति के लोग निवास करते थे. इसलिए इसका नाम ककोलत पड़ा. एक मान्यता है कि प्राचीन काल में मदालसा नाम की एक पतिव्रता नारी ककोलत के आसपास निवास करती थी और जलप्रपात में अपने रोगी पति को कंधे पर बिठाकर स्नान कराने के लिए प्रतिदिन इस जलप्रपात में ले जाती थी. कुछ समय बाद उसका पति निरोग हो गया.

अंग्रेजों के शासनकाल में फ्रांसिस बुकानन ने 1811 ई में इस जलप्रपात को देखा और कहा कि जलप्रपात के नीचे का तालाब काफी गहरा है. इसकी गहराई को भरने के उद्देश्य से एक अंग्रेज अधिकारी के आदेश पर स्नान करने वालों को स्नान करने से पहले तालाब में एक पत्थर फेकने का नियम बनाया था. इस तालाब में सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है. 1994 में इस जलप्रपात के नीचे के तालाब को भर दिया गया, जिससे लोग इसमें आराम से स्नान कर सके. तब से इसका आकर्षण और बढ गया. आज ककोलत जलप्रपात को जानने वाले लोगों का कहना है कि यदि सरकार बिहार के इस कश्मीर को विकसित कर दे, तो राज्य सरकार को विदेशी मुद्रा की आय होगी और साथ ही अद्‌भूत पर्यटन स्थल को देखने के लिए देश और दुनिया से बड़ी संख्या में लोग आ सकेंगे. फिलहाल ज़िले के फतेहपुर मोड़ से ककोलत जाने के लिए सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है. दरअसल ककोलत शीतल जलप्रपात वोट की राजनीति के लिए कोई मुद्दा नहीं बन सकता. फलत: सरकार और राजनीतिज्ञ इसके विकास पर विचार करना भी मुनासिब नहीं समझते.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

नक्सलियों का रेड हंट अभियान

जिस पुलिस को देखकर हम चैन की नींद सोते हैं. अगर वही अपनी सुरक्षा ख़ुद न कर सके तो देश की जनता क्या होगा? कुछ ऐसा ही हो रहा रोहतास में. जहां पुलिस नक्सलियों के आगे बेबस नज़र आ रही है. एक तरफ़ नक्सलियों के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चल रहा तो वहीं दूसरी तरफ नक्सली पुलिस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन रेड हंट चला रहे हैं.

देश के अन्य राज्यों में नक्सली संगठनों के ख़िलाफ़ केंद्र सरकार भले ही ऑपरेशन ग्रीन हंट चला रही हो, लेकिन मजे की बात यह है कि बिहार के रोहतास ज़िले में पुलिस के ख़िलाफ़ नक्सलियों का रेड हंट अभियान अपने चरमोत्कर्ष पर है. नक्सलियों ने पहले तिलौथू प्रखंड परिसर में निर्माणाधीन थाना भवन एवं नरेगा कार्यालय को बम से उड़ा दिया. उसके बाद सैकड़ों चक्र गोलियां चलाते हुए पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू कर दी. यही नहीं अपने बुलंद हौसलों के साथ डेहरी-यदुनाथपुर पथ पर तेलकप के समीप एक दर्ज़न वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया. हैरानी की बात तो यह कि जिस समय नक्सली इन दोनों जगहों पर हिंसक तांडव मचा रहे थे, उस वक्त बंजारी एवं डेहरी बीएमपी कैंप में सैकड़ों जवान आराम की नींद सो रहे थे. नक्सलियों के बुलंद हौसले का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद पुलिस ने जो कुछ भी किया वह केवल खानापूर्ति सा दिखा. पुलिस के इस ढुलमुल रवैये की वज़ह से नक्सलियों का मन और बढ़ गया. नतीजतन नक्सली दस्ते ने इस घटना के दूसरे ही दिन धनसा घाटी में एक और विद्यालय को बम से उड़ा दिया. बता दें कि यह वही भवन था, जहां पूर्व में बीएसएफ के जवानों ने कैंप कर नक्सलियों के साथ दो-दो हाथ किए थे. उस समय भी नक्सलियों ने मुठभेड़ के दौरान इस विद्यालय भवन का एक कमरा बारूदी सुरंग लगाकर उड़ा दिया था. नक्सलियों का तांडव यही ख़त्म नहीं हुआ. उन्होंने पुलिस के ग्रीन हंट के जवाब में रोहतास में रेड हंट चलाते हुए मध्य विद्यालय को उड़ा डाला. नक्सली कमांडर राजेश कुमार उर्फ़ तूफ़ान ने ज़िले के राजपुर बाज़ार में कुछ दबंगों के ख़िलाफ़ फतवा जारी कर लोगों के होश उड़ा दिए हैं. इधर पनारी घाट में एक किसान को नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. इस घटना के ठीक दूसरे ही दिन चेनारी थाना क्षेत्र के केनार ख़ुर्द गांव में क़रीब 200 भाकपा माओवादियों ने एक घर को डाइनामाइट लगाकर उड़ा दिया और उसके बाद गांव के ही एक व्यक्ति राम बदन सिंह एवं उसके पुत्र विशंभर को गोलियों से छलनी कर दी. 15 दिनों के अंदर घटी इन घटनाओं के पीछे पुलिस की मुस्तैदी की बात की जाए तो पाएंगे कि पुलिस के द्वारा नक्सलियों के ख़िलाफ़ छापेमारी अभियान चलाई तो गई, लेकिन छापेमारी के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं मिला. ऐसे में आम लोगों के ज़ुबान पर एक ही सवाल है कि जो पुलिस अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकती, उस पुलिस तंत्र से सुरक्षा की कैसी उम्मीद. शायद यही कारण है कि कैमूर पहाड़ी पर रहने वाले दर्ज़नों लोगों ने पुलिस के ख़िलाफ़ विरोध जताते हुए भाकपा माओवादी दस्तों के सामने घुटने टेक देने का फ़ैसला किया है, ताकि जानमाल की कोई क्षति न हो. बहरहाल, ज़िले में बढ़ती नक्सली गतिविधियों को देखकर यह कहना ग़लत नहीं होगा कि यहां जहानाबाद जेल ब्रेक, दांतेवाड़ा जैसी कोई घटना कभी भी घट सकती है. फिलहाल, देश के अन्य राज्यों में पुलिस द्वारा नक्सलियों के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे ग्रीन हंट के समानांतर नक्सलियों ने पुलिस के ख़िलाफ़ अपना रेड हंट अभियान को गति दे रखा है.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

मैडम के नए पैंतरे

कंट्रोवर्सी किंग राजा चौधरी के साथ लिव इन रिलेशन में रह चुकी श्रद्धा आजकल अपने करियर को लेकर कुछ ज़्यादा ही सतर्क हो गई हैं. हो भी क्यूं न. क्योंकि जब सितारे गर्दिश में हो तो इंसान सूझ-बूझ से काम लेता है. अगर यही काम मैडम श्रद्धा कर रही हैं तो इसमें बुरा क्या है. मैडम के सितारे इसलिए गर्दिश में क्योंकि उनकी फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर चारों खाने चित हो रही हैं. इसके अलावा वह भोजपुरी फ़िल्मों में आइटम डांसर की छवि से भी छुटकारा पाना चाहती हैं. उनका कहना है कि अब वह गंभीर फ़िल्मों में काम करके अपनी सेक्सी गर्ल की इमेज से उबरना चाहती हैं, लेकिन कुछ दिन पहले श्रद्धा अपनी इसी इमेज पर फूली नहीं समाती थीं. जब उन्होंने निर्माता-निर्देशक जी पी सिप्पी के साथ तीन फ़िल्मों की डील साइन की थी. उस वक्त उनको लगा था कि अब उन्हें भोजपुरी फ़िल्मों में नंबर एक की हीरोइन बनने से कोई भी नहीं रोक सकता. मगर, मैडम के होश ठिकाने आ गए हैं. जब एक एक कर उनकी फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर पानी मांगती नज़र आई. सिद्धार्थ के साथ उनके अफेयर की ख़बरों से उनके डगमगाते करियर को कोई भी फायदा नहीं हुआ. हाल ही में एक कार्यक्रम में उनका डांस शो था. जब श्रद्धा से इस बाबत बात हुई तो उनका कहना था कि सारे प्रोजेक्ट अभी आने बाकी है. इसलिए निराश होने की ज़रूरत नही है. असफलता निराश करती है मगर हताश नहीं. आपको बता दें कि श्रद्धा ने भोजपुरी फ़िल्मों के अलावा कई स्टेज शो और विज्ञापन फ़िल्मों में भी काम कर चुकी हैं. राखी के ब्वॉयफ्रेंड रह चुके अभिषेक अवस्थी के साथ उनके अफेयर के भी खूब चर्चे हुए थे. देखते हैं कि इस रंग बदलती फ़िल्म नगरी में श्रद्धा का यह नया पैंतरा कितना काम आता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़

दिल्ली, 03 मई–09 मई 2010

www.chauthiduniya.com

जल संकट से जनता बेहाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी भी आत्मरचित स्वप्नलोक से बाहर नहीं निकले हैं. रोटी, कपड़ा और मकान तो बहुत दूर की बात, वह राज्य की प्यासी जनता को पानी तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं. बावजूद इसके आओ बनाएं अपना मध्य प्रदेश और स्वर्णिम मध्य प्रदेश का उनका आलाप बदस्तूर जारी है.

विनय दीक्षित

मध्य प्रदेश में भीषण जानलेवा गर्मी पड़ रही है. दोपहर में तो लगता है जैसे हवा आग बरसा रही हो. राज्य में इन दिनों कहीं भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है. निमाड़, मालवा और बुंदेलखंड में तो कहीं-कहीं तापमान 45 डिग्री से ऊपर तक पहुंच जाता है. ऐसे गर्म मौसम में पूरे राज्य में जल संकट जनता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है. विभिन्न शहरों में पानी को लेकर आए दिन विवाद हो रहे हैं. पानी की वज़ह से चार हत्याओं और सौ से ज़्यादा मारपीट के मामलों की रिपोर्ट पुलिस थानों में दर्ज़ हो चुकी है. कई मामलों में तो पुलिस ने ख़ुद बीच बचाव कर लोगों को शांत करा दिया. जल संकट से न सिर्फ़ सामाजिक शांति भंग हो रही है बल्कि पुलिस के लिए भी समस्या पैदा हो रही है.

भोपाल के राज्य मंत्रालय और सिंचाई-पेयजल आपूर्ति से संबंधित विभागों के आला अफ़सरों ने गर्मी का हवाला देते हुए मांग की कि कार्यालयों में बंद पड़े एसी और कूलर चालू कराए जाएं. मुख्यमंत्री ने भी बिना देर किए घोर बिजली संकट के बावजूद सरकारी ख़र्चे पर एसी और कूलर चलवाने की अनुमति दे दी. अब सरकारी कार्यालयों में पानी ठंडा करने की मशीनें, कहीं-कहीं मटके और पुराने भवनों में खस की चटाइयां भी लग चुकी हैं. मुख्यमंत्री ने अपनी समूची संवेदनशीलता सरकारी अमले के लिए सुख-सुविधा जुटाने में ख़र्च कर दी, लेकिन जनता की ओर ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा. जानकारी के अनुसार, राज्य के 19 ज़िलों में अत्यधिक सूखे की स्थिति है और जल संकट गंभीर है. उक्त ज़िले हैं-राजगढ़, मंडला, ग्वालियर, गुना, पन्ना, दमोह, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, कटनी, टीकमगढ़, अशोकनगर, श्योपुर, खंडवा, बुरहानपुर एवं अलीराजपुर. इनके अलावा कम गंभीर माने गए 23 ज़िले हैं- सतना, उमरिया, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, सागर, छतरपुर, रायसेन, विदिशा, सीहोर, हरदा, शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, मंदसौर, नीमच, देवास, शाजापुर, रतलाम, बड़वानी, धार एवं झाबुआ. केवल भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, खरगौन, छिंदवाड़ा एवं नरसिंहपुर आदि आठ ज़िलों की स्थिति सामान्य बताई जाती है.

राज्य के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता सुधीर सक्सेना का कहना है कि राज्य में जल संकट की स्थिति है और इससे निपटने के लिए हर ज़िले में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं. प्रत्येक कंट्रोल रूम में कार्यपालन यंत्री को तैनात किया गया है. कंट्रोल रूम ट्यूबवेल सुधारने, नए ट्यूबवेल लगाने, राइजर पाइप बढ़ाने एवं हैंडपंपों में सिंगल फेस पंप लगाने का काम कर रहे हैं. जिन ज़िलों में जलस्रोत नहीं हैं और परिवहन के ज़रिए पानी की आपूर्ति होती है, वहां ज़िला प्रशासन के सहयोग से जल परिवहन की व्यवस्था की गई है. राज्य में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल एक लाख 27 हज़ार मानव बस्तियां हैं. वर्तमान में पूरे राज्य में 4,40,000 हैंडपंप हैं और 8500 नल-जल योजनाएं कार्यरत हैं. राज्य में हर नागरिक को प्रतिदिन औसतन 55 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी उन्हें 40 लीटर पानी ही दिया जा रहा है. वहीं कुछ क्षेत्रों में प्रति नागरिक को प्रतिदिन औसतन 15 से 20 लीटर पानी मुश्किल से मिल रहा है.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य में सात हज़ार से भी अधिक बस्तियों में जलस्रोत सूख चुके हैं. क़रीब 30 हज़ार हैंडपंप और 1300 से अधिक नल-जल योजनाएं बंद पड़ी हैं. विभाग ने जल संकट से निपटने के लिए 8600 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है. प्रदेश में ऐसे 19 ज़िले हैं, जो सूखे से सर्वाधिक प्रभावित हैं. इनमें जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है. नल-जल योजनाएं भी काम नहीं कर रही हैं. हालात से निपटने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें नलकूपों के खनन, हैंडपंपों में राइजर पाइप का विस्तार, सिंगल फेस सबमर्सिबल पंपों की स्थापना और बंद नल-जल योजनाओं हेतु वाहन की व्यवस्था आदि कार्य शामिल हैं. जल संकट के बारे में मध्य अप्रैल में जल संसाधन एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जो सूचना सार्वजनिक की है, वह कोई नई नहीं है. जलस्रोतों के बारे में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के जलस्रोतों में साल दर साल कमी देखी जा रही है.

राज्य में उपलब्ध जल क्षमता का अधिकतम 43.25 प्रतिशत ही सिंचाई के काम आता है, लेकिन दूसरा आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि उपलब्ध सिंचाई क्षमता का वर्तमान में 35-36 प्रतिशत ही उपयोग हो रहा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि जल संसाधन विभाग उद्योगों, बिजली परियोजनाओं एवं अन्य क्षेत्रों के लिए पानी की आपूर्ति करता है और सिंचाई के लिए पानी में जानबूझ कर कटौती करता है. मध्य प्रदेश में सतत प्रवाही नदियों की कमी नहीं है. नर्मदा, चंबल, सोन एवं बेतवा आदि अंतर्राज्यीय नदियां हैं, जिन पर बने बांधों से मध्य प्रदेश को ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र को भी भरपूर पानी मिलता है. इसके अलावा पड़ोसी राज्यों के किसान और जनसामान्य अपनी ज़रूरत के लिए इन नदियों से अवैध रूप से पानी भी खींच लेते हैं. बालाघाट ज़िले में बाणगंगा नदी तट से महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में रोज अवैध रूप से पानी लिया जाता है. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के एक सर्वेक्षण से ख़ुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से महेश्वर तक नर्मदा जल की रोज बड़ी मात्रा में चोरी की जा रही है. नर्मदा तट पर लगभग 85 हज़ार पंप नदी के जल को खींचने का काम कर रहे हैं, जिनके ज़रिए कृषि एवं उद्योगों को अवैध तरीक़े से पानी उपलब्ध कराया जा रहा है.

प्राधिकरण ने नदी में विभिन्न स्थानों पर जलगणना कराई है. इसमें लगभग एक हज़ार किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र में पानी का हिसाब लगाया जा रहा है. यह सर्वेक्षण भविष्य में नर्मदा से जुड़े अन्य राज्यों के साथ जल विवाद की आशंका को टालने के लिए किया जा रहा है. इसके लिए प्राधिकरण ने भोपाल में एक हाईटेक सेल गठित किया है. अभी तक की जलगणना में नर्मदा तट पर विद्युत चालित पंपों द्वारा अवैध रूप से पानी खींचने का अध्ययन किया गया है. सवाल यह भी उठ रहा है कि इन पंपों को बिजली कहां से और कैसे मिल रही है? ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर बिजली कटौती होती है, फिर भी नर्मदा तट पर उक्त पंप चलते रहते हैं. लगता है कि नर्मदा से पानी चुराने वाले बिजली की भी चोरी कर रहे हैं. यही हाल चंबल और बेतवा नदियों का है. इन नदियों से उद्योग और निर्माण गतिविधियों में लगी कई संस्थाएं पानी चुराती हैं.

राज्य की कई नदियां सतही एवं भूगत जलस्रोत प्रदूषण के शिकार हैं. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि राज्य की क़रीब डेढ़ करोड़ आबादी फाइलेरिया बीमारी की चपेट में है. यह बीमारी दूषित पेयजल में पनपने वाले मच्छरों से होती है. इसके अलावा मलेरिया, पीलिया, त्वचा, किडनी और लीवर के रोग भी दूषित पेयजल से ही होते हैं. शहरी क्षेत्रों के कचरे, औद्योगिक मल एवं दूषित जल से राज्य की बड़ी नदियां, उनकी सहायक नदियां और छोटे नाले प्रदूषित हो रहे हैं. गर्मी में पानी की कमी के कारण मजबूर जनता इन्हीं प्रदूषित जलस्रोतों से अपनी प्यास बुझाती है और नई-नई बीमारियों को गले लगाती है. जल संकट की गंभीरता सरकारी काग़ज़ों में दर्ज़ हैं, लेकिन इसके समाधान के लिए सरकार ज़रा भी गंभीर नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

शेर, बकरी और इंसान एक घाट पर

कि सी बादशाह के सुशासन और न्यायप्रियता की प्रशंसा में इतिहासकारों ने लिखा है कि उसके राज में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे. बादशाह की सुरक्षा प्रणाली पर बकरी को भरोसा था कि शेर अकारण उसे क्षति नहीं पहुंचा सकता. इस कहानी जैसा ही माहौल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज में है. भीषण जल संकट के इस दौर में राज्य के वन एवं पर्वतीय क्षेत्रों में जलस्रोत सूख चुके हैं. इस कारण वन्यप्राणी अपनी प्यास बुझाने के लिए समीप के गांवों, शहरों और जलस्रोतों की ओर भागने पर मजबूर हैं. गांवों में भी कुएं, तालाब और नलकूप सूख रहे हैं. इस कारण जनता और पालतू पशु भी नदियों एव सतत प्रवाही नालों से प्यास बुझाने के लिए मजबूर हैं. कई गांवों में मीलों दूर से ग्रामीण दिन भर पानी ढोने का काम करते हैं. बुंदेलखंड निमाड़ और महाकौशल अंचल में वनक्षेत्रों के समीप स्थित कई गांवों और छोटे शहरों से आए दिन ख़बरें मिल रही हैं कि वनों के हिंसक प्राणी और दूसरे अन्य जानवर प्यास बुझाने के लिए वहां के कुओं, तालाबों, पोखरों एवं नालों की ओर आते हैं. जबकि राज्य के वन विभाग का दावा है कि वन्यप्राणियों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभाग ने लाखों रुपये ख़र्च करके विशेष व्यवस्था की है.

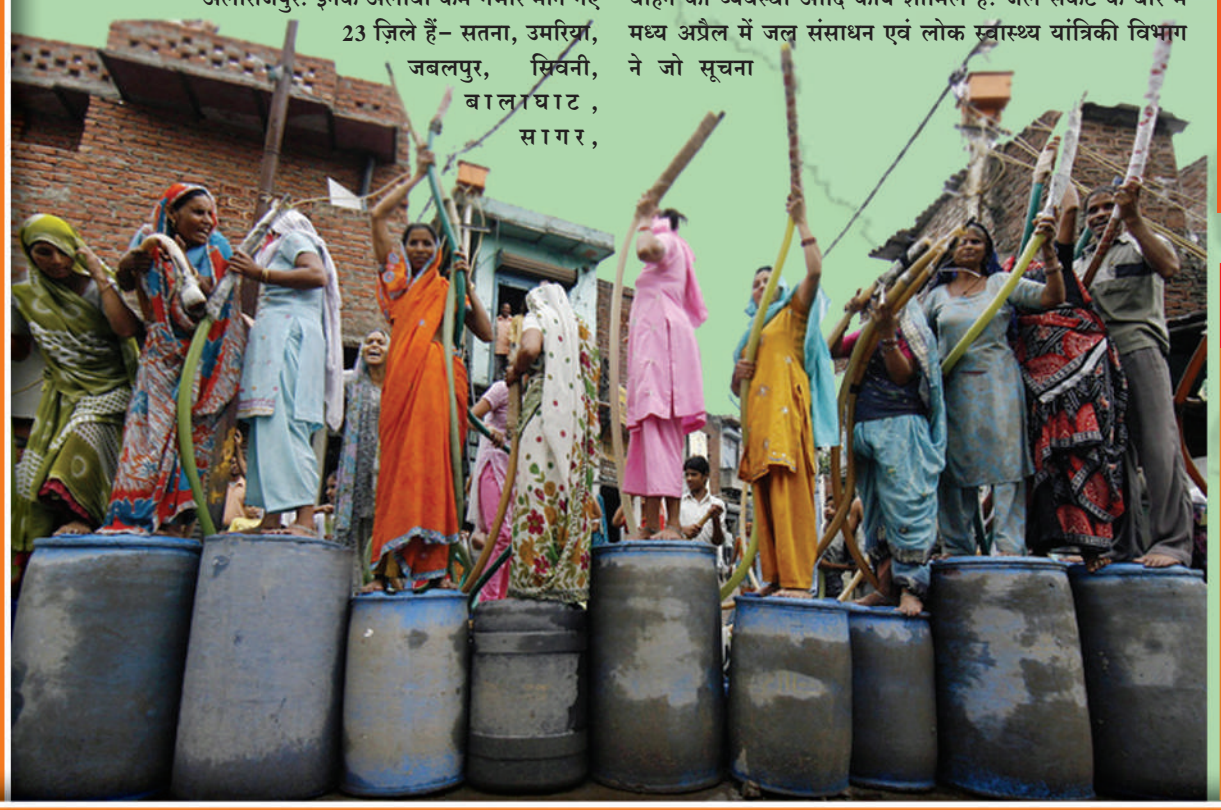

जलस्रोतों में साल दर साल कमी (हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में)

वर्ष	सरकारी नहरें	ग़ैर सरकारी नहरें	तालाब	नलकूप एवं कुएं	अन्य	कुल जल क्षेत्र	कृषि के लिए सिंचाई में उपयोग आने वाले जल का प्रतिशत
2003-04	947.3	1.9	127.2	3734.6	819.8	5630.8	37.42
2004-05	1004.0	1.6	124.7	3993.4	918.0	6041.7	40.07
2005-06	1028.3	1.4	133.8	1696.1	821.8	5681.4	37.69
2006-07	1089.2	1.7	148.9	4195.8	929.0	6364.6	42.89
2007-08	1048.3	2.3	138.1	4256.8	972.9	6418.4	43.40
2008-09	1064.8	0.9	129.9	4369.7	940.9	6506.2	43.25

सार -संक्षेप

तीस करोड़ रुपयों का चावल गोदामों में ख़राब हो रहा है

मध्य प्रदेश में सरकारी गोदामों में लगभग 20 हज़ार टन चावल पिछले डेढ़ वर्ष से पड़ा है. उचित रखरखाव के अभाव में इस चावल की गुणवत्ता दिनों-दिन ख़राब हो रही है. इस चावल का मूल्य लगभग 30 करोड़ बताया जाता है. यह चावल दिसंबर 2008 से जून 2009 के बीच समर्थन मूल्य पर ख़रीदे गए धान से तैयार किया गया था. उस समय ज़्यादा ख़रीदी होने के कारण चावल काफ़ी मात्रा में एकत्रित किया गया. इसमें से लगभग 45 करोड़ रुपये क़ीमत का 30 हज़ार टन चावल अकेले ग्वालियर क्षेत्र के गोदामों में रखा गया था. ग्वालियर में चावल की ख़पत सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कम है, जबकि जबलपुर, रीवा, सतना, अनूपपुर, उमरिया में चावल की ख़पत ज़्यादा है. राज्य शासन के कुप्रबंधन की वज़ह से ग्वालियर में तैयार चावल लंबे समय तक रखा रहा और अन्य स्थानों पर चावल की आपूर्ति भारतीय खाद्य निगम से लेकर की जाती रही. वहां से चावल निकालने का काम हाल ही में शुरू हुआ है, लेकिन अब भी 20 हज़ार टन शेष है. मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक केसी गुप्ता मानते हैं कि पिछले साल समर्थन मूल्य पर धान की ख़रीदी ज़रूरत से ज़्यादा हो गई थी. इस कारण राज्य सरकार के पास चावल का भंडार एकत्रित हो गया था. ग्वालियर संभाग में पिछले साल का बचा हुआ यही 20 हज़ार टन चावल है, लेकिन पुराना होने के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जबकि खाद्य आयोग अजीत केशरी का कहना है कि यदि पीडीएस के लिए चावल का कोटा केंद्र सरकार बढ़ा दे तो राज्य के पास भंडार में जमा चावल के स्टॉक का निस्तारण हो जाएगा. कोटा नहीं बढ़ाने के कारण हमें चावल का भंडार रखना पड़ रहा है.

ग्रामीण विद्युतीकरण की राशि ख़र्च नहीं हुई

मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में कितनी सुस्त और लापरवाह है, इसका प्रमाण यही है कि पांच साल में भारत सरकार से प्राप्त धनराशि में से लगभग तीन अरब रुपया भी राज्य सरकार ख़र्च नहीं कर पाई. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत भारत सरकार से राज्य को पांच वर्षों के लिए 720 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था, लेकिन सरकार केवल 420 करोड़ रुपया ही ख़र्च कर पाई. मध्य प्रदेश में वर्ष 2005-06 से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना संचालित हो रही है. इसके तहत प्रत्येक गांव को बिजली मुहैया कराने के लिए 5 वर्षों में केंद्र से 720 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन सरकार केवल 420 करोड़ ही ख़र्च करने में सफल रही है. यानि सरकार की मंशा कतई नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के किसानों तथा मजदूर वर्ग को बिजली मुहैया हो सके. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के योजना में 90 फीसदी राशि केंद्र तथा 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार ख़र्च करती है. इस योजना में कुछ ज़िलों में कार्य ठीक भी हुआ है, परंतु अधिकांश ज़िलों की रिपोर्ट काग़ज़ी घोड़े ही साबित हो रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इन 5 वर्षों में राज्य के बालाघाट, उमरिया, छतरपुर, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, डिंडौरी, सतना, अनूपपुर, दतिया और श्योपुर ज़िलों में एक पैसा भी ख़र्च नहीं किया गया है. मंडला, शहडोल, इंदौर ज़िलों में लगभग 30 फीसदी धनराशि ही ख़र्च की गई है. ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में न केवल विद्युत सुविधा विहीन गांव को विद्युत आपूर्ति करने का काम किया जाना था, बल्कि ग्रामीण इलाक़ों में बिजली आपूर्ति में आ रही दिक्कतों, बिजली उपकरणों में सुधार, बिजली लाइनों की मरम्मत आदि के काम भी शामिल है. राज्य में ग्रामीण इलाक़ों में हज़ारों की संख्या में विद्युत ट्रांसफॉर्मर बिगड़े हुए हैं, जिनके कारण बिजली आपूर्ति नहीं हो पाती है, लेकिन इन ट्रांसफॉर्मरों को बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है. इसके अलावा छोटे-छोटे उपकरणों के अभाव में गांव में बिजली कई-कई दिनों तक बंद रहती है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है. राज्य में इस गर्मी के मौसम में बिजली की भारी कमी है. मांग और आपूर्ति में 1500 से 1800 मेगावाट की कमी बताई जा रही है. इस कमी को देखते हुए बिजली वितरण कंपनियों ने शहरों और गांवों में बिजली कटौती योजनाबद्ध तरीके से की है, इसके अनुसार राज्य के हज़ारों गांव में प्रतिदिन दस से चौदह घंटे तक अधिकृत तौर पर बिजली कटौती की जाती है. इस बिजली कटौती से गांव में खेती और बिजली आधारित लघु तथा कुटीर उद्योगों पर बुरा असर पड़ रहा है.

रीवा में करोड़ों का दवा घोटाला

रीवा के सरकारी अस्पतालों में दो साल पहले दवा ख़रीदी के लिए हुए दो करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है. आश्चर्य की बात यह है कि इस घोटाले को अंजाम देने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीएन शर्मा को मुख्यमंत्री के आदेश पर निलंबित किया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. शर्मा को फिर से रीवा में उनके पुराने पद पर तैनात कर दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अलावा एक स्टोर कीपर भी बर्ख़ास्त किया गया था, लेकिन उसे भी बहाल कर फिर से उसी पद पर तैनात कर दिया गया है. रीवा के संभागायुक्त रविंद्र पस्तौर ने दवा घोटाले की जांच के निर्देश दिए हैं और स्टोर को सील कर दिया गया है. कलेक्टर के अवकाश पर होने के कारण डिप्टी कलेक्टर नवीन धुर्वे ने जांच की. रिपोर्ट में पता चला कि अस्पताल के लिए एक माह के स्टॉक हेतु दवा ख़रीदने की अनुमति स्वास्थ्य विभाग ने दी थी, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पूरे एक वर्ष के लिए दवाईयां ख़रीद ली, जिसका कि उन्हें अधिकार ही नहीं था. दवाईयों के इंडेंड में भी गड़बड़ी पाई गई है. यह भी पता चला कि अस्पताल के लिए 30 लाख रुपये की स्टेशनरी ख़रीदी गई थी. स्टेशनरी तो ग्वालियर से ख़रीदी गई, लेकिन इसकी रसीद उपभोक्ता भंडार रीवा के नाम की लगाई गई है. इससे भी गड़बड़ घोटाले की आशंका जन्म ले रही है. डॉ. शर्मा के बारे में बताया जाता है कि वर्ष 2006-07 में ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 42 लाख रुपये की दवा ख़रीदी में भी गड़बड़ी हुई थी. राज्य के लोकस्वास्थ्य विभाग के सचिव एसआर मोहंती ने इस दवा घोटाले के बारे में भोपाल में कहा है कि कलेक्टर रीवा की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी व्यक्तियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

विस्फोटकों का ज़खीरा बरामद

राजधानी भोपाल के परवलिया क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक खदान पर की गई छापेमारी में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है. इस बारे में जनता के बीच तरह-तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं. पुलिस के अनुसार ग्राम रसुलिया पठार में राजू राय का क्रेशर है. इस क्रेशर के लिए पत्थर, बोल्डर सप्लाई करने के लिए खदान के ठेकेदार वैध और अवैध रूप से इस क्षेत्र में उत्खनन के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल करते हैं. इस बारे में पुलिस को कुछ शिकायतें मिली थीं. शुक्रवार को पुलिस ने बम निरोधक दस्ते के साथ इस क्षेत्र में छापा मारा और पाया कि खदान क्षेत्र में कई जगह बड़ी मात्रा में विस्फोटक लगाए गए हैं. बम निरोधक दस्ते ने इन विस्फोटकों की तलाश कर उन्हें निकाला और फिर डिफ्यूज़ किया. विस्फोटक लगाने का शक खदान मालिक राजू राय और उसके दो साथी पर किया जा रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

शिक्षा का अधिकार
क़ानून का पालन असंभव है

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक-बालिकाओं के लिए शिक्षा के अधिकार की गारंटी देते हुए सभी को शिक्षित करने का एक महत्वाकांक्षी और क्रांतिकारी क़ानून लागू तो कर दिया है, लेकिन प्रदेश में इस क़ानून का पालन होने में अभी कुछ और साल लग सकते हैं. राज्य में शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य पाने के लिए शिक्षा क्षेत्र में न तो आधारभूत ढांचा है और न ही आवश्यक सुविधा और संसाधन.

वर्तमान की बात करें तो राज्य में साक्षरता दर 63.7 फीसदी है जो कि राष्ट्रीय औसत से कम है. राज्य में लगभग 50 फीसदी महिलाएं निरक्षर हैं. आदिवासी तथा दलित समुदाय में 60 से 65 फीसदी तक निरक्षरता की समस्या है. हालांकि राज्य सरकार ने 1998 से राज्य में सामाजिक क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देते हुए शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए प्रयास किए हैं. वहीं इन प्रयासों के कुछ अच्छे नतीज़े भी निकले हैं. लेकिन शिक्षा के सीमित विकास और इसके विस्तार के बावजूद, शिक्षण संस्थाएं बच्चों को पाठशालाओं की ओर आकर्षित करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई हैं.

सरकारी सूत्रों के अनुसार फ़िलहाल राज्य में 97900 प्राथमिक स्कूल हैं. इनमें 82185 सरकारी, 919 सैटेलाइट, 13915 निजी और 881 सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक पाठशालाएं हैं. इनके अलावा 39227 माध्यमिक शालाएं हैं. वर्ष

> **शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि समाज में ग़रीबी के कारण बच्चे रोजी-रोटी की जुगाड़ में काम धंधे में लग जाते हैं. गांव में पशुपालन, खेती-बाड़ी, घरेलू उद्योग, दस्तकारी आदि व्यवसाय में परिवार के बुज़ुर्ग ही अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं.**

स्तर	कुल छात्र-छात्राएं	अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राएं	अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राएं
कक्षा 1 से 10	55.74 प्रतिशत	53.72 प्रतिशत	73.27 प्रतिशत
कक्षा 1 से 12	72.93 प्रतिशत	78.45 प्रतिशत	83.63 प्रतिशत

2006-07 में इन प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में कुल एक करोड़ 63 लाख बच्चों का नामांकन हुआ, जो 2007-08 में बढ़कर एक करोड़ 67 लाख हो गया और 2008-09 में ये आकंड़ा कुछ कम होकर एक करोड़ 65 लाख तक रहा.

जहां एक ओर नामांकन वृद्धि पर सरकार ने ध्यान दिया, वहीं इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि स्कूल आने वाले छात्र-छात्राएं बीच में ही पढ़ाई छोड़कर स्कूल से निकल जाते हैं. सरकारी भाषा में इसे शाला-त्याग कहा जाता है. सरकार ने शाला-त्यागी बच्चों की दर निकाली है, जिससे साफ़ पता चलता है कि बड़ी संख्या में बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं. राज्य में 4997 हाईस्कूल और 4675 हायरसेकेंडरी स्कूल हैं, जिनमें क्रमश: 18.18 लाख तथा 10.64 लाख छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं.

बीच में पढ़ाई छोड़ देने के कारणों का विश्लेषण करने वाले शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि समाज में ग़रीबी के कारण बच्चे रोजी-रोटी की जुगाड़ में काम धंधे में लग जाते हैं. गांव में पशुपालन, खेती-बाड़ी, घरेलू उद्योग, दस्तकारी आदि व्यवसाय में परिवार के बुज़ुर्ग ही अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं. जहां तक बालिकाओं का सवाल है, आज भी ग्रामीण इलाक़ों में तथा आदिवासी दलित और पिछड़ी जातियों में बालिकाओं को साक्षर बनाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. इसके कारणों में सामाजिक जागरुकता का अभाव भी एक है. बालिकाओं को घरेलू कामकाज, बच्चों की देखभाल और खेती-पशुपालन में मददगार के रूप में काम देकर परिवार वाले उन्हें स्कूल जाने से रोकते हैं या हतोत्साहित करते हैं, जबकि सरकार ने बालिकाओं को स्कूल के प्रति आकर्षित करने के लिए अनेक प्रलोभनकारी या प्रोत्साहनकारी योजनाएं शुरू की हैं. जैसे-स्कूल जाने वाली 9वीं कक्षा में प्रवेश करने वाली छात्राओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण, आदि. इसके तहत पिछले तीन वर्षों से हर साल औसतन डेढ़ लाख से ज़्यादा छात्राओं को शासन की ओर से मुफ्त साइकिल वितरण किया जाता है. इसके अलावा क़रीब 15 लाख बच्चों के बीच नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक भी वितरित किया जाता है. आदिवासियों और दलितों को मासिक छात्रवृत्ति के साथ-साथ अनेक सुविधाएं भी दी जाती हैं, लेकिन इन सब के बाद भी राज्य में साक्षरता का प्रतिशत नहीं बढ़ा और न ही शिक्षा-स्तर में कोई आशाजनक सुधार ही हुआ है.

सरकार द्वारा स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने के बाद कई स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति केवल काग़ज़ों पर ही बढ़ी है. इतना ही नहीं, फ़र्ज़ी प्रवेश संख्या भी बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई हैं, ताकि भोजन के लिए मिलने वाला धन बटोरा जा सके. ज़ाहिर है भोजन के लालच में ग़रीब छात्र-छात्राएं देर तक स्कूल में रहते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

शिक्षा का स्तर

ज़िला सूचना पद्धति द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों और वन्य आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर इतना ख़राब है कि पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को 10 तक पहाड़े भी याद नहीं है और चार अंकों वाली संख्या के गुणा भाग के गणित भी उनसे हल नहीं हो पाते हैं. इतना ही नहीं वे शुद्ध-शुद्ध हिन्दी भी नहीं लिख पाते है.सामान्य ज्ञान के बारे में तो कहना ही क्या? एक एनजीओ कार्यकर्ता ने सन 2000 में मंडला ज़िले के एक आदिवासी विद्यालय में कक्षा पांच के छात्र से जब भारत के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया तो उसने बड़े आत्मविश्वास से राजीव गांधी का नाम बताया. यह मज़ाक नहीं है. हाल में ग्रामीण क्षेत्रों से 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर राज्य पुलिस विभाग में सिपाही की भर्ती के लिए हुई लिखित परीक्षा में की गई कॉपी जांच में आला अफ़सरों ने बिल्कुल ग़लत किंतु रोचक उत्तर देखा. उदाहरण के लिए भारत का राष्ट्रपति कौन है, के जवाब में उत्तर था-सोनिया गांधी. इसी तरह प्रधानमंत्री के नाम पर राहुल गांधी का नाम लिखा गया था.

गांवों में जाना नहीं चाहते शिक्षक

भौतिकतावादी और सुविधा भोगी युग में आज मध्य प्रदेश के गांव बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं और कई गांवों में तो शिक्षकों के निवास के लिए उपयुक्त आवास भी नहीं है. ऐसे में शिक्षक गांव में जाना नहीं चाहते है, लेकिन सरकारी नौकरी और अच्छे वेतन के लालच में वे नौकरी करते हैं और कुछ दिनों बाद राजनैतिक और प्रशासनिक जोड़तोड़ के ज़रिये किसी शहरी स्कूल में अपनी पदस्थापना भी करा लेते हैं. जिन अभागे शिक्षकों की शहरों में पदस्थापना नहीं होती हैं वे शहर से प्रतिदिन गांव अपने स्कूल जाते हैं और थोड़े समय पढ़ाने के बाद घर लौट आते हैं. राजधानी भोपाल से प्रतिदिन लगभग 300 शिक्षक-शिक्षिकाएं आसपास के 70 किलोमीटर दूर तक के गांव के स्कूल में सेवा देने के लिए हरदिन आना-जाना करते हैं. इसी तरह जबलपुर में लगभग 400 ग्रामीण शिक्षक रहते हैं, जबकि उनकी पदस्थापना आसपास के 40 किलोमीटर तक के गांव में हैं. ज़िला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों वाले शहरों की बात करें तो राज्य में 15000 से ज़्यादा ग्रामीण शिक्षक अपनी पदस्थापना वाले गांव में न रहकर, गांव से 10-50 किलोमीटर दूर तक रहते हैं और हरदिन आना-जाना करते हैं. शिक्षकों के गांव में न रहने से भी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि कई बार ये शिक्षक बिना कारण गायब हो जाते हैं या काफ़ी देरी से स्कूल आते हैं.

16000 स्कूल एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं

सरकार की ज़िला सूचना पद्धति के माध्यम से कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में साढ़े चौदह हज़ार सरकारी प्रायमरी स्कूल और लगभग डेढ़ हज़ार मिडिल स्कूल एक-एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं. इन स्कूलों में कुल 25 लाख से ज़्यादा बच्चों का दाखिला होना बताया गया है. सवाल है कि एक से पांचवीं तक अलग-अलग कक्षा में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चों को एक शिक्षक कैसे पढ़ा सकता है. सरकारी नियमों के अनुसार शिक्षक एक वर्ष में आकस्मिक अवकाश, बीमारी अवकाश और अर्जित अवकाश के मद में 37 दिन की छुट्टी ले सकता है. अर्थात यदि यह एक मात्र शिक्षक स्कूल नहीं आता है तो स्कूल बंद रहता है. इसके अलावा चुनाव, जनगणना और अन्य सरकारी कामों में भी शिक्षकों की सेवाएं ली जाती है. तब एक शिक्षक वाले स्कूल बंद रहते है. ऐसा नहीं कि सरकार इस समस्या से अनजान है. स्कूल शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनीस का कहना है कि शिक्षकों की कमी को अगले छह माह में पूरा कर लिया जाएगा. जहां तक भवनों और कमरों की कमी है, इसे भी अगले तीन वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा.

जहां तक स्कूल भवनों का सवाल है, एक एनजीओ के अध्ययन के अनुसार राज्य में 50 प्रतिशत से ज़्यादा प्राथमिक स्कूल घटिया, अस्वास्थ्यकर और सुविधा विहीन है. लगभग 75 प्रतिशत स्कूलों में न तो खेल के मैदान हैं और न ही बच्चों के लिए शौचालय.

सार -संक्षेप

रेल पुल जर्जर और ख़तरनाक हैं

मध्य प्रदेश में लगभग 2096 रेलवे पुल 100 वर्ष से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं. इनमें से 43 पुलों को ख़तरनाक माना जा रहा है. इस ख़तरनाक स्थिति के बावजूद भी रेल विभाग मामूली मरम्मत करके इन पुलों को काम योग्य बनाए हुए है. जानकारों का कहना है कि लगभग सवा सौ वर्ष पहले बने इन रेल पुलों की क्षमता 60-70 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार तक चलने वाली गाड़ियों की ही है, लेकिन अब तो 80 से 100 किलोमीटर रफ्तार वाली और पहले से तीन गुना ज़्यादा वज़न वाली गाड़ियां इन पुलों से गुज़रती है, ऐसे में पुराने जर्जर पुलों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है.

अधिकृत सूत्रों के अनुसार पश्चिम मध्य रेल ब्रिज सौ साल से भी ज़्यादा पुराने हो गए है. इनमें छोटे-बड़े दोनों प्रकार के पुल शामिल हैं. 100 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके बड़े पुलों की संख्या 143 हैं, जबकि छोटे पुलों की संख्या 1953 बताई जा रही है. इन पुलों में सर्वाधिक 35 जबलपुर डिवीजन में है. जोन के कोटा डिवीजन में मात्र 2 पुल ख़तरनाक पाए गए, जबकि भोपाल डिवीजन के ख़तरनाक पुलों की संख्या 6 बताई जा रही है. पश्चिम मध्य रेल प्रशासन के अनुसार ख़तरनाक रेल पुलों का सुधार कार्य कर लिया गया है और इन पर ट्रेनों के संचालन में कोई ख़तरा नहीं है. जबलपुर डिवीजन का ही एक ख़तरनाक पुल ऐसा है, जिसमें सुधार कार्य जारी है. यह पुल किलोमीटर क्रमांक 768/2 पर है, जिस पर कॉशन ऑर्डर लगाकर ट्रेनें चलाई जा रही है. ख़तरनाक पाए गए और सौ साल की उम्र पार कर चुके रेलवे पुलों पर कॉशन ऑर्डर लगाकर ट्रेनें धीमी गति से चलाई जा रही है. इटारसी-जबलपुर-सतना और कटनी-बीना के बीच दर्ज़नों स्थानों पर लगे कॉशन ऑर्डर के कारण ट्रेनें अक्सर लेट भी हो जाती हैं. पुलों पर कॉशन ऑर्डर लगाकर गति सीमा निर्धारित कर दिए जाने से रेल चालक को काफ़ी पहले ही ट्रेन की रफ्तार धीमी कर देनी पड़ती है.

रेलवे द्वारा छोटे-बड़े सभी रेलवे पुलों की नियमित तौर पर बाकायदा जांच कराई जाती है और गंभीरता से परीक्षण किया जाता है. किसी भी पुल में कोई ख़राबी पाई जाती है तो तत्काल उसका सुधार कार्य कराया जाता है. ख़तरनाक पाए गए पुलों पर भी ट्रेनों के संचालन में कोई ख़तरा नहीं है. सुधार कार्य कराए जाने के साथ ही इन पर लगातार नज़र रखी जा रही है. पश्चिम मध्य रेल मंडल में अधिकांश रेल लाइनों का दोहरीकरण हो चुका है और ज़्यादातर रेल मार्गो पर दो-दो पुल बन चुके हैं. इसके बाद भी पुराने पुलों की देखरेख और मरम्मत पर रेलवे को विशेष चौकसी रखनी पड़ती है और हर साल करोड़ों रुपया ख़र्च करना पड़ता है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सतना पुलिस चौकी को अस्तित्व की तलाश

मुंबई-हावड़ा प्रमुख रेल मार्ग पर स्थित है सतना स्टेशन. यहां स्थित रलवे पुलिस चौकी 160 साल पुरानी हो चुकी है. इसकी स्थापना अंग्रेज़ों द्वारा की गई थी. यह इकलौती पुलिस चौकी थी जहां बीमा राजघराने की हुकूमत नहीं चली. डेढ़ सदी गुज़र जाने के बाद आज भी यह चौकी सुविधाओं के लिए मोहताज है.

पुष्पेन्द मोर्या

सतना स्टेशन स्थित जीआरपी पुलिस की चौकी अंग्रेज़ों के राज्य में 160 साल पहले स्थापित की गई थी. मुंबई-हावड़ा प्रमुख रेल मार्ग से गुज़रने वाली सभी ट्रेनें इस चौकी से होकर ही गुज़रती थी. चौकी की स्थापना के समय सतना रेलवे स्टेशन से काशी एक्सप्रेस, मुंबई हाबड़ा मेल, इटारसी इलाहाबाद पेसेंजर और बाम्बे जनता मेल ही गुज़रता था. आज यहां से प्रतिदिन 105 ट्रेनों का आवागमन होता है. इन ट्रेनों में 25 हज़ार यात्री प्रतिदिन सफ़र करते है. रेलवे स्टेशन का विस्तार हुआ, पर 160 साल पुरानी इस चौकी की स्थिति जस की तस है.

रेल यात्रियों की हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी जीआरपी पुलिस की होती है. 160 साल बाद भी इस चौकी को प्रमोट कर थाने का दर्ज़ा नहीं दिया गया. आज भी सतना जीआरपी चौकी में कटनी थाने से कायमी नंबर लेकर प्रकरण पंजीबद्ध करना पड़ता है. जीआरपी के जवानों को रहने लायक आवास नहीं है. इस चौकी में एक सब इंस्पेक्टर, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 10 प्रधान आरक्षक और 21 आरक्षक तैनात हैं. इनमें से सिर्फ़ 9 जवानों को निवास के लिए जर्जर आवास दिए गए हैं.

रेलवे परिसर में होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए ज़िम्मेदार इस चौकी के पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान यात्रा के मुफ्त पास भी नहीं दिए जाते. यह बात अलग है कि रेलवे कुलियों, पोर्टर और प्वाइन्ट्स मैन को बकायदा फैमिली पास दिया जाता है. रेल सेवा के दौरान जीआरपी जवानों को टीए-डीए राज्य शासन के कोटे से दिया जाता है. इस चौकी के जवान वारदात की छानबीन के लिए देश के विभिन्न भागों में जाते हैं. शहर में किराये पर मकान ले रहे इन जवानों को 400 रुपये प्रतिमाह आवासीय भत्ता दिया जाता है, लेकिन इन्हें किराए पर मकान के लिए 1500 रुपये तक ख़र्च करने होते हैं.

सतना में पदस्थ मुट्ठी भर जवानों का कार्यक्षेत्र सतना से झांसी आउटर, इलाहाबाद ट्रेक से नैनी आउटर और मैहर तक है. इनमें से अधिकांश स्टेशन दस्यु प्रभावित माने जाते हैं. डकैती, हत्या और लूट जैसे अपराध सामान्य समझे जाते हैं. इतना ही नहीं शहर के 40 फीसदी शहर और रेलवे कॉलोनी का जिम्मा भी जीआरपी के पास ही है. स्टेशन परिसर के जीआरपी बैरक में बुनियादी सुविधाओं का आभाव है. जीआरपी बैरक इलाहाबाद, मानिकपुर, मुगलसराय और बनारस से पेट्रोलिंग पर आने वाले जवानों के अल्पकालिक विश्राम के लिए बनाए गए हैं.

सतना के मुक़ाबले कटनी जीआरपी थाने का क्षेत्र भी कम है और वहां सुविधाएं भी बेहतर हैं. वहीं रीवा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी ने अपने प्रभाव से जीआरपी चौकी को थाना घोषित करवा लिया है. यह बात अलग है कि रेलवे से सहमति न मिल पाने के कारण यह प्रक्रिया अभी लंबित है.

feedback@chauthiduniya.com

आदिवासी एकता की हलचल से परेशान कांग्रेस और भाजपा

हाल ही में हुए आदिवासी सम्मेलन में जुटी भीड़ और इस सम्मेलन की सफलता ने राजनीतिक हलकों में कई बदलावों के संकेत दे दिए हैं. राज्य की आदिवासी जनसंख्या इस बार किसी और पर भरोसा न कर अपने समुदाय के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री बनाने की फ़िराक़ में है.

रमन सिंह

रामदयाल उइके

सुब्रत भौमिक

बत्तीस फीसदी आरक्षण न होने की दशा में भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों के आदिवासी नेता एकजुट होकर विधानसभा की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे. पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री अजीत जोगी के लिए भाजपा विधायक पद से त्यागपत्र देने वाले रामदयाल उईके ने यह घोषणा की है.

छत्तीसगढ़ में आदिवासी एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ रही है. राज्य के आदिवासी नेता, चाहे वो किसी भी दल के क्यों न हों, किसी आदिवासी को अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट हो रहे हैं. 27 फरवरी को रायपुर में आदिवासी सम्मेलन के बाद सरकार द्वारा गठित उपसमिति ने भी आदिवासी आरक्षण पर सहमति देकर इस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है. रमन सरकार ने तो आरक्षण की मांग पर सहमति देकर विरोधियों को शांत करने का प्रयास किया था, लेकिन आदिवासियों की एकजुटता अब राज्य सरकार की राजनीतिक बिसात पर भारी पड़ती दिख रही है. वर्तमान में कांग्रेस के विधायक रामदयाल उईके ने स्पष्ट किया है कि रमन सरकार आदिवासियों से छल कर रही है. पहले सरकार को उन आदिवासियों को आदिवासी कहलाने का हक़ देना चाहिए जो आदिवासी होने के बावजूद अपने अधिकारों से वंचित हैं.

छत्तीसगढ़ में धनुहार, अघरिया, भार्या, भरेवा, मुवार, बिंझिया, पोबिया, सउरा, तौंरा और सौंरा आदि ऐसी आदिवासी जातियां है, जिन्हें उनके अधिकार आज तक नहीं मिले. मध्य प्रदेश में मानिकपुरी, पनिका जातियों को आदिवासी घोषित कर लाभ दिया जा रहा है, पर छत्तीसगढ़ में इन्हें पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा गया है. चौथी दुनिया से बातचीत करते हुए रामदयाल उईके ने कहा कि रमन सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही है. चतुर्थ श्रेणी के पुलिसकर्मियों की भर्ती में केवल 20 फीसदी आदिवासी ही लिए जा रहे हैं, जबकि आरक्षण 32 फीसदी का है. उईके के अनुसार, अगर आदिवासियों को उचित आरक्षण नहीं मिलता तो सभी दलों के आदिवासी नेता मिलकर 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे. यह संकेत है कि शोषित वर्ग अब अधिक शोषण के लिए तैयार नहीं हैं और वो आर-पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं.

आदिवासियों की इस एकजुटता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों में खलबली मचा दी है. इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी के अंदर आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष की मांग उठने लगी है. पार्टी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू पिछड़ा वर्ग से आते हैं. भाजपा ने भी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आदिवासी को ही ज़िम्मेदारी सौंप रखी है. इसके बावजूद रायपुर में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में राज्य सरकार के चार प्रभावशाली मंत्री न केवल शामिल हुए, बल्कि सरकार के विरोध में उठने वाले स्वरों को मजबूती भी देते रहे.

कूटनीतिक तरीके से रमन सिंह ने आरक्षण की नई व्यवस्था लागू करने की जो कोशिश की है, वह भी एक उलझन बनती जा रही है. नई व्यवस्था के तहत आदिवासियों को 12 फीसदी और पिछड़े वर्ग को 13 फीसदी का अतिरिक्त लाभ मिल रहा है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लोगों को चार फीसदी का नुकसान हो रहा है. सरकार की इस कार्यवाही से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन गडकरी के दलित वोट बैंक बढ़ाने के फॉर्मूले को झटका लगा है.

जनसंख्या के आधार पर आरक्षण के बारे में उपसमिति की सिफ़ारिशों के विरोध में अनुसूचित जनजाति के समुदायों में विरोध के स्वर उठने लगे है. वहीं भाजपा का समर्थक रहा सवर्ण समाज 71 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की सिफ़ारिश से आहत है. सरकार ग्राम स्वराज जैसे लोकलुभावन और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बीच अंबेडकर जयंती कार्यक्रम को महत्व देकर सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत काम कर रही है. भाजपा मंत्रिमंडल के आदिवासी मंत्री वर्तमान में आदिवासी एक्सप्रेस पर सवार हो चुके है और पार्टी के लिए यह चिंता का कारण हो सकता है. इतनी बड़ी संख्या में आदिवासी नेताओं का एक मंच पर एकत्र होना अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि एक सुनियोजित पहल नज़र आती है. आदिवासी बहुल इस राज्य में आदिवासी अपनी उपेक्षा से आहत हैं और राज्य के सत्ता शीर्ष तक पहुंच बनाने के लिए अब कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार हैं.

feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. 45843/86

चौथी दुनिया

दिल्ली, 03 मई–09 मई 2010

इन ऋणग्रस्त किसानों में लगभग 30 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास एक से तीन हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है.

क्रोकोडाइल पार्क परियोजना रामभरोसे

युगल किशोर तिवारी

छत्तीसगढ़ में विकास के नाम पर करोड़ों रुपयों की योजनाओं का भूमि–पूजन एक दिन में तो कर लिया जाता है, परंतु उसके क्रियान्वयन में कई साल लग जाते हैं. राज्य सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैये के कारण कई योजनाएं घोषणा होने के बाद भी लगातार दम तोड़ रही हैं. इनमें से ही एक महत्वपूर्ण योजना क्रोकोडाइल पार्क बनाने से संबंधित है.

जांजगीर–चांपा के ग्राम कोटमी सोनार में क्रोकोडाइल पार्क लोगों की मांग नहीं, बल्कि गांव की आवश्यकता है. इसकी कमी की वज़ह से यहां के दो बच्चे और तीन पुरुष अपनी जान गंवा चुके हैं. इनमें से दो लोग अपंग होकर आज भी अपना जीवन–निर्वाह कर रहे हैं. तीन परिवारों के चिराग़ बुझ चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति अपना हाथ गंवाकर पशु–प्रेम की क़ीमत चुका रहा है. जांजगीर ज़िला मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर स्थित कोटमी सोनार नामक गांव मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है. इस क्षेत्र के निवासियों ने मगरमच्छ को अपनी औलाद की तरह 15 सालों से पाल रखा है. 01 अप्रैल 2006 को प्रजननकाल के दौरान जब कुछ युवकों ने एक मगरमच्छ को छेड़ा तो उसने मंदिर के सीताराम दास पर हमला कर दिया और उसके बाएं हाथ को घसीटते हुए पानी में ले गया. सीताराम का अब एक हाथ नहीं है. इसके बावज़ूद सीताराम आज भी मगरमच्छों के साथ ही जीवन बिता रहे हैं.

कोटमी सोनार का मुढ़ा तालाब जो 86 एकड़ में विकसित है, को क्रोकोडाइल पार्क के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी. इस तालाब में 150 से अधिक छोटे बड़े मगरमच्छ हैं. इस परियोजना में अभी तक डेढ़ करोड़ से अधिक की राशि व्यय हो चुकी है. इस पार्क को जांजगीर चंपा के लिए ही नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी क्रोकोडाइल कॉलोनी के रूप में विकसित किए जाने की योजना थी. इस परियोजना के साथ–साथ चिल्ड्रेन पार्क और एनर्जी पार्क बनाने का कार्यक्रम भी रखा गया है.

इस परियोजना पर 06 फरवरी 2006 से काम शुरू हुआ. इस पर ईको टूरिज्म के मद से 72 लाख रुपये स्वीकृत किए गए. प्रदेश के मुखिया डॉ. रमन सिंह ने 09 मई 2006 को इस परियोजना का भूमि–पूजन किया था जबकि मुढ़ा तालाब के गहरीकरण का काम 12 मई 2006 से प्रारंभ हुआ है. इसके बावज़ूद परियोजना का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है. यही कारण है कि करोड़ों रुपये ख़र्च करने के बाद भी अपेक्षाकृत परिणाम सामने नहीं आ सका. परियोजना को प्रभावित करने में संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है. स्थानीय प्रशासन ने तालाब के आसपास अवैध क़ब्ज़े को हटाने में भी देरी की. इस गांव के आसपास इलाक़ों में ग्रामीणों और मगरमच्छों के बीच हुए टकराव से आम घटनाएं भी हो चुकी हैं.

इस गांव में 85 मगरमच्छ अनेक तालाबों में रहा करते थे. इस गांव के अलावा तटीय बड़गांव, रैड़ा सहित अन्य गांवों में मगरमच्छों को स्थानांतरित किया गया है. क्रोकोडाइल पार्क के प्रभारी डीएफओ इवाशीश बनर्जी के अनुसार, अब तक प्रथम चरण में 72 लाख रुपया, द्वितीय चरण में 70 लाख रुपया और

सीताराम दास

तृतीय चरण में एक करोड़ रुपये का काम पूरा किया जा चुका है. प्राप्त राशि से मगरमच्छों को अंडे देने के लिए तालाब का गहरीकरण, रेत को इकट्ठा करके टीला बनाना, तालाबों की फैंसिंग करना और मगरमच्छों के आहार के लिए तालाब में मछली डालना जैसे कार्य अब तक किए गए हैं. उनके अनुसार चौथे चरण के लिए एक करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हो गई है. बनर्जी के अनुसार पार्क की दशा 2010 तक बदल दी जाएगी और 2011 में पर्यटक स्थल के रूप में यह पार्क विकसित हो जाएगा. फ़िलहाल यहां लगभग 400 पर्यटक प्रतिदिन पहुंचते है. यह स्थिति तब है जब पार्क के संबंध में सरकार के द्वारा कोई प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है. इस परियोजना के निर्माण के साथ–साथ व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता भी है. वन विभाग वर्तमान में चिल्ड्रेन पार्क, एनर्जी पार्क, रेस्ट हाउस, स्टाफ क्वाटर, कॉफी हाउस, भीम वेल्ट और

मगरमच्छों से जुड़ी जानकारियां

कोटमी सोनार का यह क्रोकोडाइल पार्क प्राकृतिक रूप से प्रजनन एवं संरक्षण के नज़रिए से देश का पहला पार्क है. रेप्टाईल प्रजाती के मगरमच्छ मुख्य रूप से काफ़ी शर्मिले स्वभाव के होते हैं, पानी के भीतर ये घंटों बैठकर अपने संभावित शिकारों पर हमले की मुद्रा में ताक़ लगाए रहते हैं. यह पानी के नीचे बिना सांस लिए एक घंटे तक छिपे रह सकते है. इन मगरमच्छों के पेट का आकार महज़ एक फुटबॉल के समान होता है. एक वयस्क नर मगरमच्छ की औसतन आयु 35 से 40 वर्ष तक होती है. यह जीव मीठे व ख़ारे पानी में भी रह सकते हैं. मगरमच्छ 3 से 4 मीटर पानी के भराव वाले इलाक़े में रहना पसंद करते हैं. वहीं मादा मगरमच्छ नर की तुलना में अपेक्षाकृत छोटी होती हैं. मादा मगरमच्छ औसतन 30 से 40 अंडे देती हैं. इनमें महज़ 8 से 10 बच्चे ही पूर्ण विकसित हो पाते हैं. मादा मगरमच्छ अपने अंडे को मिट्टी या रेत के बने टीलों में लगभग 3 से 5 फ़ीट की गहराई तक गाड़ कर दिन रात उसकी रखवाली करती हैं. मादा मगरमच्छ के अंडे से जून और जुलाई माह में ही बच्चे निकलते हैं. अंडे से निकलने वाले बच्चों की अनुमानित लंबाई लगभग 6 इंच तक की होती है. मगरमच्छों को छेड़ने पर ये उग्र भी हो जाते हैं. पानी में इनके संवेदनशील अंग ज़रा सी भी कंपन को भांप लेते हैं.मगरमच्छों को खाना पचाने के लिए सूर्य की गर्मी की आवश्यकता होती है. अन्य मांसाहारी जीवों की तुलना में इनका 25 से 30 फ़ीसदी खाने पर ही गुज़ारा हो जाता है. शेष खाना इन्हें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है. इसी कारण मगरमच्छ विषम परिस्थितियों में भी अपने वज़ूदों को बचा पाने में सक्षम होते हैं. जिन देशों में मगरमच्छ की बहुतायत है वहां के लोग इसे मारकर इसके चमड़ियों से जैकेट एवं जूते बनाने का काम करते हैं. यही वज़ह है कि यह प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है. मगरमच्छों का स्वभाव जितना क्रूर है, पर्यावरण के लिहाज से इन्हे उतना ही सफ़ाई खोर भी माना जाता है. एक पूर्णरूप से विकसित मगरमच्छ की औसतन लंबाई 10 फ़ीट तक होती है, वहीं उसका वज़न 200 किलो से भी अधिक हो सकता है. मगरमच्छों का मुख्य भोजन मछली है. मछलियों की अनुपलब्धता में मगरमच्छ किसी भी सड़ी–गली लाश, या मांश के लोथड़ों से अपना पेट भर लेते हैं. इनकी पाचन–प्रणाली काफ़ी अच्छी होती है. यहां तक कि ये हड्डियों को भी पचा सकते हैं. मगरमच्छ अपनी पूंछ पर अतिरिक्त चर्बियों को जमाकर रख सकते हैं. भोजन नहीं मिलने की स्थिति में यह उसी चर्बी के सहारे महीनों तक जिंदा रह सकते हैं.

फ़र्ज़ी लालबत्ती का खेल

फ़र्ज़ी लालबत्ती लगाकर एक चोर चार दिन तक शहर में घूमता रहा और लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता रहा. बेरोज़गार और भोलेभाले युवकों को नौकरी दिलवाने के नाम पर छह लाख रुपया का चूना लगाने वाला आरोपी हाल में पुलिस के शिकंजे में तो आया, लेकिन पुलिस के ग़ैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते वह फिर से भागने में कामयाब हो गया.

जबलपुर ज़िला प्रशासन भी चार दिनों तक शहर में घूमने वाली इस फ़र्ज़ी लालबत्ती कार को पकड़ पाने में पूरी तरह असमर्थ रही. उज्जैन निवासी अरविंद श्रीवास्तव मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले शहर

अरविंद श्रीवास्तव(आरोपी)

राहुल जैन(पीड़ित)

जबलपुर में चार दिनों तक लालबत्ती की कार में फ़र्ज़ी तौर पर घूमता रहा. अरविन्द ख़ुद को मध्य प्रदेश के राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और पंचायत राज्यमंत्री देवी सिंह सय्याम का प्रतिनिधि बताकर लोगों को नौकरी दिलवाने का झूठा प्रलोभन देता था. इस तरह से उसने लोगों से लाखों की रकम वसूली कर ली. जबलपुर की पुलिस अपनी सक्रियताओं का दावा करने के बावज़ूद इस जालसाज़ को पकड़ पाने में नाक़ाम रही.

अरविंद श्रीवास्तव ने मंत्री के ख़ास आदमी के रूप में जबलपुर और लखनादौन क्षेत्र में नौकरी देने का एक धोख़ेबाज़ी भरा व्यवसाय शुरू किया.

यह जालसाज लखनादौन क्षेत्र के चार युवकों को नौकरी का झांसा देकर उनसे छह लाख रुपये ऐंठने में कामयाब हो गया. नौकरी न मिलने पर जब एक युवक ने पैसा वापस मांगा तो उसे एक चेक दिया गया जो बैंक में पैसा न होने के चलते बाउंस हो गया. जबलपुर शहर में इस जालसाज को लखनादौन के राहुल जैन नामक फरियादी ने खुलेआम लालबत्ती की गाड़ी में घूमते देखा. सवाल उठता है कि आख़िर पुलिस इसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई.

अरविंद श्रीवास्तव की जब गिरफ्तारी हुई थी तब वह चिल्ला चिल्लाकर स्वयं को मंत्रियों का आदमी बता रहा था. जबलपुर पुलिस ने अरविंद के ख़िलाफ़ मदन महल थाने में फ़र्ज़ी लालबत्ती लगाकर घूमने और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज़ तो किया लेकिन फिर कुछ ही देर में आरोपी को छोड़ भी दिया. वहीं लखनादौन की पुलिस जब वहां दर्ज़ प्रकरणों में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जबलपुर पहुंची तो उसे निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि अरविंद को पहले ही छोड़ा जा चुका था. हालांकि, सरकार के दोनों मंत्रियों ने उपरोक्त आरोपी से किसी तरह का संबंध होने की बात से इंकार किया है. ज़ाहिर है आरोपी को मदन महल पुलिस द्वारा लखनादौन की पुलिस का इंतज़ार किए बग़ैर छोड़ देना संदेह को जन्म देता है. अगर पुलिस चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज सकती है.

आरती पटेल
feedback@chauthiduniya.com

किसानों की आत्महत्या जारी

संध्या पांडे

मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार भले ही किसान को खुशहाल बनाने और खेती को लाभदायक व्यवसाय बनाने का प्रचार कर रही है, लेकिन हक़ीक़त यह है कि राज्य के किसानों की हालत काफ़ी ख़राब है. हालात ये है कि ग़रीबी तथा ऋण से परेशान होकर किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल किसानों द्वारा आत्महत्या करने के जो मामले सामने आए हैं, उनमें से 66 प्रतिशत मामले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों से हैं. मध्य प्रदेश में वर्ष 2004 में 1638, वर्ष 2005 में 1248, वर्ष 2006 में 1375, वर्ष 2007 में 1263, वर्ष 2008 में 1509 और वर्ष 2009 में 1500 किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामले प्रकाश में आए हैं.

मध्य प्रदेश में बिजली संकट, सिंचाई हेतु पानी, खाद, बीज, कीटनाशकों की उपलब्धता में कमी और मौसमी प्रकोप के कारण कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. इसके अलावा किसानों को बाज़ार में उनकी उपज का लाभदायक मूल्य भी नहीं मिल पाता है. इसके साथ ही सरकारी भ्रष्टाचार और सहकारी संस्थाओं में राजनैतिक भेदभाव तथा भ्रष्टाचार से भी किसानों को सरकार की प्रोत्साहनकारी और रियायती योजनाओं का भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है. कई सहकारी संस्थाओं के ज़रिए किसानों को घटिया खाद–बीज और कीटनाशकों की आपूर्ति की गई है, बावज़ूद इसके सरकार ने उन किसानों को न्याय नहीं दिलाया. भारत सरकार ने ऋणग्रस्त किसानों के ऋण माफ़ कर दिए हैं और इसके लिए राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति भी की है, लेकिन सहकारी संस्थाओं में घपले, घोटालों के कारण लगभग 115 करोड़ रुपयों के कृषि ऋण माफ़ नहीं हो पाए हैं. जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इन संस्थाओं को ऋण माफ़ी की प्रतिपूर्ति राशि आवंटित की जा चुकी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 32 लाख 11 हज़ार किसान ऋणग्रस्त हैं और प्रत्येक किसान पर औसतन चौदह हज़ार दो सौ अठारह रुपयों का ऋण बोझ है. इन ऋणग्रस्त किसानों में लगभग 30 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास एक से तीन हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है. इसके अलावा बहुत सारे किसान साहूकारों और बड़े व्यापारियों के कर्ज़ के बोझ से लदे हुए हैं.

मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस तथ्य को छिपाना चाहती है, फिर भी सच सामने आ ही जाता है. हाल ही में सरकार ने कुछ किसानों की आत्महत्या की घटनाओं के बारे में विधानसभा के प्रश्नों के उत्तर की जानकारी दी है. मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया ज़िलों में ग़रीबी के कारण 13 मज़दूरों और किसानों ने आत्महत्या की है, इसकी पुष्टि राज्य सरकार ने भी की है. पिछले दो वर्षों में 1000 से ज़्यादा आत्महत्याएं हो चुकी है. इनमें पांच से दस प्रतिशत आत्महत्याएं कर्ज़ और कर्ज़ वसूली में अपमानित होने के चलते की गई हैं, जबकि सरकारी आंकड़ों में इन आत्महत्याओं के कारणों को अज्ञात श्रेणी में रखा गया है. होशंगाबाद ज़िले के बनखेड़ी विकासखंड के कुर्सीढाना गांव में किसान अमान सिंह ने ज़हरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली. उस पर बैंक का लगभग एक लाख रुपये का कर्ज़ था. वहीं एक और किसान मिथिलेश ने ऋण के बोझ से दुखी होकर आत्महत्या की है. रीवा ज़िले के घोपकरा गांव में अमरनाथ मिश्रा ने बिजली बिल न चुका पाने पर अधिकारियों द्वारा जेल भेजने की धमकी सुनकर आत्महत्या कर ली. छतरपुर के दरगुवां गांव के किसान कल्लू खां ने कर्ज़ वसूली के डर से और खरगौन के सुरपाला गांव के किसान ने कर्ज़ और बिजली बिल न चुका पाने से दुखी होकर आत्महत्या की है. ऐसे सैकड़ों मामले है. वर्ष 2010 में मार्च माह तक 135 किसानों द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी मिली है, लेकिन सरकार इन आंकड़ों को उजागर नहीं करती हैं.

कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने पिछले दिनों विधानसभा में राज्य में हुई आत्महत्याओं के बारे में जानकारी मांगी थी, लेकिन सरकार ने केवल ग्वालियर के चार ज़िलों की ही जानकारी उपलब्ध करवाई. विधायक रामनिवास का कहना है कि किसानों की आत्महत्या से जुड़े आंकड़े ही भाजपा के स्वर्णिम प्रदेश को आईना दिखाने के लिए पर्याप्त हैं.

feedback@chauthiduniya.com